

# मेरी खेती

PAGE NO. 1-90, MAY, 2023

किसान  
समाचार



खेत खलियान  
सरकारी नीतियां  
मौसम व अन्य कृषि सुझाव  
सब्ज़ी  
फूल  
औषधीय खेती  
पशुपालन - पशुचारा  
प्रगतिशील किसान





## केंद्र सरकार का साहसिक फैसला: किसान के भीगे और टूटे गेहूं की भी होगी खरीद

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है। साथ ही, मार्च में हुई बारिश से अधिकांश किसानों का गेहूं भीग गया था। केंद्र सरकार की तरफ से नवीन नियमों के अंतर्गत 20 प्रतिशत तक भीगा गेहूं खरीदने की छूट प्रदान की गई है।

भारत के विभिन्न राज्यों में गेहूं की कटाई हो चुकी है। कटाई के उपरांत मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान शीघ्र ही मंडी में अपना गेहूं बेचने के लिए पहुँच गए थे। फरवरी और मार्च माह के मध्य हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का काफी गेहूं काफी हद तक भीग गया था। किसान चिंतित थे, कि भीगे गेहूं को किस प्रकार मंडी में बेच पाएँगे। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साहसिक कदम उठाया। भारत सरकार ने गेहूं खरीद से जुड़े जो भीगे गेहूं के लिए नियम सख्त थे, उन नियमों में केंद्र सरकार द्वारा काफी सहूलियत करदी है। किसानों को गेहूं बेचने के लिए किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।

मार्च माह में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में गेहूं की फसल को काफी मोटी हानि पहुंची थी। किसानों का गेहूं काफी ज्यादा भीग गया था। राज्य के किसान केंद्र सरकार से गेहूं खरीद में सहूलियत देने की मांग कर रहे थे। किसानों की मांग और समस्याओं को देखते हुए तीनों राज्यों के लिए केंद्र सरकार के स्तर से गेहूं खरीद हेतु बनाए गए नियमों में ढ़िलाई की गई। परिणामस्वरूप, किसान वर्षा से प्रभावित गेहूं का भी एमएसपी पर विक्रय कर पा रहे हैं।

-दिलीप यादव



किसान



**वोट करने से पहले जानिए  
अपने पसंदीदा नेता के बारे में  
सिर्फ NETAHUB पर**



# खेत खलियान



जानें उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली धान की इन दस उन्नत किस्मों की खासियत और उत्पादन के बारे में

## जानें उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली धान की इन दस उन्नत किस्मों की खासियत और उत्पादन के बारे में

आज हम आपको धान की उन दस उन्नत प्रजातियों के विषय में बताने जा रहे हैं। जो कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में धान की खेती काफी बड़े स्तर पर की जाती है। अब हम बात करेंगे इन 10 उन्नत किस्मों में से हर एक की अपनी प्रमुख विशेषताओं और फायदों के बारे में।

बता दें, कि धान की इन उन्नत किस्मों को उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा उनकी उच्च उपज क्षमता, कीटों एवं रोगों के लिए अच्छे प्रतिरोध साथ ही उत्कृष्ट अनाज की गुणवत्ता की वजह से पसंद किया जाता है। किसी विशेष प्रजाति का चयन किसानों की प्रमुख जरूरतों और प्राथमिकताओं पर आश्रित रहता है।

चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सिंचाई सुविधाओं, उर्वरक उपयोग मृदा के प्रकार, मौसम, कीट प्रबंधन बाकी प्रबंधन कार्य जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर अलग हो सकता है। हालांकि, यहां धान की 10 उन्नत प्रजाति हैं। तो वहीं उनकी अनुमानित प्रति हेक्टेयर उत्पादन, जो समान्तयः उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं।

**पंत धान 10: 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर**

यह एक और संकर किस्म है, जो कि उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। यह अपनी उच्च उपज क्षमता, कीटों एवं रोगों के लिए अच्छे प्रतिरोध और खाना पकाने की अच्छी गुणवत्ता हेतु मशहूर है। यह एक लघु समयावधि की फसल भी है, जो कि तकरीबन 115-120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

**पीबी1: 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर**

यह चावल की एक ऐसी किस्म है, जिसको उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। यह अपनी उच्च उपज क्षमता, कीटों एवं रोगों के प्रति अच्छे प्रतिरोध और उत्कृष्ट अनाज की गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। यह अति शीघ्र पकने वाली फसल भी है, जिसे पकने में लगभग 110-115 दिन लगते हैं।

**एचयूआर 105: 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर**

यह चावल की एक संकर किस्म है, जो उत्तर प्रदेश में काफी मशहूर है। यह अपनी उच्च उपज क्षमता, कीटों और रोगों के लिए अच्छे प्रतिरोध और खाना पकाने की अच्छी गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। यह एक छोटी अवधि की फसल भी है, जो तकरीबन 115-120 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है।

## एनडीआर 97: 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

यह चावल की एक गैर-बासमती किस्म है, जो आमतौर पर उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। यह अपनी उच्च उपज क्षमता, कीटों और रोगों के लिए अच्छे प्रतिरोध और अनाज की अच्छी गुणवत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह पकने वाली फसल भी है, जिसके पकने में तकरीबन 115-120 दिन लग जाते हैं।

## पूसा बासमती 1121: 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

यह बासमती चावल की एक बेहतरीन पैदावार देने वाली किस्म है, जो अपने लंबे एवं पतले दानों, सुखद सुगंध व उत्कृष्ट खाना पकाने की गुणवत्ता हेतु जानी जाती है। यह कीटों एवं रोगों के लिए भी प्रतिरोधी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए अन्य किस्मों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बाजार में काफी मांग है। साथ ही, इसका इस्तेमाल सामान्य तौर पर बिरयानी बनाने के लिए किया जाता है।

## पूसा सुगंध 5: 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

यह एक सुगंधित चावल की किस्म है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक तौर से उत्पादित की जाती है। यह अपने छोटे और सुगंधित अनाज, उच्च उपज क्षमता के लिए मशहूर है। यह पकाने में भी आसान होती है।

## पूसा 44: 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

यह चावल की एक गैर-बासमती किस्म है, जो उत्तर प्रदेश में बेहद मशहूर है। यह भी एक उच्च उपज वाली किस्म है, जो बहुत सारे कीटों व रोगों के लिए प्रतिरोधी सबित होती है, जो कि इसको कृषकों हेतु एक विश्वसनीय विकल्प बनाती है।

## सरजू 52: 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

यह एक और गैर-बासमती किस्म है जो कि सामान्यतः उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। यह अपने मध्यम आकार के अनाज एवं खाना पकाने की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। साथ ही, यह कीटों और रोगों के लिए भी प्रतिरोधी है।

## महसूरी: 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

यह चावल की एक किस्म है, जो उत्तर प्रदेश समेत भारत के विभिन्न इलाकों में उगाई जाती है। यह अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उच्च उपज क्षमता के साथ-साथ अच्छी खाना पकाने की गुणवत्ता हेतु जानी जाती है। यह शीघ्र पकने वाला भी है एवं यह 120-125 दिनों में कटाई हेतु तैयार हो जाती है।

## पीआर 121: 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

यह चावल की एक संकर किस्म है, जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। यह किस्म की उच्च उत्पादक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। कीटों एवं रोगों के प्रति अच्छी प्रतिरोध क्षमता और उत्तम अनाज की गुणवत्ता हेतु काफी मशहूर मानी जाती है। यह एक छोटी समयावधि की फसल भी है, जो तकरीबन 110-115 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है।

यह धान की उन्नत किस्मों के कुछ उदाहरण हैं, जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाती हैं। बहुत सारी बाकी किस्में भी उत्पादित की जाती हैं, जिनमें से हर एक किस्म की अपनी अनोखी खासियत और फायदा है। यह ध्यान रखना काफी अहम है, कि इस लेख में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है। क्योंकि किसानों द्वारा अपनाई गई खास स्थितियों एवं प्रबंधन प्रथाओं के तहत वास्तविक पैदावार भिन्न हो सकती है।



## इस तरह से खेती करके किसान एक ही खेत में दो फसलें उगा सकते हैं



## इस तरह से खेती करके किसान एक ही खेत में दो फसलें उगा सकते हैं

आजकल उपलब्ध आधुनिक कृषि तकनीकों से जोखिम को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं कुछ तकनीकें तो कम वक्त में फसलों से ज्यादा आमदनी कराने में भी सहयोग करती हैं। वर्तमान में किसान एक ही भूमि पर एक साथ 2 से अधिक फसलें उत्पादित कर सकता है।

आधुनिकता के जमाने में फिलहाल हमारा कृषि क्षेत्र भी सुपर एडवांस होने की दिशा में तेजी से बढ़ता जा रहा है। किसान आजकल यंत्रों और नई तकनीकों के माध्यम से फसल का बेहतरीन उत्पादन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोखिम को कम करके कृषकों की आमदनी बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक भी नित नई तरकीबें पेश कर रहे हैं। अंतरवर्तीय खेती भी इन तरकीबों में शामिल है। यह तरीका बढ़ती आबादी की खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं कम खेती-कम वक्त में ज्यादा पैदावार लेने में सहायक भूमिका निभा रहा है। अगर किसान को फसल चक्र की सटीक जानकारी है, तो वह अंतरवर्तीय खेती के जरिए अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकता है। आजकल जायद सीजन की फसलों की बुवाई का कार्य चल रहा है।

बहुत सारे किसान भाई अपने खेत में ग्रीष्मकालीन मूंग सहित विभिन्न दलहनी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। अगर कतारों में दलहन की बुवाई की गई है, तो मध्य में हल्दी, अदरक की भांति औषधी और मसाला फसलों का उत्पादन करके दोगुना उत्पादन ले सकते हैं। अंतरवर्तीय खेती की सर्वाधिक विशेष बात यही है, कि कतारों में 2 से ज्यादा फसलों की बुवाई की जा सकती है।

इसमें अलग से खाद-उर्वरक का खर्चा नहीं आता है। किसान को केवल भिन्न-भिन्न बीज डालने होते हैं, जिसके उपरांत एक ही फसल में लगाए जाने वाले इनपुट्स से सारी फसलों की उन्नति हो सकती है।

### अरहर और हल्दी की अंतरवर्तीय खेती से अच्छा मुनाफा हांसिल किया जा सकता है

अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल मानी जाती है, तो वहीं मसाला एवं औषधी के रूप में बाजार में हल्दी की काफी मांग रहती है। एक ही भूमि पर कतारों में इन दोनों फसलों को बोया जा सकता है। हालांकि, हल्दी को छायादार जगह पर उत्पादित किया जाता है, इस वजह से अरहर समेत इसकी फसल लेना काफी फायदेमंद रहेगा।

एक साथ बुवाई करके दोनों फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। अरहर जैसी दलहनी फसलों के साथ अंतरवर्तीय खेती करने का सबसे बड़ा लाभ यह है, कि यह फसलें वातावरण से नाइट्रोजन को सोखकर भूमि तक पहुंचाती हैं।

इससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। वहीं साथ-साथ में उगने वाली फसल को इसका प्रत्यक्ष तौर पर फायदा मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार, दलहनी फसलों की खेती सहित अथवा इसके उपरांत बोई जाने वाली फसलों की पैदावार में वृद्धि हो जाती है। दलहनी फसलों की कटाई करने के उपरांत अलग से खाद-उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना होता है।

## मृदा में कटाव होने से भी बचता है

जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव साफ तौर पर खेती-किसानी पर देखने को मिल रहा है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा जैसी परिस्थितियों से फसलें चौपट होती जा रही हैं। भूजल स्तर में गिरावट आने से मृदा में कटाव काफी बढ़ रहा है। अंतरवर्तीय खेती को इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान माना जाता है।

एक सहित विभिन्न फसलों को लगाने से मृदा में जल को बांधने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे वर्षा के समय में कटाव की समस्या नहीं रहती एवं मिट्टी में भी नमी बरकरार रहती है। अगर किसी कारणवश एक फसल को हानि पहुँच भी जाए तब भी किसान पर जीवनयापन करने हेतु दूसरी फसल का सहारा मिल जाता है। औषधीय फसलों की अंतरवर्तीय खेती करने अथवा फसल विविधता के चलते फसल में कीट-रोगों का प्रकोप नहीं रहता है। इससे कीटनाशकों का खर्चा बच जाता है। फसल की गुणवत्ता को उत्तम बनी रहने के साथ बाजार में उत्पादन को अच्छा खासा भाव मिल जाता है।

## मृदा में कटाव होने से भी बचता है

जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव साफ तौर पर खेती-किसानी पर देखने को मिल रहा है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा जैसी परिस्थितियों से फसलें चौपट होती जा रही हैं। भूजल स्तर में गिरावट आने से मृदा में कटाव काफी बढ़ रहा है। अंतरवर्तीय खेती को इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान माना जाता है।

एक सहित विभिन्न फसलों को लगाने से मृदा में जल को बांधने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे वर्षा के समय में कटाव की समस्या नहीं रहती एवं मिट्टी में भी नमी बरकरार रहती है। अगर किसी कारणवश एक फसल को हानि पहुँच भी जाए तब भी किसान पर जीवनयापन करने हेतु दूसरी फसल का सहारा मिल जाता है। औषधीय फसलों की अंतरवर्तीय खेती करने अथवा फसल विविधता के चलते फसल में कीट-रोगों का प्रकोप नहीं रहता है। इससे कीटनाशकों का खर्चा बच जाता है। फसल की गुणवत्ता को उत्तम बनी रहने के साथ बाजार में उत्पादन को अच्छा खासा भाव मिल जाता है।



# सब्ज़ी



**गर्मियों के मौसम में ऐसे करें  
प्याज की खेती, होगा बंपर  
मुनाफा**

## गर्मियों के मौसम में ऐसे करें प्याज की खेती, होगा बंपर मुनाफा

देश के कई राज्यों में प्याज की खेती साल में सिर्फ एक बार की जाती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां प्याज की खेती साल में तीन बार की जाती है। इसमें महाराष्ट्र का स्थान सबसे ऊपर है। इस राज्य के धुले, अहमदनगर, नासिक, पुणे और शोलापुर जिलों में प्याज का बंपर उत्पादन होता है। यहां पर साल में अमूमन तीन बार प्याज की खेती की जाती है। इसलिए महाराष्ट्र को देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य कहा जाता है। महाराष्ट्र के नाशिक जिले की लासलगांव मंडी को एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी का दर्जा प्राप्त है।

प्याज का उपयोग ज्यादातर सब्जी के रूप में हर घर में किया जाता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में इसका उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। प्याज की फसल सामान्यतः 100 से 120 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। प्याज का बंपर उत्पादन होने के कारण किसान भाई इस खेती से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं।



**प्याज की खेती के लिए उचित जलवायु और मृदा**

प्याज की खेती के लिए ज्यादा तापमान उचित नहीं माना जाता। ऐसे में गर्मियों के मौसम में किसानों को यह सुनिश्चित करना होता है कि खेत का तापमान बहुत ज्यादा न बढ़ने पाए। इसके साथ ही शुष्क जलवायु इस खेती के लिए बेहतर मानी जाती है।

अगर प्याज की खेती में मृदा की बात करें तो उचित जलनिकास एवं जीवाणुयुक्त उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। प्याज की खेती अत्यंत गीली या दलदली जमीन पर नहीं करना चाहिए। प्याज की खेती के लिए मिट्टी का पी.एच. मान 6.5-7.5 के मध्य होना चाहिए। इसके लिए किसान भाई बुवाई के पहले मृदा परीक्षण अवश्य करवा लें।

**प्याज की किस्में**

बाजार में प्याज की कुछ किस्में ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें एग्री फाउण्ड डार्क रेड, एन-53 और भीमा सुपर का नाम आता है।

एग्री फाउण्ड डार्क रेड किस्म को भारत में कहीं भी आसानी से उगाया जा सकता है।



इसके कंद गोलाकार होते हैं, जिनका आकार 4 से 6 सेंटीमीटर बड़ा होता है। इसके साथ ही यह फसल 95-110 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। यह किस्म एक हेक्टेयर में 300 क्विंटल का उत्पादन दे सकती है।

एन-53 किस्म को भी भारत में कहीं भी उगाया जा सकता है। लेकिन इसकी फसल 140 दिनों में तैयार होती है। साथ ही इस किस्म का उत्पादन 250-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है।

भीमा सुपर एक अलग तरह की प्याज की किस्म है। जिसमें किसानों को उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। यह किस्म 110-115 दिन में तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन भी 250-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है।

## ऐसे करें भूमि की तैयारी

प्याज की खेती के लिए भूमि को अच्छे से तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए कल्टीवेटर या हैरो की मदद से 2 से 3 बार जुताई करें। जुताई के साथ ही खेत में पाटा अवश्य चलाएं, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो सके और नमी सुरक्षित रहे। भूमि की सतह से 15 से.मी. उंचाई पर 1.2 मीटर का बेड तैयार कर लें। जिस पर प्याज की बुवाई की जाती है।

## खाद एवं उर्वरक की मात्रा

प्याज की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मिट्टी के परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। अगर खेत में अधिक पोषक तत्वों की जरूरत हो तो खेत में गोबर की सड़ी खाद 20-25 टन/हेक्टेयर की दर से बुवाई के 1 माह पूर्व डालना चाहिए। इसके अलावा खेत में नत्रजन 100 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर, स्फुर 50 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तथा पोटाश 50 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। यदि खेत की गुणवत्ता ज्यादा ही खराब है तो खेत में सल्फर 25 कि.ग्रा. एवं जिंक 5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं।

## ऐसे तैयार करें पौध

प्याज की पौध को उठी हुई क्यारियों में तैयार किया जाता है। बोने के पहले बीजों को अच्छे से उपचारित करना चाहिए। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 15 से 20 ग्राम बीज बोना चाहिए। इसके लिए 3 वर्ग मीटर की क्यारियां बनाना चाहिए। एक हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम बीज बोया जाता है।

## ऐसे करें रोपाई

प्याज की पौध की रोपाई मिट्टी के तैयार किए गए बेड में की जाती है। इसके लिए एक हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई करने के लिए 12 से 15 क्विंटल पौध की जरूरत होती है। पौध की रोपाई कूड़ शैथ्या पद्धति से करना चाहिए। इसमें 1.2 मीटर चौड़ा बेड एवं लगभग 30 से.मी. चौड़ी नाली तैयार की जाती हैं। पौध को अंकुरित होने के 45 दिन बाद ही बेड पर लगाना चाहिए।

## खरपतवार नियंत्रण

प्याज की फसल में खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए समय-समय पर निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पूरी फसल के दौरान कम से कम 3 से 4 बार निराई गुड़ाई अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा खरपतवार को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए पौध की रोपाई के 3 दिन पश्चात 2.5 से 3.5 लीटर/हेक्टेयर की दर से पैन्डीमैथेलिन का छिड़काव किया जा सकता है। इसे 750 लीटर पानी में घोला चाहिए। इसके अलावा इतने ही पानी में 600-1000 मिली/हेक्टेयर के हिसाब से ऑक्सीप्लोरोफेन का छिड़काव भी किया जा सकता है।



जबरदस्त फीचर्स, जबरदस्त ट्रैक्टर



## प्याज की फसल की सिंचाई

प्याज की फसल में सिंचाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्यथा फसल तुरंत ही सूख जाएगी। इस फसल में यह ध्यान देने योग्य बात होती है कि जब कंदों का निर्माण हो रहा हो तब खेत में पानी की कमी न रहे। नहीं तो पौध का विकास रुक जाएगा और प्याज का आकार बड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे में उपज प्रभावित हो सकती है। आवश्यकतानुसार 8 से 10 दिन के अंतराल में फसल में पानी देते रहें। यदि खेत में पानी रुकने लगे तो उसकी जल्द से जल्द निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। अन्यथा फसल में फफूंदी जनित रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है।

## कंदों की खुदाई

जैसे ही प्याज की पत्तियां सूखने लगती हैं और प्याज की गांठ अपना आकार ले लेती है तो 10-15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देना चाहिए। जब खेत पूरी तरह से सूख जाए, उसके बाद पौधों के शीर्ष को पैर की मदद से कुचल देना चाहिए। इससे कंदों की वृद्धि रुक जाती है और कंद ठोस हो जाते हैं। इसके बाद कंदों को खोदकर खेत में ही सुखाना चाहिए। सूखने के बाद प्याज को भरकर भंडारण के लिए भेज देना चाहिए।



NEW HOLLAND  
AGRICULTURE

जबरदस्त फीचर्स, जबरदस्त ट्रैक्टर





# गर्मियों के मौसम में ऐसे करें करेले की खेती, होगा ज्यादा मुनाफा

## गर्मियों के मौसम में ऐसे करें करेले की खेती, होगा ज्यादा मुनाफा

सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है। जिसके तहत सब्जियों की फसल लगाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों के हाथ में नियमित रूप से पैसे आते रहें। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तो सरकार सब्जियों की खेती ले लिए किसानों को अनुदान भी उपलब्ध करवा रही है।

गेहूं, चना, सरसों आदि की तुलना में सब्जियों की फसल जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे में उसी जमीन पर अगली फसल लगाने के लिए किसानों को समय मिल जाता है, जिससे किसान अच्छे से खेत तैयार करके किसी अन्य फसल को अपने खेत में लगा सकते हैं। वैसे तो बाजार में कई सब्जियां हैं जिनकी गर्मियों में भारी मांग रहती है। लेकिन करेले का एक अलग ही स्थान है। जिसकी खेती करके किसान भाई कम समय में अच्छा खासा लाभ काम सकते हैं।

करेला अपने औषधीय गुणों के कारण सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी है। यह शुगर और डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। इसलिए डॉक्टर डायबिटीज के मरीजों को करेले का ज्यूस पीने की सलाह देते हैं। साथ ही यह शुगर कंट्रोल करने में भी सहायक होता है इसलिए डॉक्टर करेले की सब्जी खाने के लिए कहते हैं। करेला कई विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, बी और सी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है। इसके अलावा करेले में कैरोटीन, बीटाकैरोटीन, लूटीन, आइरन, जिंक, पोटैशियम, मैग्नीशियम और मैगनीज जैसे फ्लावोन्वाइड जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।

इन पोषक तत्वों के कारण यह त्वचा रोग में बेहद लाभकारी होता है। इसके सेवन से पाचन शक्ति बढ़ती है, इसलिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उच्च होती है। मोटापा कम करने के लिए और पीलिया ठीक करने के लिए भी करेले का सेवन किया जाता है।

### ऐसे करें मिट्टी का चुनाव

करेले की खेती बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में करना चाहिए। इसके साथ ही नदी किनारे की जलोढ़ मिट्टी भी इसके लिए उत्तम मानी गई है। करेले के खेत में उचित जल निकास की जरूरत होती है, नहीं तो पेड़ सड़ जाएंगे। करेले को गर्मियों से साथ-साथ वर्षा ऋतु में भी उगाया जा सकता है। अगर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है तो यह फसल के विकास के लिए सर्वोत्तम है। बीजों के जमाव के लिए खेत का तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए।

### ऐसे करें खेत की तैयारी

खेत में करेले की फसल की बुवाई करने से पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें। बुवाई से 20 दिन पहले 25-30 टन गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। इसके बाद कतारबद्ध रूप से बेड बना लें। बुवाई के पहले मिट्टी के बेड के बगल से बनी नालियों में 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलो म्यूरेट आफ पोटैस का मिश्रण प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बुवाई के बाद यूरिया का भी प्रयोग करना चाहिए।

इसके लिए शाम का समय चुनें, ताकि उतने समय खेत में नमी बरकार रहे। बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद करेले के पुष्पन व फलन के समय भी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इससे पौधे को पोषण मिलता है और उत्पादन अधिक होता है।

### ये हैं करेले की उन्नत किस्में

वैसे तो बाजार में करेले की कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। जिनको आप बुवाई के लिए चुन सकते हैं। इनमें कल्याणपुर बारहमासी, पूसा विशेष, हिसार सलेक्शन, कोयम्बटूर लौंग, अर्का हरित, पूसा हाइब्रिड-2, पूसा औषधि, पूसा दो मौसमी, पंजाब करेला-1, पंजाब-14, सोलन हरा और सोलन सफ़ेद, प्रिया को-1, एस डी यू-1, कल्याणपुर सोना, पूसा शंकर-1 आदि किस्में शामिल हैं। जिन्हें किसान भाई अपने खेतों में लगाना पसंद करते हैं।

### ऐसे करें करेले की बुवाई

अब बाजार में ऐसी हाइब्रिड किस्में आ गई हैं जिससे करेले की खेती अब हर मौसम में की जाती है। आमतौर पर करेले को दो तरीकों से लगाया जाता है। पहला, खेत में सीधे बुवाई के माध्यम से और दूसरा, इसकी नर्सरी तैयार करके। नर्सरी के पौधे जब बौने लायक हो जाते हैं तब इनको खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बुवाई करने के लिए खेत में 2 फीट की दूरी पर बेड बना लें। इसके बाद बेड पर 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बीजों की रोपाई करें। बीजों को हमेशा 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अगर करेले की पौध की रोपाई कर रहे हैं तो नाली से नाली की दूरी 2 मीटर रखनी चाहिए। साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर और मिट्टी के बेड की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

एक एकड़ में बुवाई करने के लिए करेले के 500 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। अगर पौध के माध्यम से करेले की बुवाई करना है तो बीज की मात्रा में कमी भी की जा सकती है। बुवाई से पहले बीजों को बाविस्टीन के घोल में उपचारित करना चाहिए। इससे पेड़ों पर कीटों का आक्रमण नहीं होता है।



### करेले की फसल की सुरक्षा और निराई गुड़ाई

करेला बेल के रूप में उगाता है। ऐसे में करेले की बेल को सहारा देना जरूरी हो जाता है नहीं तो बेल खराब हो जाएगी। जब करेले का पौधा थोड़ी बड़ा हो जाए तो उसे लकड़ी या बांस का सहारा देना चाहिए। ताकि यह एक निश्चित दिशा में वृद्धि कर सके। इसके अलावा पौधे को रस्सी के सहारे से बांधा भी जा सकता है।

करेले की फसल के शुरूआती समय में निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। ऐसे में फसल की निराई गुड़ाई करें ताकि खेत में खरपतवार न पनपने पाएं। अगर शुरूआती दौर में खरपतवार पर नियंत्रण कर लेते हैं तो करेले की अच्छी फसल प्राप्त होती है।

### करेले की फसल में सिंचाई

वैसे तो करेले की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। फिर भी खेत में हल्की सिंचाई करते रहें, ताकि खेत में नमी बरकरार रहे और पौधे सूखें नहीं। फूल व फल बनने की अवस्था में फसल की सिंचाई जरूर करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा न होने पाए। खेत में पानी जमा होने की स्थिति में पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करें ताकि फसल खराब न होने पाए।

### करेले की तुड़ाई

आमतौर पर करेले की फसल 60 यह 70 दिनों में तैयार हो जाती है। करेले के कठोर होने के पहले ही इसकी तुड़ाई कर लेना चाहिए। करेले को तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि करेले के डंठल की लंबाई 2 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो। इससे करेले ज्यादा समय तक तरोताजा बने रहते हैं। करेले की फसल कि तुड़ाई हमेशा सुबह के समय करनी चाहिए।

### करेले की फसल का उत्पादन

एक एकड़ की फसल में किसान भाई आराम से 50 से 60 क्विंटल तक करेले का उत्पादन कर सकते हैं। जबकि प्रति एकड़ इसकी खेती में मात्र 30 हजार रुपये की लागत आती है। इस हिसाब से बड़ी मात्रा में करेले की खेती करके किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।



जबरदस्त फीचर्स, जबरदस्त ट्रैक्टर



# फल

## जानें विश्व के सर्वाधिक महंगे आम की विशेषताओं के बारे में



### जानें विश्व के सर्वाधिक महंगे आम की विशेषताओं के बारे में

जापान में उत्पादित किए जाने वाले इस आम का नाम 'टाइयो नो टमैगो' (TAIYO NO TAMAGO) है। मुख्य रूप से जापान के मियाजाकी शहर में इसका उत्पादन किया जाता है। विश्व के प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न प्रजातियों के आम उत्पादित किए जाते हैं। समस्त आमों की कीमत गुणवत्ता के आधार पर भिन्न-भिन्न रहती है। साथ ही, खाने में स्वाद भी सभी का अलग-अलग रहता है। बता दें कि किसी आम को उसकी मिठास के लिए जाना जाता है, तो किसी आम को उसकी खटास के लिए जाना जाता है। यही कारण है, कि किसी आम का इस्तेमाल केवल अचार निर्मित करने में किया जाता है, तो किसी आम द्वारा जूस, आइसक्रीम, जैम और फ्रूटी बनाई जाती है।

हालाँकि भारत में चौसा, दशहरी, जरदालू, अल्फोंस और लंगड़ा आम ज्यादा प्रसिद्ध है। दरअसल, इन सब में से भी अल्फोंस आम सबसे महंगा है। यह 1200 से 2000 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है। परंतु, अल्फोंस आम विश्व का सबसे महंगा आम नहीं है। इससे भी महंगा आम जापान में उत्पादित किया जाता है। इसका भाव सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालाँकि, फिलहाल भारत के अंदर भी विश्व के सबसे महंगे आम की खेती होनी शुरू हो गई है।

**इस आम को कहाँ-कहाँ उत्पादित किया जाता है**

जापान में उत्पादित किए जाने वाले इस आम का नाम 'टाइयो नो टमैगो' है। विशेष रूप से जापान के मियाजाकी शहर में इसका उत्पादन किया जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक महंगा आम माना जाता है। परंतु, फिलहाल इसकी खेती थाईलैंड, बांग्लादेश और फिलीपींस में होनी शुरू हो गई है। यह एक तरह का इरविन आम है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पादित किए जाने वाले पीले पेलिकन आम से अलग है। मध्य प्रदेश में एक किसान ने 'टाइयो नो टमैगो' की खेती करनी चालू करदी है।

**इस किस्म के एक आम में कितना वजन होता है**

'टाइयो नो टमैगो' के पेड़ पर अप्रैल माह में छोटे-छोटे फल लगने चालू हो जाते हैं। तो वहीं अगस्त माह आते-आते आम प्राकृतिक तौर पर पक कर तैयार हो जाता है। इसके एक फल का औसत वजन 350 ग्राम होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका भाव 2 लाख 70 हजार रुपये प्रति किलोग्राम है। इस आम में 15 प्रतिशत तक चीनी की मात्रा होती है। ऐसे में शुगर पेशेंट भी इस आम का सेवन कर सकते हैं।

## बीटा-कैरोटीन और फोलिक एसिड भी इस आम में पाया जाता है

'टाइयो नो टमैगो' एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर है। इसमें बीटा-कैरोटीन एवं फोलिक एसिड भी प्रचूर मात्रा में पाया जाता है। इससे आंखों की रोशनी काफी अच्छी रहती है। साथ ही, शरीरिक थकावट भी दूर हो जाती है। जानकारों के अनुसार, इसका सेवन करने से निकट दृष्टि दोष भी दूर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, टाइयो नो टमैगो का उत्पादन 70 के दशक के समापन एवं 80 के दशक के आरंभ में मियाज़ाकी में चालू हुआ था। बता दें, कि इस शहर के गर्म मौसम, लंबे समय तक धूप एवं भरपूर वर्षा ने मियाज़ाकी के कृषकों को इस आम की खेती करने में सहयोग किया था।





## लीची की इस किस्म से किसान बंपर पैदावार के साथ बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं



## लीची की इस किस्म से किसान बंपर पैदावार के साथ बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं

बिहार राज्य में सर्वाधिक लीची का उत्पादन किया जाता है। यहां वर्ष 2021-22 में 308.1 मीट्रिक टन लीची की पैदावार हुई थी। बिहार राज्य के लीची उत्पादक किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार लीची की नवीन किस्म का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। विशेष बात यह है, कि सरकार द्वारा राज्य में लीची की पैदावार में वृद्धि करने हेतु यह कदम उठाया गया है। दरअसल, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा एक ऐसी किस्म तैयार की है, जिसका उत्पादन करने पर लीची का उत्पादन काफी बढ़ जाएगा। इससे प्रदेश में लीची की पैदावार को बढ़ावा मिलेगा।

मीड़िया खबरों के मुताबिक, बिहार राज्य में अकेले 43 फीसदी लीची का उत्पादन किया जाता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची तो अपने स्वाद की वजह से पूरे विश्व में मशहूर है। यही कारण है, कि बिहार सरकार विशेषकर लीची की प्रजाति गंडकी योगिता, गंडकी लालिमा एवं गंडकी संपदा की खेती करने के लिए किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया है, कि राज्य सरकार और एनआरसीएल (मुजफ्फरपुर) लीची उत्पादन, गुणवत्ता एवं भंडारण में सुधार करने हेतु एकजुट होकर कार्य कर रही है।

मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। यह अपनी अनोखी सुगंध की वजह से जानी जाती है। इसके अंदर ज्यादा रस एवं सामान्य से छोटी गुठली विद्यमान रहती है।

### 18 से 23 फीसद फसल क्षतिग्रस्त हो चुकी है

बता दें, कि लीची एक नॉन-क्लिमैक्ट्रिक फल है। नॉन-क्लिमैक्ट्रिक फलों की विशेषता यह है, कि यह सिर्फ पेड़ पर लगे रहने के दौरान ही पकते हैं। अगर पेड़ से उसको तोड़ लिया जाए, तो इसका पकना समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में पके हुए लीची के फलों को ही पेड़ों से तोड़ा जाता है। साथ ही, ऐसे में इसके जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए इसको दीर्घ काल तक भंडारित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, इसकी कटाई के उपरांत 18 से 23 फीसद तक फसलों को हानि पहुँचती है। यही कारण है, कि सरकार किसानों से लीची की नई किस्म का उत्पादन करने की अपील कर रही है।

### 2021-22 में लीची की पैदावार 308.1 मीट्रिक हुई थी

अधिकारियों के मुताबिक, गंडकी संपदा लीची काफी समय में पकती है। यह जून माह के बीच तक पक कर तैयार हो जाती है। गंडकी संपदा लीची का वजन 35-42 ग्राम तक होता है। इसका गूदा मलाईदार-सफेद, मुलायम एवं रसदार होता है। इसकी सुगंध भी काफी अच्छी होती है। इसके एक पेड़ से 140 किलो तक लीची अर्जित कर सकते हैं।

इसी प्रकार 'गंडकी योगिता' भी धीमी गति से उगती है, जो गर्मी की लहरों को झेल सकती है। बिहार में साल 2021-22 में लीची उत्पादन 308.1 मीट्रिक हुआ था। वहीं, साल 2020-21 में 308 मीट्रिक टन पैदावार हुई थी। बता दें कि शाही लीची को 2018 में जीआई टैग हांसिल होने से इसकी संपूर्ण विश्व में मांग बढ़ गई है।







# इस विदेशी फल से 6 माह में किसान कर सकते हैं मोटी कमाई जानें खेती करने का तरीका

## इस विदेशी फल से 6 माह में किसान कर सकते हैं मोटी कमाई, जानें खेती करने का तरीका

आजकल देश में देशी फलों के साथ-साथ विदेशी फलों की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अब देश के किसान विदेशी फलों की खेती की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाते जा रहे हैं। जिससे देश के किसान अब स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों की खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं। इन फलों की खेती में जहां उन्हें जबरदस्त मुनाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इन फलों की खेती में किसानों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।

इसी प्रकार का एक फल है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस फल का नाम है थाई एप्पल बेर (THAI APPLE BER)। जैसा की नाम से ही स्पष्ट है कि यह थाईलैंड में पाया जाने वाला फल है, जिसकी खेती अब भारत सहित कई देशों में की जाने लगी है। यह फल दिखने में सेब की तरह होता है, लेकिन खाने में इसका स्वाद बेर की तरह होता है। साथ ही इस फल में जबरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है।

बाजार में इस फल की डिमांड को देखते हुए किसान भाई शुरुआत में कम लागत से इस फल की खेती शुरू कर सकते हैं। थाई एप्पल बेर के पौधे लगाने के लिए सबसे पहले भूमि पर गड्डों की खुदाई की जाती है। ध्यान रहे कि गड्डों की लंबाई और चौड़ाई 2-2 फीट होनी चाहिए। साथ ही एक गड्ढे की दूसरे गड्ढे से दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। गड्डों की खुदाई करने के बाद कम से कम 25 दिन तक तेज धूप में इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 20-25 किलो जैविक खाद, या सड़ी गोबर की खाद से गड्डों को भर दिया जाता है। गड्डों को भरने में नीम की पत्तियों और नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

थाई एप्पल बेर की खेती में कलम विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाई एक बीघा खेत में 80 पौधों की रोपाई बेहद आसानी से कर सकते हैं। रोपाई करते समय ध्यान रखें की हर पेड़ के बीच कम से कम 15 फीट की दूरी अवश्य हो। इसके साथ ही पेड़ों के बीच खाली पड़ी जमीन में किसान भाई किसी भी प्रकार की सब्जियों की खेती कर सकते हैं ताकि किसान भाइयों को कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके।

इसकी खेती में मुख्यतः देसी और हाइब्रिड किस्मों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर थाई एप्पल बेर की खेती में इन किस्मों का इस्तेमाल करते हैं पेड़ से 6 माह के भीतर ही 100 किलो तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खेत में एक बार थाई एप्पल बेर के पेड़ को लगाने के बाद किसान भाई अगले 50 साल तक इससे फल प्राप्त सकते हैं और बाजार में महंगे दामों पर बेचकर मोटी कमाई कर सकते हैं।



# फूल

इस औषधीय गुणों वाले  
बोगनविलिया फूल की खेती  
से होगी अच्छी-खासी कमाई



इस औषधीय गुणों वाले बोगनविलिया फूल की खेती से होगी  
अच्छी-खासी कमाई

भारतीय किसानों को पारंपरिक खेती से घाटा होने के चलते उनको अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिलहाल, औषधीय पौधों एवं फूलों की खेती की जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको बोगेनवेलिया फूल की जानकारी प्रदान की जा रही है। जो केवल दिखने में अच्छी लगने के साथ-साथ विभिन्न एलोपैथिक व आयुर्वेदिक इलाज के लिए गुणकारी मानी जाती है।

भारत में बागवानी की तरफ किसान फिलहाल ज्यादा रुची रखने लगे हैं। इस वजह से किसानों को खेती करने हेतु बोगेनवेलिया फूल के संबंध में बताया जा रहा है। माना जा रहा है, कि जैसा नाम वैसा बहार क्योंकि इसको कागजी फूल के नाम से जाना जाता है। जो कि काफी कम देखभाल करने से भी रंगीन एवं सुंदर बनता जा रहा है।

बता दें, कि विभिन्न देशों में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। मुख्य तौर पर यह दक्षिण अमेरिका के देशों में पाया जाता है। इसकी खोज फिलबरट कॉमर्सन एवं लुई एंटोनी डी बोगनविले नाम के दो वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। इनमें से एक वैज्ञानिक के नाम पर इस पौधे का नामकरण किया गया है। यह पौधा आयुर्वेद में पेचिश, पेट, फेफड़ों, खांसी और दमा की तकलीफ से राहत दिलाने का कार्य करती है।

**बोगनविलिया की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु**

इन पौधों को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से 20 डिग्री से ऊपर तापमान होना चाहिए। अगर उस जगह पर जहां पौधों में सामान्य तौर पर ठंड होती है, तो उन्हें प्लास्टिक से अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहिए अथवा उनको अंदर रखना चाहिए।

**बोगनविलिया कटिंग के द्वारा इस प्रकार लगाएं**

सर्वप्रथम एक विकसित पौधे से 5-6 इंच की कटिंग निकाल लें, उसके बाद एक पारदर्शी जार में जल भरें पानी में बिल्कुल थोड़ी मात्रा में रूटिंग हॉर्मोन डालें। अब जल में कटिंग को डालकर ऐसे स्थान पर रखें जहां छनकर हल्की धूप आती हो। लगभग 5-6 दिनों में जल परिवर्तित कर दें। लगभग 10 दिन के उपरांत कटिंग से छोटी-छोटी जड़ें निकलने लगती हैं। तब इस कटिंग को गमले में लगाया जा सकता है।

**बीज से बोगनविलिया इस तरह लगाई जाती है**

बोगनविलिया बीज से उगाने हेतु एक परिपक्व पौधे के बराबर आवश्यकता होती है। यह बेहतरीन जल निकासी वाली मृदा, पर्याप्त धूप एवं अनुकूल बढ़ती परिस्थितियों की जरूर मांग करता है। सर्व प्रथम बीज की मोटाई के 2-3 गुना की गहराई तक उनको रोक करके बोए बीजों को नियमित तौर पर पानी दें। मिट्टी को नम रखें जिससे कि अंकुरण में सहायता मिल सके। अंकुरित होने में लगभग 30 दिन लगेंगे। जब बीज अंकुरित हो जाएं तब उन्हें गमले में स्थापित कर सकते हैं।

## सिंचाई कब और कैसे करें

जड़ सड़न बोगनविलिया की मृत्यु का सबसे आम वजह होती है। इसलिए सतर्क रहने एवं अत्यधिक सिंचाई करने से बचने की आवश्यकता होती है। विशेषकर जब पौधे गमलों में तैयार होते हैं। अधिक सिंचाई करने से फूलों की कीमत पर अस्थायी रूप से अंकुर, पत्तियों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, परंतु, आखिर में जड़-सड़न और पौधे की मृत्यु जैसे असर देखने को मिलेंगे। हालांकि, गर्मियों के कड़े तापमान में पौधे को प्रति दिन सिंचाई की आवश्यकता होगी। परंतु, सिंचाई केवल गमले की मिट्टी सूखने की स्थिति में करें।





# भारत में ऐसे करें डेज़ी फूल की खेती

## भारत में ऐसे करें डेज़ी फूल की खेती

डेजी एक सजावटी पौधा है जिसे दुनिया भर में उगाया जाता है। इसे अफ्रीकी डेज़ी, ट्रांसवाल डेज़ी और जरबेरा के फूल के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल मुख्य तौर पर इसका उत्पादन नीदरलैण्ड, इटली, पोलैण्ड, इजरायल और कोलम्बिया आदि देशों में किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि भारत में भी इस फूल की मांग तेजी से बढ़ी है। जिसके कारण कई राज्यों के किसानों ने डेज़ी फूल की खेती करना शुरू कर दी है। फिलहाल इस फूल की खेती मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात आदि राज्यों में हो रही है।

### डेजी फूल की खेती

यह एक बहुत ही लोकप्रिय फूल है, जिसका उपयोग घर की साज सज्जा में किया जाता है। इसके साथ ही इन फूलों का उपयोग गुलदस्ते बनाने में और विवाह में सजावट के दौरान भी बहुतायत में हो रहा है। इसलिए बाजार में इन फूलों की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण भारत के किसान इस खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मांग के अनुसार डेजी फूल की खेती करके किसान भाई अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।

### डेजी फूल के लिए इस प्रकार की जलवायु होती है उपयुक्त

डेजी फूल की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में की जाती है। इसकी खेती के लिए ठंड में धूप तथा गर्मियों में छायादार जगह की जरूरत होती है।

अगर दिन का तापमान 20°C-25°C और रात का तापमान 12°C-15°C के बीच हो तो यह डेजी फूल की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण हो सकता है। इसलिए इसकी खेती के लिए ग्रीन हाउस या पॉलीहाउस सबसे उपयुक्त विकल्प माना जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में डेजी फूल की खेती खुले मैदानों में भी की जा सकती है।

### इस प्रकार से करें मिट्टी का चयन

डेजी फूल की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन लैटराइट मृदा इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी से जल के उचित निकास के लिए व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मिट्टी का पीएचमान 5.0 से 7.2 के बीच होना चाहिए। मिट्टी में जीवांश पदार्थों की उपयुक्त मात्रा मिलाने पर डेजी फूल के पौधों की वृद्धि तेजी से होती है।

### ये हैं डेजी फूल की उन्नत किस्में

डेजी फूल की लगभग 70 अलग-अलग किस्में हैं जो विभिन्न रंगों के फूल देती हैं। इसलिए हम आपको फूलों के रंगों के आधार पर किस्मों को बताने जा रहे हैं।

- सफ़ेद फूल की उन्नत किस्में : फरीदा, व्हाइट मारिया, विंटर क्वीन, डेल्फी और स्नोफ्लेक।
- नारंगी रंग के फूल की किस्में : कोजक, ऑरेंज क्लासिक, कैरेरा, मारा सोल और गोलियथा।
- जामुनी रंग के फूल की किस्में : ब्लैक जैक और ट्रीजर।
- पीले रंग वाले फूल की किस्में : तलासा, फ्रेडकिंग, नाडजा, पनामा, फूलमून, डोनी, सुपरनोवा, मेमूट और यूरेनस।
- लाल रंग के फूल वाली किस्में : साल्वाडोर, रेड इम्पल्स, फ्रेडोरेल्ला, रूबीरेड, वेस्टा और तमारा।
- गुलाबी रंग के फूल की किस्में : रोसलिन, मारा, सल्वाडोर, पिंक एलिगेंस, रोसलिन, टेरा क्वीन और वेलेंटाइन।

ऐसे करें खेत की तैयारी

खेत में पलाऊ की सहायता से जुताई करके पुरानी फसल के बचे हुए अवशेषों और खरपतवारों को नष्ट करके मिट्टी में मिला दें। इसके बाद कम से कम 2 से 3 बार जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लें। खेत की जुताई करते समय गोबर की खाद मिलाएं। इससे खेत की उर्वराशक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। मिट्टी भुरभुरी होने के उपरांत अंत में खेत में पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को पूरी तरह से समतल कर दें।

डेजी फूल की खेती के लिए इस प्रकार से तैयार करें बेड

डेजी फूल की खेती के लिए ऐसे बेड तैयार करने चाहिए जिनमें पानी निकास की उचित व्यवस्था हो। ताकि पानी जल्द से जल्द खेत से बाहर भेजा जा सके। फूलों के पौधों की रोपाई के लिए 1.5 फीट ऊंचे और 2 से 3 फीट चौड़े बेड बनाने चाहिए। इसके साथ ही कतार से कतार की दूरी 1 फीट होना चाहिए। अगर किसान बेड बनाते समय नीम की खली का प्रयोग करते हैं तो पौधों में नेमाटोड जैसा रोग नहीं लगेगा।

इस समय पर करें डेजी फूल की बुवाई

डेजी फूल की बुवाई साल में तीन बार की जा सकती है। साल की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच इसकी बुवाई की जा सकती है, इसके बाद जून से जुलाई और नवंबर से दिसंबर के बीच इसकी बुवाई की जा सकती है।

डेजी फूल की रोपाई

जब इस फूल के पौधों की रोपाई करें तो यह ध्यान रखें कि पौधे का क्राउन मिट्टी से 2-3 सेमी ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही कतार से कतार की दूरी 35-40 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 25-30 सेमी होना चाहिए। एक बेड पर दो कतारों में डेजी फूल के पौधों को लगाया जा सकता है।

इस प्रकार से करें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग

डेजी फूल की खेती करते समय खेत तैयार होने के पहले 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश का प्रयोग करें। मिट्टी में आयर्न की कमी होने की स्थिति में 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फेरस सल्फेट का भी प्रयोग किया जा सकता है।

डेजी फूल की रोपाई

जब इस फूल के पौधों की रोपाई करें तो यह ध्यान रखें कि पौधे का क्राउन मिट्टी से 2-3 सेमी ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही कतार से कतार की दूरी 35-40 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 25-30 सेमी होना चाहिए। एक बेड पर दो कतारों में डेजी फूल के पौधों को लगाया जा सकता है।

इस प्रकार से करें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग

डेजी फूल की खेती करते समय खेत तैयार होने के पहले 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश का प्रयोग करें। मिट्टी में आयर्न की कमी होने की स्थिति में 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फेरस सल्फेट का भी प्रयोग किया जा सकता है।



- डेजी फूल की रोपाई
- जब इस फूल के पौधों की रोपाई करें तो यह ध्यान रखें कि पौधे का क्राउन मिट्टी से 2-3 सेमी ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही कतार से कतार की दूरी 35-40 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 25-30 सेमी होना चाहिए। एक बेड पर दो कतारों में डेजी फूल के पौधों को लगाया जा सकता है।
- इस प्रकार से करें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग
- डेजी फूल की खेती करते समय खेत तैयार होने के पहले 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटेश का प्रयोग करें। मिट्टी में आयरन की कमी होने की स्थिति में 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फेरस सल्फेट का भी प्रयोग किया जा सकता है।

### डेजी फूल की रोपाई

जब इस फूल के पौधों की रोपाई करें तो यह ध्यान रखें कि पौधे का क्राउन मिट्टी से 2-3 सेमी ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही कतार से कतार की दूरी 35-40 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 25-30 सेमी होना चाहिए। एक बेड पर दो कतारों में डेजी फूल के पौधों को लगाया जा सकता है।

इस प्रकार से करें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग

डेजी फूल की खेती करते समय खेत तैयार होने के पहले 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटेश का प्रयोग करें। मिट्टी में आयरन की कमी होने की स्थिति में 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फेरस सल्फेट का भी प्रयोग किया जा सकता है।

### डेजी फूलों की मांग एवं विपणन

अगर उत्पादन की बात करें तो डेजी फूलों का उत्पादन ज्यादातर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। लेकिन इसकी मांग दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, कोलकाता जैसे बाजारों में ज्यादा है। इसका प्रयोग ज्यादातर शादियों में साज सज्जा में किया जाता है। इसलिए इसकी बिक्री पर किसानों को अच्छी खासी कमाई होती है। डेजी फूल की खेती करके किसान कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं।



**POWERTRAC**  
देरा बा. १. विजयवाडी ट्रेक्टर



**POWERTRAC RDX**

किफ़ायत हो या ताकत  
अब कोई समझौता नहीं!



**ESCORTS**

# मानसून



## मई माह के कृषि संबंधी आवश्यक कार्य

### क्या होता है पावर वीडर? जानिए भारत के टॉप 5 पावर वीडर

#### ग्रीष्मकालीन जुताई

रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े है तो यह सही समय है खेतों को सुधारने का। ग्रीष्मकाल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बक्खर चला कर कर सकते है। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी में छुपे हुए कीटों के अंडे लावा इत्यादि बहार आ जाते है तथा धूप में अधिक तापमान के कारण मर जाते है। इसी प्रकार कई मृदाजनित रोगों के रोगाणु भी भूमि में दबे रहते है तथा फसलों को नुकसान पहुंचाते है। अगर गर्मी में गहरी जुताई करते है तो ये रोगाणु भी मर जाते है तथा फसलें रोगमुक्त पैदा होती है। कुछ बहुवर्षीय खरपतवारों से फसलों को बहुत नुकसान होता है तथा उनका नियंत्रण भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। जो खत उबड़-खाबड़ है उनको कंप्यूटर चालित लेजर समतलक से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो। कृषि कार्य सुविधाजनक तरीके से सम्पादित हो तथा जल की बचत हो सके। अगर गोबर की खाद, कम्पोस्ट आदि भी इसी माह मिट्टी में मिला दें जिससे उनका सही से अपघटन हो।

#### ग्रीष्मकालीन उड़द एवं मूंग की देखरेख

इस माह ग्रीष्मकालीन उड़द / मूंग की बुवाई संपन्न हो जाती है देरी की बुवाई की स्थिति में महीने की शुरुआत तक भी कई जगह बुवाई करते है। उड़दमूंग की उपयुक्त बीजदर 15-20 कि. ग्रा./हैक्टेयर होती है, परन्तु देरी से बुवाई की स्थिति में 4-5 कि.ग्रा./ हैक्टेयर अधिक बीज का उपयोग करें। यदि पौधे घने हो तो बुवाई के 15-20 दिन बाद पाही निराई-गुड़ाई के समय कुछ पादप उखाड़ कर पौध संख्या सही कर दें। समय समय पर सिंचाई करते रहें।

हो सके तो पूर्व फसलों के अवशेषों का आवरण पलवार के रूप में बिछा दें जिससे फसल में जल की बचल होती है तथा अधिक तापमान से होने वाले नुकसान से बच्चा जा सकता है।

#### खरीफ फसलों की बुवाई पूर्व तैयारी

महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई पूर्व तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना प्रारंभ हो जाता है

अतः उसके लिए भी उन्नत बीज, खाद, खरपतवारनाशी, कीटनाशी आदि की खरीद करके रखें। खेत की तैयारी भी पहले से ही करके रखें। अरहर व कपास की बुवाई भी समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत

बीज की खरीददारी जैसी तैयारी समय रहते कर लें जिससे की बुवाई में देरी ना हो। जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उनमें गोबर की खाद, कम्पोस्ट आदि इसी माह खेत में डाल कर मिट्टी में मिला दें। जो खेत उबड़ खाबड़ है उनको कंप्यूटर चालित लेजर समतलक से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में जल की बचत हो सके।

## सब्जियाँ

कट्टवर्गीय सब्जियों की बुवाई इस माह समाप्त कर लेनी चाहिए। इन सब्जियों की उन्नत किस्मों का चुनाव करें जो इस प्रकार हैं। खीरा पोइसेट, जापानीज लॉग ग्रीन, पूसा संयोग तथा पूसा उदय, लौकी- पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि. पी.एस.पी.एल. तथा पूसा हाइब्रिड-3य करेला पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड-2, चिकनी तोरी- पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, पूसा चिकनीय धारीदार तोरी- पूसा नसदार, सतपुतिया, पूसा नूतन, को-1, चप्पन कट्टू आस्ट्रेलियन ग्रीन, पैटी पैन, अर्ली येलो, पूसा अलंकार्य पैठी- पूसा उज्ज्वलय खरबूजा पूसा मधुरस, हरा मधु, पंजाब सुनहरी, दुर्गापुरा मधु लखनऊ सफेदा और पंजाब संकर-1, तरबूज- सुगर बेबी, असाही यामातो. अर्का व ज्योति, आदि। उपरोक्त बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15-20 टन / गोबर की खाद व 80 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 50 कि.ग्रा. फास्फोरस तथा 50 कि.ग्रा. पोटैश प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता होती है। खेत में लगभग 45 से.मी. चौड़ी तथा 30-40 से.मी. गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढवार के अनुसार 1.5 मी. से 5.0 मी. तक रखें। बुवाई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुवाई के लिए उपयुक्त हो जाए तो उनमें बीज बोएं।

इन फसलों की बीज दर इस प्रकार हैं- खीरा 22-2.5 कि.ग्रा. लौकी 4-5 कि.ग्रा. करेला 6-7 कि.ग्रा. कट्टू 3-4 कि.ग्रा., तोरी 5-5.5 कि.ग्रा., चप्पन कट्टू 5-6 कि.ग्रा. खरबूजा 15-20 कि.ग्रा. तरबूज 2.5-3.0 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर।

• भिंडी की अगेती बुवाई हेतु ए-4, परबनी क्रांति आदि किस्मों की बुवाई हेतु खेतों की तैयारी करें। बीज की मात्रा 20-25 कि.ग्रा./ हैक्टेयर रखें। 2 ग्रा. केप्टान अथवा थीरम से प्रति कि. ग्रा. बीज को उपचारित करें।

सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड @ 0.25 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से पके फलों की तुड़ाई के बाद छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम एक सप्ताह तक तुड़ाई न करें। बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण का विशेष ध्यान रखें।

प्याज की फसल में हल्की सिंचाई करें। फसल की इस अवस्था में उर्वरक न दे अन्यथा

फसल की वनस्पति भाग की अधिक वृद्धि होगी और प्याज की गांठ की कम वृद्धि होगी। • प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहे। थ्रिप्सकीट की संख्या अधिक पाए जाने पर कार्बारिल (2 ग्रा./ लीटर पानी) अथवा इमिडाक्लोप्रिड (1 मि.ली. / 4 लीटर पानी) किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपोल आदि (10 ग्रा./लीटर घोल) में मिलाकर आसमान साफ होने छिड़काव पर करें।

लहसुन में बैंगनी ब्लीच (धब्बा) रोग तथा थ्रिप्स कीटों का आक्रमण हो सकता है। अतः खेत की निरंतर निगरानी करते रहना चाहिए। रोग तथा कीट के पाए जाने पर मेंकोजेब (2 ग्रा./ लीटर) तथा कानफीडॉर (1 मि.ली. / लीटर) किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपोल आदि, (1 ग्रा./लीटर घोल) में मिलाकर छिड़काव करें।

टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं।

कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा देना चाहिए। साथ ही फल छेदक कीट

की निगरानी के लिए फेरोमोन प्रपंश @ 2-3 प्रपंश प्रति एकड़ की दर से लगाएं।

• बैंगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोहों को

इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो कीटनाशी स्पिनोसेड 48 ई.सी. @ 1 मि.ली. / 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। • लोबिया की उन्नतशील किस्मों जैसे पूसा कोमल अथवा पूसा फागुनी किस्मों की बुवाई करें।

• अगेती बोई गई बेलवाली सब्जियों में लाल भृंग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है।



यदि कीट की संख्या अधिक हो तो डाइक्लोरेवास 76 ई.सी. (डी.डी.वी.पी.) @ 1 ग्राम / लीटर

पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।

उद्यान

इस माह भी किसान भाई आम के बागों से मिलीबग कीटों के अंडों तथा नये प्रजन्मों को नष्ट करने के लिए जुताई कर सकते हैं। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर प्लास्टिक (1 फीट चौड़ा) का एक चदर तने के चारों ओर लगाएं तथा ग्रीस से सभी प्रकार के छिद्रों को बंद कर दें।

• मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाईयों को सलाह है कि ग्रीष्मऋतु के लिये गेदे की

तैयार पौध की रोपाई करें।

मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाईयों को अंगूर, आड़ू व आलुबुखारा आदि फलों में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें।

• जहाँ तक सम्भव हो इस माह किसी भी कीटनाशी का प्रयोग आम में न किया जाए, परन्तु आम के भुनगे का अत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास अथवा डाइमिथोएट के 10.05: घोल का एक छिड़काव कर सकते हैं। आम में खर्रा रोग का प्रकोप होने पर डिनोकेप 10.05: कवकनाशी का छिड़काव आवश्यक होता है। भुनगा कीट एवं खर्रा रोग की रोकथाम

हेतु कीटनाशी एवं कवकनाशी को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं।



# मशीनरी

## क्या होता है पावर वीडर? जानिए भारत के टॉप 5 पावर वीडर



## क्या होता है पावर वीडर? जानिए भारत के टॉप 5 पावर वीडर

खेती किसानों में ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जिनका किसान भाइयों को समय-समय पर सामना करना पड़ता है। जैसे फसल के साथ खरपतवार का उगना आम बात है। जिसके निराकरण के लिए किसानों को खेत में निराई गुड़ाई करना होती है। इससे किसानों को खरपतवार से छुटकारा मिलता है और फसल की वृद्धि तेजी के साथ होती है।

लेकिन खेत से खरपतवार को हटाना एक महंगा और पेचीदा सौदा है, क्योंकि इसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है और कई बार मांग के हिसाब से मजदूर नहीं मिल पाते। अगर मिलते भी हैं तो उन्हें ज्यादा मजदूरी भुगतान करनी पड़ती है जिससे किसानों की खेती की लागत बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए बाजार में इन दिनों एक मशीन आ रही है, जिसे पावर वीडर के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र देखने में पावर टिलर जैसा होता है जो खेत में किसानों और मजदूरों की मेहनत को कम करता है। इसका इस्तेमाल निराई गुड़ाई के लिए किया जाता है। मुख्यतः जिस जगह में ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता वहां पर निराई गुड़ाई के लिए यह बेहद उपयोगी यंत्र है। यह खेत में खरपतवार प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है पावर वीडर

पावर वीडर का सबसे पहला उपयोग खेत में निराई गुड़ाई करके खरपतवार को नष्ट करना है। इसके साथ ही यह यंत्र खरपतवार को काटकर पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता है। छोटे खेत की जुताई के साथ ही खेत में मिट्टी चढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी का समतलीकरण करना, जुताई के साथ खेत में मेढ बनाकर खेती के लिए भूमि तैयार करना और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना इसके अन्य कार्य हैं।

ये हैं पावर वीडर यंत्र की विशेषताएं

इस यंत्र का उपयोग विशेष तौर पर बागवानी फसलों में किया जाता है। इस यंत्र की सहायता से गन्ना, कपास, मक्का, केला, नारियल, सब्जियों आदि फसलों से खरपतवार को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। यह आकार में छोटा होता है इसलिए इसका इस्तेमाल हर तरह की जमीन में आसानी से किया जा सकता है। समतल खेत से लेकर ऊबड़ खाबड़ जमीन में यह बेहद प्रभावी होता है।

## पावर वीडर यंत्र से किसानों को होते हैं ये लाभ

यह एक ऐसा उपकरण है जो फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम पूरी तरह से करता है। साथ ही इसको खरीदने पर किसान को निराई गुड़ाई के लिए श्रमिकों की जरूरत नहीं होती, जिससे कृषि लागत में कमी आती है। इसके उपयोग के बाद खेत में हानिकारक रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना पड़ता। यह अवांछित घास को बेहद सफाई से हटाता है। साथ ही कृषि कार्य में लगने वाले समय की बचत करता है।

## इतनी होती है पावर वीडर की कीमत

भारत में पावर वीडर फिलहाल 2 प्रकार के आते हैं। पहला डीजल से चलने वाला पावर वीडर और दूसरा पेट्रोल चलने वाला पावर वीडर। पावर वीडर की कीमत जगह और शहर के ऊपर निर्भर करती है। यह अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हो सकती है। इसके साथ ही ऑटोमेटिक, सेमि-ऑटोमेटिक के आधार पर की इस यंत्र की कीमतें भिन्न होती हैं। लेकिन यदि हम देखें तो पावर वीडर की शुरुआती कीमत 10 हजार रुपये होती है जो 1.50 लाख रुपये तक जा सकती है।

## खरपतवार को नष्ट करने के लिए ऐसे करते है पावर वीडर का उपयोग

पावर वीडर का इस्तेमाल करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें की खेत की मिट्टी में नमी की मात्रा कम से कम 20 प्रतिशत हो। साथ मशीन चलाने से पहले मशीन की अच्छे तरह से जांच कर लें। इसके बाद हाथों की सहायता से धीरे-धीरे खरपतवार वाली लाइन में पावर वीडर को चलाएं। जब यह मशीन खरपतवार को नष्ट करके खाद में बदल दे तो उसके बाद मिट्टी को सूखने दें।

## ये हैं भारत के टॉप 5 पावर वीडर

### वीएसटी शक्ति FT50 जोश

यह वजन में बेहद हल्का पावर वीडर है जो मात्र 83 किलोग्राम वजन के साथ आता है। यह पेट्रोल से चलने वाला है जिसमें कंपनी ने शक्तिशाली गियरबॉक्स दिया है। इसमें 5 हॉर्सपावर का इंजन लगा है। जो समतल भूमि में बेहद अच्छे से कार्य करता है।

### वीएसटी एमटी 50 जीई

यह बाजार में आने वाले पावर वीडरों में से सबसे अच्छा पावर वीडर माना जाता है। यह भी 5 हॉर्सपावर के पेट्रोल इंजन के साथ आता है। इस मशीन में 3.6 लीटर की ईंधन टैंक उपलब्ध करवाया गया है। इस यंत्र का कुल भार 66 किलोग्राम है। वीएसटी एफटी50 जीई पावर वीडर बागवानी फसलों और रोपण फसलों के लिए बनाया गया है। जिसमें यह बेहद उम्दा परिणाम देता है।

### पबर्ट टिलर एआरओ प्रो 55P C3

यह एक पावर वीडर 6 हॉर्सपावर के साथ आता है। यह मशीन हर तरह के मौसम और हर तरह के खेतों और फसलों के लिए उपयुक्त है। यह भी पेट्रोल से चलता है, इसका इंजन एक घंटे में 600 मिलीलीटर ईंधन की खपत करता है।

### श्राची 105G

यह पेट्रोल से चलने वाला पावर वीडर है जो 6 से लेकर 8 इंच गहराई तक निराई गुड़ाई करता है। इसमें 18 से लेकर 32 ब्लेड तक आती हैं। यह एक भारी पावर वीडर है जिसका वजन 105 किलोग्राम है। यह एक घंटे में 750 मिलीलीटर ईंधन की खपत करता है।

### वीएसटी मेस्ट्रो 55P

यह पावर वीडर 5.6 हॉर्सपावर इंजन के साथ आता है। यह अन्य यंत्रों की अपेक्षा ईंधन की खपत कम करता है। साथ ही यह पावर वीडर भी हर तरह की फसल के लिए उपयोगी है।

## भारत में लॉन्च

# हुए ये

## 7 दमदार नए ट्रैक्टर



## भारत में लॉन्च हुए ये 7 दमदार नए ट्रैक्टर

ट्रैक्टर एक ऐसी मशीन है जिसके बिना आज के युग में खेती कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदवाने का प्रयास कर रही हैं जिसके लिए कई राज्य सरकारें नई-नई योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं। जिनमें ट्रैक्टर से लेकर कृषि उपकरण खरीद पर किसानों को भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकारों के साथ ही ट्रैक्टर निर्माता कंपनियां भी इस सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। खेती किसानों के काम को और अधिक सुगम बनाया जा सके, इसके लिए कंपनियां नई रिसर्च को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही ट्रैक्टरों के अत्याधुनिक तकनीक वाले नए मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। जिनको देखकर किसान नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इस साल कई कंपनियों ने अपने नए ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।

### महिंद्रा नोवो 755 डीआई ट्रैक्टर

महिंद्रा नोवो 755 डीआई ट्रैक्टर चार सिलेंडर के साथ आने वाला 75 एचपी का ट्रैक्टर है। अगर इसके इंजन रेटेड आरपीएम की बात करें तो यह 2100 आरपीएम आता है। इसके साथ ही इस ट्रैक्टर की पीटीओ क्षमता 66 एचपी है। महिंद्रा के इस ट्रैक्टर में कंपनी ने 3500 सीसी का इंजन दिया है। इसमें कंपनी ने ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी दी है। इसके साथ ही ट्रैक्टर को ड्यूल-क्लच के साथ लॉन्च किया गया है। यह ट्रैक्टर मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है जिससे फिसलन की समस्या नहीं रहती।

महिंद्रा के इस ट्रैक्टर में 60 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। यह ट्रैक्टर 2WD और 4WD दोनों वैरियंट में उपलब्ध है। ट्रैक्टर का वजन 2600 किलोग्राम है। साथ ही इस ट्रैक्टर की कीमत 12.30 लाख रुपए से लेकर 12.90 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है।

### जॉन डियर 3036 ईएन ट्रैक्टर

जॉन डियर 3036 ईएन एक मिनी ट्रैक्टर है। जो 1500 सीसी इंजन के साथ आता है। यह तीन सिलेंडर इंजन के साथ आता है जो 2800 इंजन रेटेड आरपीएम जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर में फ्यूल टैंक की क्षमता 32 लीटर है। साथ ही इसमें पीटीओ पावर 30.6 एचपी है। इस ट्रैक्टर की बाजार में कीमत 7.20 लाख रुपये से लेकर 7.80 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है। जिसके कारण भारतीय बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है।



## न्यू हॉलैंड एक्सेल 5510 ट्रेक्टर

न्यू हॉलैंड एक्सेल 5510 ट्रेक्टर 3 सिलेंडर वाला 50 एचपी का ट्रेक्टर है। इसकी पीटीओ पावर 46 एचपी है। यह 2931 सीसी इंजन के साथ आता है, जिसमें कंपनी की तरफ से सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन दिया गया है। यह ट्रेक्टर हाइड्रोस्टैटिक स्टीयरिंग के साथ आता है, जिसमें 100 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। ट्रेक्टर 2500 किलोग्राम तक का वजन उठाया सकता है। इसके साथ ही ट्रेक्टर में कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स दिए हैं जो अन्य ट्रेक्टरों में नहीं आते हैं। इस ट्रेक्टर की बाजार में कीमत 9.97 लाख रुपये से लेकर 11.65 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है।

## मैसी फर्ग्यूसन 8055 मैनाट्रैक ट्रेक्टर

इस ट्रेक्टर को हाल ही में मैसी ने लॉन्च किया है। जो 3 सिलेंडर के बेहद शक्तिशाली 3300 सीसी के इंजन के साथ आता है। यह ट्रेक्टर 50 एचपी के साथ आता है, जिसमें पीटीओ पावर 46 एचपी है। इस ट्रेक्टर में कंपनी ने ड्यूल क्लच ऑफर की हैं। इस ट्रेक्टर में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिए गए हैं। इस ट्रेक्टर की बाजार में कीमत 6.80 लाख रुपये से लेकर 7.40 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है।

## फार्मट्रैक 60 ट्रेक्टर

फार्मट्रैक 60 ट्रेक्टर एक शानदार ट्रेक्टर है जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। यह 50 एचपी का ट्रेक्टर है जो 2200 आरपीएम जनरेट करता है। फार्मट्रैक 60 ट्रेक्टर में 3147 सीसी का इंजन आता है। जो 2200 इंजन रेटेड आरपीएम जनरेट करता है। इस ट्रेक्टर में फ्यूल टैंक की क्षमता 50 लीटर आती है। इसके गियर बॉक्स में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर आते हैं। यह ट्रेक्टर 1400 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। इस ट्रेक्टर की कीमत 7.10 लाख रुपये से लेकर 7.40 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है।

## प्रीत 6049 सुपर ट्रेक्टर

प्रीत 6049 सुपर एक शक्तिशाली ट्रेक्टर है जो 3 सिलेंडर के 4087 सीसी इंजन के साथ आता है। इसमें कंपनी पावर स्टीयरिंग के साथ ड्यूल क्लच ऑफर करती है। इस ट्रेक्टर में 60 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। साथ ही यह ट्रेक्टर 2200 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है।

## वीएसटी 929 डीआई, ईजीटी ट्रेक्टर

कंपनी ने इस ट्रेक्टर को शानदार डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। यह 28 एचपी का ट्रेक्टर है जो तीन सिलेंडर के साथ आता है। इस ट्रेक्टर का इंजन रेटेड 2400 आरपीएम है। इसके साथ ही इसके गियर बॉक्स में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स हैं। साथ ही यह पावर स्टीयरिंग के साथ आता है जो 750 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम है। इस ट्रेक्टर की बाजार में कीमत 4.80 लाख रुपये से लेकर 6.10 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है।



# मौसमी व अन्य कृषि सुझाव



**सुगंधित फसलों को उगाने के लिए सरकार दे रही है ट्रेनिंग, होगा बंपर मुनाफा**

## सुगंधित फसलों को उगाने के लिए सरकार दे रही है ट्रेनिंग, होगा बंपर मुनाफा

इन दिनों देश में विभिन्न प्रकार की फसलों का चलन बढ़ा है। अलग-अलग तरह की फसलों को उत्पादित करने से किसानों को मोटा मुनाफा हो रहा है। इसलिए किसानों का रुझान इस ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए सरकार अब सुगंधित फसलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसे 'एरोमा मिशन' का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को लेमन ग्रास, पामारोजा, मिंट, तुलसी, जिरेनियम, अश्वगंधा, कालमेघ, पचौली और कैमोमाइल जैसी फसलों को उगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग लखनऊ में आयोजित की जाएगी।

सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध अनुसंधान संस्थान मिलकर आगामी 26 से 28 अप्रैल तक किसानों के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू कर रहा है। जिसमें किसानों को सुगंधित फसलों की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में फसलों की प्रोसेसिंग की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसलों की गुणवत्ता और बाजार में उनके भाव को लेकर भी जागरूक किया जाएगा।



जो भी किसान भाई इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो डायरेक्टर सीआईएमएपी, लखनऊ के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक में 3 हजार रुपये की फीस का भुगतान कर सकते हैं। जिसका खाता नंबर 30267691783 है तथा IFSC कोड SBIN000012 है। इसके बाद रुपये भेजने का प्रमाण पत्र या रशीद मेल आईडी TRAINING@CIMAP.RES.IN पर भी भेजें।

सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध अनुसंधान संस्थान ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। किसान को ट्रेनिंग के दौरान लखनऊ में रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी। ट्रेनिंग के दौरान किसानों को दोपहर का खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बार की ट्रेनिंग के लिए मात्र 50 सीटें उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई 0522-2718596, 598, 606, 599, 694 पर संपर्क कर सकते हैं।



# इन तकनीकों से उत्पादन कर किसान कमा रहे हैं मोटा मुनाफा



## इन तकनीकों से उत्पादन कर किसान कमा रहे हैं मोटा मुनाफा

पारंपरिक खेती करके किसान भाई केवल किसानों की आजीविका ही चलती थी। लेकिन, खेती की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आमदनी काफी बढ़ती जा रही है। यह तकनीकें कृषकों का धन, समय और परिश्रम सब बचाती हैं। इसलिए किसानों को फिलहाल आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके उत्पादन करने की बेहद आवश्यकता है।

आधुनिकता के वक्त में हमारी खेती भी अग्रिम होती जा रही है। क्योंकि विज्ञान द्वारा इतनी प्रगति कर ली गई है, कि फिलहाल नवीन तकनीकों से संसाधनों की बचत के साथ-साथ लाभ अर्जित करना भी सुगम हो गया है। इस कार्य में नवीन मशीनें एवं तकनीकें किसानों की हेल्पिंग हैंड की भूमिका अदा कर रही हैं।

### ड्रिप सिंचाई तकनीक से करें उत्पादन

संपूर्ण विश्व जल की कमी से लड़ रहा है, इस वजह से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरीके की तकनीकें जो कम सिंचाई में भरपूर पैदावार मिलती है। सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक शामिल हैं। इन तकनीकों द्वारा सीधे फसल की जड़ों तक जल पहुंचता है। ड्रिप सिंचाई से 60 प्रतिशत जल की खपत कम होती है। फसल की पैदावार में भी काफी वृद्धि देखी जाती है।

### वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से खेती करें

संपूर्ण विश्व में खेती का रकबा कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बढ़ती जनसंख्या की खाद्य-आपूर्ति करना कठिन होता जा रहा है। यही कारण है, कि विश्वभर में वर्टिकल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वर्टिकल फार्मिंग को खड़ी खेती भी कहा जाता है, जिसमें खेत की आवश्यकता नहीं, बल्कि घर की दीवार पर भी फसलें उत्पादित की जा सकती हैं। यह खेती करने का सफल तरीका माना जाता है। इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि में भी अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे पैदावार भी ज्यादा होती है।

### शेड नेट फार्मिंग के जरिए करें खेती

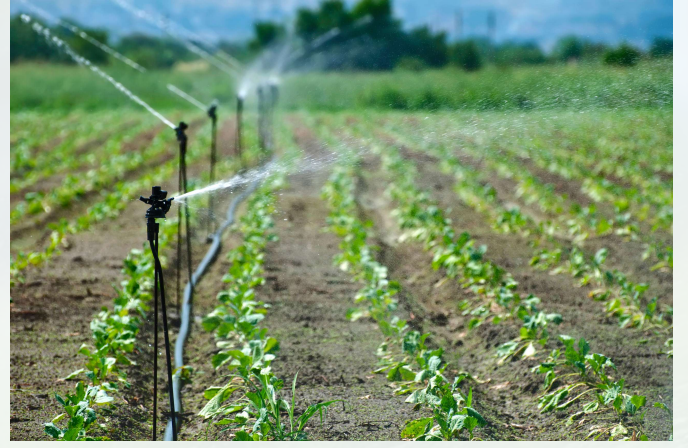
जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से खेती-किसानी में हानि होती जा रही है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, सूखा और कीट-रोगों के संक्रमण से फसलों में काफी हद तक हानि हो रही है, जिसको कम करने हेतु किसानों को शेडनेट फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव फसलों पर ना पड़े, इस वजह से ग्रीनहाउस, लो टनल, पॉलीहाउस जैसे संरक्षित ढांचे स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें गैर मौसमिक बागवानी फसलें भी वक्त से पहले उत्पादित हो जाती हैं।

### शेड नेट फार्मिंग के जरिए करें खेती

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से खेती-किसानी में हानि होती जा रही है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, सूखा और कीट-रोगों के संक्रमण से फसलों में काफी हद तक हानि हो रही है, जिसको कम करने हेतु किसानों को शेडनेट फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव फसलों पर ना पड़े, इस वजह से ग्रीनहाउस, लो टनल, पॉलीहाउस जैसे संरक्षित ढांचे स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें गैर मौसमिक बागवानी फसलें भी वक्त से पहले उत्पादित हो जाती हैं।

## शेड नेट फार्मिंग के जरिए करें खेती

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से खेती-किसानी में हानि होती जा रही है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, सूखा और कीट-रोगों के संक्रमण से फसलों में काफी हद तक हानि हो रही है, जिसको कम करने हेतु किसानों को शेडनेट फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव फसलों पर ना पड़े, इस वजह से ग्रीनहाउस, लो टनल, पॉलीहाउस जैसे संरक्षित ढांचे स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें गैर मौसमिक बागवानी फसलें भी वक्त से पहले उत्पादित हो जाती हैं।



Hydrex

# EURO 45 PLUS 4X4

ESCORTS

**चारों पहिये करे काम**  
ताकत. सुख्खा. गति. आराम

35 kW  
(47.1 HP)

8+8  
Dual Axle





यहां के किसान मिर्च की  
खेती से हो रहे हैं  
मालामाल.



सरकार भी कर रही है मदद



## यहां के किसान मिर्च की खेती से हो रहे हैं मालामाल, सरकार भी कर रही है मदद

पंजाब के फिरोजपुर जिले में इन दिनों किसान गेहूं-चावल की फसल को बहुत हद तक कम उत्पादित कर रहे हैं। इसकी जगह उन्होंने अब एक नई फसल की खेती प्रारंभ की है जिसे मिर्च की खेती के नाम से जानते हैं। मिर्च का इस्तेमाल ज्यादातर भारतीय व्यंजनों में स्वाद को बढ़ाने के लिए मसाले के रूप में होता है। बाजार में लाल मिर्च के साथ-साथ हरी मिर्च भी बड़ी मात्रा में बिकती है, इसलिए फिरोजपुर के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर मिर्च की खेती करना शुरू कर दी है। वैसे तो मिर्च की खेती के लिए फिरोजपुर की खास पहचान नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा हाल ही में फसल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के अपने अभियान के तहत इस जिले में एक मिर्च क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की गई है।

पंजाब सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में मिर्च का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसलिए सरकार मिर्च क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत मिर्च उत्पादकों को सहूलियतें भी मुहैया करवा रही है। सरकार की कोशिश है कि राज्य से मिर्च का अधिक से अधिक निर्यात किया जाए, साथ ही किसानों को गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी मदद भी मुहैया कारवाई जाए ताकि घरेलू बाजार में उनकी पकड़ मजबूत हो सके।

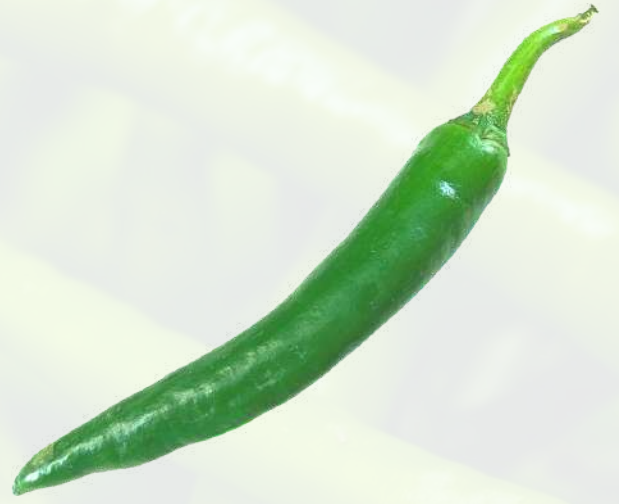
वर्तमान में पंजाब राज्य में 10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर मिर्च का उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें किसान हर साल लगभग 20,000 टन मिर्च का उत्पादन करते हैं। वैसे तो देश में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन होता है लेकिन पंजाब का भी इस खेती में अपना एक अलग स्थान है।

मिर्च उत्पादक किसानों ने बताया है कि परंपरागत खेती के इतर मिर्च की खेती में प्रति एकड़ लगभग 1.50 से 2 लाख रुपये की आमदनी होती है। वहीं गेहूं और धान की खेती में इतनी ही जमीन पर मात्र 90 हजार रुपये की कमाई हो पाती है। इसलिए गेहूं, चावल की अपेक्षा मिर्च से होने वाली कमाई बहुत ज्यादा है। यह फसल नवंबर में लगाई जाती है और मार्च के महीने के तैयार हो जाती है।

फिरोजपुर के एक किसान ने बताया कि वो फिरोजपुर के एक गांव में 100 एकड़ जमीन पर मिर्च की फसल उगाते हैं, जिसमें प्रति एकड़ 2 लाख रुपये की मिर्च का उत्पादन होता है। बाजार में लाल मिर्च 200-250 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाती है जबकि हरी मिर्च का भाव 20-25 रुपये प्रति किलो होता है। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर की मिर्च को अब बाजार में पहचान मिल गई है, यही कारण है कि अब पड़ोसी राज्य राजस्थान के गंगानगर के व्यापारी और आंध्र प्रदेश के व्यापारी यहां मिर्च खरीदने आते हैं।



यहां की लाल मिर्च ज्यादातर गुजरात में भेजी जाती है, जबकि गहरे रंग की हरी मिर्च नागपुर, भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भेजी जाती है। वहां इस फसल की जबरदस्त मांग रहती है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अभी फिलहाल फिरोजपुर जिले के तीन ब्लॉक- घल खुर्द, फिरोजपुर और ममदोट में मिर्च की खेती की जा रही है। इस खेती में किसानों को लाभ हो और किसान इसके प्रति जागरूक हों, इसलिए जिले में क्लस्टर विकास का तरीका अपनाया गया है। इससे मिर्च उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। अधिकारियों ने आगे बताया कि पंजाब में फिरोजपुर के अलावा पटियाला, मलेरकोटला, संगरूर, जालंधर, तरनतारन, अमृतसर, एसबीएस नगर और होशियारपुर जिलों में भी मिर्च की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।



# सरकारी नीतियां



**इस राज्य में आमदनी दोगुनी करने वाली तकनीक के लिए दिया जा रहा 50 % अनुदान**

## इस राज्य में आमदनी दोगुनी करने वाली तकनीक के लिए दिया जा रहा 50 % अनुदान

छत्तीसगढ़ राज्य के कृषक बड़े पैमाने पर शेडनेट तकनीक द्वारा फूलों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी भी काफी बढ़ गई है। किसान केवल पारंपरिक फसलों की खेती से हटकर फूल उगाकर भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। फूलों की मांग भारत सहित पूरी दुनियाभर में है। यदि किसान भाई शेडनेट तकनीक से फूलों का उत्पादन करें, तब उनको अधिक आमदनी होगी। इस तकनीक से जरिए वर्षभर एक ही खेत में फूल का उत्पादन किया जा सकता है। शेडनेट तकनीक में खर्चा भी कम आता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई शेडनेट तकनीक का उपयोग करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के अनुसार, छत्तीसगढ़ के किसान बड़े पैमाने पर शेडनेट तकनीक द्वारा फूलों का उत्पादन कर रहे हैं। नतीजतन, उनकी आमदनी भी काफी बढ़ चुकी है। साथ ही, इस तकनीक के चलते फूलों की पैदावार भी बढ़ गई है। विशेष बात यह है, कि यहां के कृषक शेडनेट के अतिरिक्त पॉली हाऊस, ड्रिप और मल्लिंग तकनीक द्वारा भी फूलों की खेती कर रहे हैं। इन किसानों द्वारा उत्पादित फूलों की मांग हैदराबाद, भुवनेश्वर, अमरावती और नागपुर जैसे बड़े शहरों में भरपूर है।

शेडनेट तकनीक किसानों की मेहनत कम कर देती है

फूलों की खेती करने के लिए शेडनेट तकनीक बेहद फायदेमंद है। इस तकनीक के उपयोग से खेती करने पर फसल में कीट संक्रमण और रोगिक भय नहीं रहता है। अब ऐसी स्थिति में फूलों की पैदावार एवं गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ता है। विशेष बात यह है, कि दीर्घकाल तक एक ही स्थान पर फसल के लगे रहने से कृषकों को परिश्रम कम करना पड़ता है। इससे उनकी आमदनी भी दोगुनी हो जाती है।

छत्तीसगढ़ सरकार शेडनेट तकनीक के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है

जानकारों के अनुसार, इस तकनीक का उपयोग गर्मी से पौधों को संरक्षण देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शेडनेट के अंतर्गत आप गर्मी के मौसम में नहीं उगने वाले पौधों का भी उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही, बारिश के मौसम में भी शेडनेट के कारण फूल सुरक्षित रहते हैं।

परंतु, फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार अपने प्रदेश में इस तकनीक के माध्यम से खेती करने वाले कृषकों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित खेती हेतु 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना के चलते किसान भाई ज्यादा से ज्यादा 4000 वर्गमीटर में शेडनेट स्थापित कर सकते हैं।

किसान लगभग 10 लाख रुपये तक की आमदनी कर रही है

छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जनपद के डोंगरगढ़ विकासखंड में किसान शेडनेट तकनीक के इतेमाल से बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं। बता दें, कि ग्राम कोलिहापुरी के किसान गिरीश देवांगन ने जखेरा, रजनीगंधा और गुलाब की खेती कर रखी है।

इससे वर्षभर में लगभग 10 लाख रुपये की आमदनी हो रही है। गिरीश देवांगन के अनुसार, उनके गांव में उत्पादित किए जाने वाले फूलों की अधिकांश मांग सजावट के उद्देश्य से हो रही है। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर, हैदराबाद, अमरावती एवं नागपुर में भी इस गांव से फूलों का निर्यात किया जा रहा है।

ESCORTS

**EURO 45 PLUS**  
**4X4**

**चारों पहिये करे काम**  
**ताकत. सुरक्षा. गति. आराम**

**35 KM**  
**(MPH)**

**8+8**  
**(Gear)**

**ESCORTS**

# इस राज्य सरकार ने आल इन वन तरह का कृषि ऐप जारी कर किसानों का किया फायदा



## इस राज्य सरकार ने आल इन वन तरह का कृषि ऐप जारी कर किसानों का किया फायदा

आधुनिक युग में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन के लिए किसान भाईयों को ई-मित्र केंद्र अथवा कृषि विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि, राजस्थान में खेती-किसानी करने वालों के लिए राज किसान एप पर ऐसी विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

सीधी सी बात है, अगर कृषि क्षेत्र की प्रगति एवं विकास-विस्तार होगा तो किसान भी की उन्नत और खुशहाल होंगे। सरकार इसको बरकरार रखने के लिए किसानों की निरंतर रूप से हर संभव सहायता करती है। इसलिए किसानों के हित में विभिन्न कृषि योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिसके माध्यम से बीमा, लोन एवं अनुदान आदि का फायदा प्राप्त होता है। इन योजनाओं से जुड़कर किसान भाई अपने आर्थिक हालातों को अच्छा कर सकते हैं। परंतु, कृषि योजनाओं के विषय में जानकारी इकट्ठी करना एवं आवेदन करना किसान भाइयों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बहुत बार किसानों को कृषि विभाग से लेके ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर तक काटने पड़ते हैं।

इन सभी स्थितियों से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए फिलहाल राज्य सरकारें मोबाइल एप्लीकेशन जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की तरफ से भी राज किसान एप्लीकेशन जारी किया गया है।

### केवल एक क्लिक से मिलेगी सभी योजनाओं की जानकारी

राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदेश के किसानों के लिए राज किसान एप्लीकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत कृषि विभाग से लेकर बागवानी एवं पशुपालन विभाग की नई-पुरानी समस्त योजनाओं की जानकारी चढ़ा दी जाती है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज किसान एप पर स्व-पंजीकरण का विकल्प दिया गया है। मललब कि फिलहाल किसान भाई अपना पंजीकरण करके सीधे कृषि योजनाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं।

### क्षतिग्रस्त फसल की शिकायत भी यहीं दर्ज होगी

राज किसान साथी पोर्टल को पूर्णतया किसानों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें फसल बीमा क्लेम से लेकर ब्याज की जानकारी, ऑनलाइन अदायगी के साथ फसल क्षति की शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।

इन समस्त कार्यों हेतु कृषि विभाग द्वारा राज किसान एप पर फसल बीमा का कॉलम भी बनाया गया है। एक ही प्लेटफॉर्म पर यह समस्त सुविधाएं प्राप्त होने से ना केवल किसान का वक्त बचेगा, साथ ही, पैसे की भी बचत होगी।

## कृषि से संबंधित सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई है

राजस्थान के किसान केवल खेती-किसानी तक ही सीमित नहीं रहे हैं। साथ ही, दूसरी गतिविधियों से भी जुड़कर अच्छी आय कर रहे हैं। इसके लिए राज किसान साथी एप पर एग्री मशीनरी की बुकिंग, कीट-रोग प्रबंधन की जानकारी, उन्नत कृषि तकनीक, मिट्टी और पानी की जांच के लिए नजदीकी लैब, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग, कृषि कार्यों की वीडियो, खाद्य उत्पादक और निर्यातकों की लिस्ट-मोबाइल नंबर, मशीनों की खरीद या किराए पर उठाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स की जानकारी, खाद उर्वरक व कीटनाशक विक्रेताओं की सूची एवं इसके उपयोग करने के तरीके की भी एप पर जानकारी दी गई है।





## मखाना बीजों के उत्पादन के लिए सरकार दे रही है अनुदान, किसानों को मिलेगी मोटी रकम

### मखाना बीजों के उत्पादन के लिए सरकार दे रही है अनुदान, किसानों को मिलेगी मोटी रकम

देश में मखाना एक मुख्य आहार है, जिसका उपयोग उपावस से लेकर खाना और मिठाई बनाने में बहुतायत से किया जाता है। मखाने की खेती देश के कई राज्यों में की जाती है, लेकिन बिहार इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में उत्पादित होने वाले मखाना का 80 से 90 फीसदी सिर्फ बिहार में उत्पादित किया जाता है। बिहार में ज्यादातर मखाना मिथिला में उगाया जाता है। यहां के मखाने की ख्याति देश विदेशों तक फैल चुकी है, इसलिए सरकार ने यहां के मखाने को जीआई टैग दिया है। चूंकि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है इसलिए इसे सुपरफूड के नाम से भी जाना जाता है।

बिहार सरकार अब राज्य में उत्पादित होने वाले मखाने की क्वालिटी पर फोकस कर रही है। जिसके तहत मखाना अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। साथ ही मखाना विकास की कई योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसके तहत मखाना उत्पादन करने वाले किसानों को कई तरह की सहूलियतें उपलब्ध कारवाई जाती हैं। अब बिहार की राज्य सरकार मखाना किसानों को इसके बीज उत्पादन के लिए 50 से 75 फीसदी तक की सब्सिडी मुहैया करवाती है।

बिहार के कृषि विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मखाना विकास योजना के तहत मखाना के उच्च प्रजाति के बीजों का उत्पादन करने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार ने अपनी गणना के अनुसार प्रति हेक्टेयर 97 हजार रुपये की लागत निर्धारित की है। जिस पर 75 फीसदी की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जो अधिकतम 2,750 रुपये तक हो सकती है। इस हिसाब से एक हेक्टेयर में खेती करने के लिए किसान को मात्र 24,250 रुपये ही खर्च करने होंगे।

#### इन किस्मों के बीज उत्पादन पर देती है सरकार अनुदान

कृषि विभाग ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि बिहार सरकार की तरफ से मखाना की मुख्यतः 2 किस्मों पर अनुदान दिया जाता है। जिनमें साबौर मखाना-1 और स्वर्ण वैदेही प्रभेद को सम्मिलित किया गया है। इन दो किस्मों के जरिए ही राज्य सरकार प्रदेश में मखाने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।

असली हीरो की ताकत  
भरोसे की विरासत



## इस मौसम में होती है मखाने की खेती

बिहार में दो मौसम में मखाने की खेती की जाती है। साल में पहली बार में फसल मार्च अप्रैल में लगाते हैं, जिससे अगस्त-सितंबर तक मखाने का उत्पादन कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरी बार फसल सितंबर-अक्टूबर में लगाते हैं जिसका उत्पादन फरवरी-मार्च में मिलता है। मखाने के बीजों के उत्पादन के बाद भी इसमें काफी काम होता है। इसके बीजों को तेज धूप में सुखाया जाता है, इसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है और ग्रेडिंग की जाती है। सबसे अंत में मखाने को गर्म रेत में सेंककर छिलका हटा देते हैं। अगर एक मौसम की बात करें तो किसान भाई इस खेती से आराम से 5 लाख रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं।







## किसानों के लिए खत्म होगा बिजली का संकट, 2 हजार यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त

### किसानों के लिए खत्म होगा बिजली का संकट, 2 हजार यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त

केंद्र सरकारों के साथ राज्य सरकारें भी किसानों की हर संभव सहायता कर रही हैं ताकि किसानों के ऊपर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ न आए और वो फसल उत्पादन पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर सकें। इसी के तहत अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को उर्जा मित्र योजना के तहत 2 हजार यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इससे राज्य के 14 लाख किसानों को सीधे फायदा होगा और उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं का 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ कर दिया गया है। जिससे 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा और उन्हें अब बिजली बिल नहीं देना होगा। मतलब उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा।

अशोक गहलोत सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला किसानों के लिए फायदेमंद होने वाला है। अभी तक किसान भी महंगे बिजली बिल के कारण अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब रियायती दामों पर बिजली मिलने के कारण किसान भाई अपनी इच्छा के अनुसार खेतों की सिंचाई कर पाएंगे। जिसके चलते उत्पादन ज्यादा होगा और किसानों को बंपर मुनाफा मिलेगा। मुफ्त बिजली का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जिनका पहले से कोई बिजली बिल बकाया नहीं है।

2 हजार यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को बिजली का अनुदान उनके बैंक खातों के माध्यम से दिया जाएगा।

इससे किसान बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और बिजली की फिजूलखर्ची पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान को अपने बिजली बिल क्रमांक को बैंक खाता नंबर से लिंक करवाना होगा।

मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए उन्हें सबसे पहले नजदीकी बिजली विभाग के दफ्तर में जाना होगा। यहां पर एक आवेदन पत्र में नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, फोटो जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही बिजली बिल की कॉपी और आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी होगी। जिसके बाद किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

इस योजना को सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 मई 2021 को प्रारंभ किया था। जिसके माध्यम से अब तक करोड़ों किसानों के साथ लाखों लोगों को बिजली बिल पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देना है। सरकार के आदेश के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं।



**सरकार किसान बेटियों को देगी हर साल 40,000 की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी**

## **सरकार किसान बेटियों को देगी हर साल 40,000 की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी**

खेती-किसानी और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक करने एवं उनको सशक्त कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराने की पहल की जा रही है। बेटियों को आधुनिक किसान बनाने के लिए राज्य सरकार 40,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है।

कृषि क्षेत्र की उन्नति एवं किसानों के कल्याण के लिए पुरे भारत में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान एवं किसान परिवारों को आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण मुहैया कराया जा रहा है। खेती-किसानी एवं संबंधित गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए भी विभिन्न कोशिशों की जा रही हैं। इसी कड़ी में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, इन कदमों से महिलाएं आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी अनोखी पहल की है।

### **छात्रा प्रोत्साहन योजना क्या होती है**

प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए छात्रा प्रोत्साहन योजना जारी की है। जिसके अंतर्गत कृषि विषय पढ़ने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप पर 40,000 रुपये तक का सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य के नवीन बजट में भी छात्रा प्रोत्साहन योजना की धनराशि को बढ़ा दिया गया है।

इससे ग्रामीण इलाकों में पली-बड़ी किसान परिवारों की बेटियों को काफी सहयोग मिलेगा। हालांकि, शहरी बालिकाओं को भी छात्रा प्रोत्साहन का समतुल्य फायदा प्रदान करने का प्रावधान है।

### **छात्रा प्रोत्साहन योजना की पात्रता क्या होनी चाहिए**

राजस्थान में कृषि संकाय से पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये तक का सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु राज्य सरकार ने पात्रता भी घोषित की है, जिसके अंतर्गत केवल प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन करने वाली छात्राओं के पास खुद का बैंक खाता भी होना चाहिए। जिससे कि सब्सिडी की धनराशि खाते में हस्तांतरित की जा सके। छात्रा प्रोत्साहन योजना के नियमानुसार किसी राजकीय अथवा सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर क्षेत्र के साथ अध्ययनरत हों।

### **इन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी**

छात्रा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने से पूर्व राज किसान पोर्टल वेबसाइट [HTTP://RAJKISAN.RAJASTHAN.GOV.IN](http://RAJKISAN.RAJASTHAN.GOV.IN) पर जाके विस्तृत से जानकारी ले सकते हैं। चाहें तो स्वयं के जनपद में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि उपनिदेशक से भी संपर्क साधा जा सकता है। इस योजना में आवेदन करने वाली छात्राएं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्क शीट अथवा ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साइन वाला प्रमाण पत्र एवं स्व-प्रमाणित पत्र, जिसमें कृषि संकाय को परिवर्तित करने के विषय में लिखा हो, आदि दस्तावेज भी अटैच करने पड़ेंगे।

# 10 रुपये की फिक्स डिपॉजिट

पर मिलेंगे पेड़, किसानों की होगी बंपर कमाई

## 10 रुपये की फिक्स डिपॉजिट पर मिलेंगे पेड़, किसानों की होगी बंपर कमाई

इन दिनों देश में खेती किसानों को भी मुनाफे वाले व्यवसायों में गिना जाने लगा है, क्योंकि अब देश के किसान आधुनिक तरीकों से खेती करके कम समय में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अब किसान पारंपरिक खेती के अलावा पेड़ों की खेती की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। अगर किसान धैर्य बनाए रखें तो कई ऐसे पेड़ हैं जो समय के साथ किसानों को बंपर मुनाफा प्रदान करते हैं।

किसानों की आय बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य के वन विभाग ने एक नई योजना लॉन्च की है, जिसे 'कृषि वानिकी योजना' कहा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वन विभाग की तरफ से किसानों को मात्र 10 रुपये की सिक्वोरिटी डिपॉजिट पर पौधे दिए जा रहे हैं। 3 साल बाद यह सिक्वोरिटी डिपॉजिट 6 गुना अधिक अनुदान के साथ किसानों को वापस कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य खेतों में फसलों के साथ बड़े स्तर पर पेड़ लगाना है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है।

ट्विटर पर जारी 'मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना' के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये प्रति पौधा सिक्वोरिटी डिपॉजिट देकर वन विभाग की नर्सरी से 25 से अधिक पौधे खरीदने होंगे। अगर तीन साल बाद 50 फीसदी पौधे जीवित रहते हैं तो किसान को प्रति पौधा 60 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही जमा किया गया सिक्वोरिटी डिपॉजिट भी किसान को वापस कर दिया जाएगा।

### इस योजना से ये होंगे लाभ

इस योजना के अंतर्गत पेड़ लगाने से किसानों को अतिरिक्त आय होगी। इसके साथ ही शीशम, अमरूद, गंभीर, आंवला, महोगनी, सागौन, पीपल, जामुन, कचनार, गुलमोहर, आम नीलगिरी, नीम, कदम, बहेड़ा, पलास आदि के पेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी। ये पेड़ आगे चलकर पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे।

### इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग या वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसानों को मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगानी होगी। जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पौधे किसानों को दे दिए जाएंगे। साथ ही समय समय पर इन पौधों का निरीक्षण भी किया जाएगा। 3 साल बाद यदि 50 फीसदी पौधे सुरक्षित रहते हैं तो अनुदान और सिक्वोरिटी डिपॉजिट की राशि किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी बिहार के वन विभाग की वेबसाइट

[HTTPS://FORESTONLINE.BIHAR.GOV.IN](https://forestonline.bihar.gov.in) से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 0612-2226911 पर फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

## दुधारू पशु खरीदने पर सरकार देगी 1.60 लाख रुपये तक का लोन, यहां करें आवेदन



## दुधारू पशु खरीदने पर सरकार देगी 1.60 लाख रुपये तक का लोन, यहां करें आवेदन

भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर नए प्रयास करती रहती है। जिसके अंतर्गत किसानों को खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसी कड़ी में अब हरियाणा की सरकार किसानों को दुधारू गाय और भैंस पालने पर लोन तथा सब्सिडी की सुविधा प्रदान कर रही है। जिसको देखते हुए सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से पशुपालन के इच्छुक किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे 1.60 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है।

पशु क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गाय या भैंस खरीदने पर किसानों को 7 फीसदी ब्याज देना होता है। यदि किसान समय से अपना ब्याज चुकाते हैं तो इन 7 फीसदी में 3 फीसदी ब्याज सरकार वहन करती है। किसानों को वास्तव में मात्र 4 फीसदी ब्याज का ही भुगतान करना होता है। जिसे किसान अगले 5 साल तक चुका सकते हैं। जिन किसानों के पास खुद की जमीन है और उसमें वो पशु आवास या चारागाह बनाना चाहते हैं, वो भी इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा की सरकार ने भिन्न-भिन्न पशुओं पर भिन्न-भिन्न लोन की व्यवस्था की है। कृषि वेबसाइट के अनुसार, पशु किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके गाय खरीदने पर 40,783 रुपये, भैंस खरीदने पर 60,249 रुपये, सूअर खरीदने पर 16,237 रुपये और भेड़ या बकरी खरीदने पर 4,063 रुपये का लोन मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही मुर्गी खरीदने पर प्रति यूनिट 720 रुपये का लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए किसानों को किसी भी प्रकार की कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होगी। साथ ही किसान भाई पशु क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक के भीतर डेबिट कार्ड के रूप में भी कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत अभी तक हरियाणा के 53 हजार से ज्यादा किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इन किसानों को सरकार के द्वारा 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन मुहैया करवाया जा चुका है। योजना के अंतर्गत दुधारू पशु खरीदने के लिए अभी तक 5 लाख किसान आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 1 लाख 10 हजार किसानों के आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है। जिन किसानों को हाल ही में मंजूरी दी गई है उन्हें भी जल्द से जल्द पशु क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

### पशु क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ये बैंक देते हैं लोन

किसानों को 'पशु क्रेडिट कार्ड योजना' का लाभ देने के लिए सरकार ने कुछ बैंकों का चयन किया है। जिनके माध्यम से किसान जल्द से जल्द अपना 'पशु क्रेडिट कार्ड' बनवा सकते हैं। इनमें सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया है।



## पशु क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, इसके साथ ही लोन लेने के लिहाज से सिविल ठीक होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड ,पेन कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता डिटेल, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।

## ऐसे करें 'पशु क्रेडिट कार्ड' बनवाने के लिए आवेदन

जो भी व्यक्ति 'पशु क्रेडिट कार्ड' बनवाना चाहता है उसे ऊपर बताए गए किसी भी बैंक की नजदीकी शाखा में जाना चाहिए। इसके बाद वहां पर आवेदन पत्र लेकर आवेदन को सावधानी पूर्वक भरें। साथ ही आवेदन के साथ दस्तावेजों की फोटो कॉपी चस्पा करें। ये सभी दस्तावेज बैंक अधिकारी के पास जमा कर दें। आवेदन सत्यापन के एक महीने बाद किसान को पशु क्रेडिट कार्ड दे दिया जायेगा।



# महिला निधि योजना

के अंतर्गत लोन लेने पर  
सरकार देगी 8 प्रतिशत  
ब्याज का अनुदान



## महिला निधि योजना के अंतर्गत लोन लेने पर सरकार देगी 8 प्रतिशत ब्याज का अनुदान

राजस्थान की सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नित नए प्रयास करती रहती है। इसके लिए अब सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के महिला निधि योजना में बड़ा संशोधन किया है। सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि अब सरकार महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को देने वाले लोन पर 8 प्रतिशत का अनुदान देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है।

जानकारी के अनुसार, गहलोट सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 2 साल की समय सीमा पर मिलने वाले 1 लाख रुपये के लोन पर 8 प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान से महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी।

राजस्थान की सरकार पहले भी ऐसी योजनाओं को राज्य में लागू कर चुकी है ताकि महिलायें भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। इनके अलावा महिला उत्थान के लिए कई अन्य योजनाएं भी हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। निकट भविष्य में इनके धरातल पर उतरने की पूर्ण संभावनाएं हैं।

इसके पहले 26 अगस्त 2022 को सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोट ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए 'राजस्थान महिला निधि' की शुरुआत की थी। यह शुरुआत 'महिला समानता दिवस' के मौके पर की गई थी। 'राजस्थान महिला निधि' का लक्ष्य महिलाओं को बेहद आसानी से स्वरोजगार हेतु पर्याप्त मात्रा में लोन उपलब्ध करवाना है।

### इसलिए शुरू की गई थी 'महिला निधि योजना'

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोट ने बताया है कि 'महिला निधि योजना' की शुरुआत महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने, गरीब, सम्पत्तिहीन और सीमान्त महिलाओं की आय बढ़ाने और महिलाओं के कौशल के विकास के लिए की गई है। इससे महिलायें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नति करेंगी। अभी तक राजस्थान में 36 लाख परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं।

राजस्थान के पहले तेलंगाना में भी 'महिला निधि योजना' की स्थापना की गई थी। राजस्थान इस योजना को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इस योजना के अंतर्गत 40 हजार रुपये तक का लोन मात्र 48 घंटे के भीतर मिल जाता है। 40 हजार रुपये से ज्यादा का लोन 15 दिन के भीतर दे दिया जाता है।



## ‘महिला निधि योजना’ के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में रहने वाली सभी महिलायें एवं स्वयं सहायता समूह आवेदन कर सकते हैं। ‘महिला निधि योजना’ के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना आवश्यक है। यह योजना हाल ही में शुरू की गई है इसलिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई गई है। जैसे ही सरकार की तरफ से वेबसाइट की स्वीकृति मिल जाती है तो महिलायें बेहद आसानी से वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी।



# यह राज्य सरकार किसानों की क्षतिग्रस्त फसल को खरीदने के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी देगी



## यह राज्य सरकार किसानों की क्षतिग्रस्त फसल को खरीदने के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी देगी

किसानों को हमेशा किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों प्रचंड गर्मी उसके बाद तेज बारिश से लाखों हेक्टेयर में खड़ी रबी सीजन की फसलें चौपट हो गई हैं। फसल क्षति की पूर्ति के लिए यूपी सरकार के माध्यम से खराब फसल की खरीद सहित कृषि निवेश राहत धनराशि देने की घोषणा की है।

इस वर्ष का मार्च का महीना कृषकों हेत अत्यंत नुकसानदायक साबित हुआ है। बेमौसम बारिश ने मध्य एवं उत्तर भारत में तबाही मचा दी है। फरवरी माह में अचानक तापमान अधिक होने की वजह से सरसों के साथ गेहूं की फसल को भी हानि पहुंच रही थी। परंतु, उसके बाद मार्च की बारिश से किसानों के परिश्रम को पूर्णतय विफल कर दिया है। खेतों में कटाई हेतु तैयार खड़ी गेहूं एवं सरसों के साथ-साथ मसूर व चना की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गईं। किसानों पर विपदा की भांति आई इस संकट के समय में विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों को सहायता धनराशि के तौर पर मुआवजा देने की घोषणा तो कर दी। परंतु, किसान भाइयों हेतु बर्बाद हुई फसल चिंता का कारण बन चुकी है। ऐसे में प्रभावित किसानों की इस समस्या का निराकरण कर दिया गया है। हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने अपने प्रदेश में बारिश एवं आंधी से क्षतिग्रस्त हुई फसलों को खरीने का ऐलान किया है।

**किसानों की आधी से ज्यादा फसल चौपट हो चुकी है**

यदि हम फसल के नुकसान पर नजर डालें तो मार्च के दूसरे पखवाड़े में बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं एवं सरसों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक हानि की अटकलें लगाई जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में हुई फसल हानि के आकलन के अनुरूप कृषि विभाग के अधिकारियों ने 34,137 हेक्टेयर फसल बर्बादी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है।

बेमौसम बारिश से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जनपदों में उन्नाव, हमीरपुर, झांसी, प्रयागराज, चंदौली, आगरा, बरेली, वाराणसी और लखमीपुर खीरी शामिल हैं। सरकार द्वारा कराये गए 15 मार्च तक के सर्वेक्षण में यह पाया गया है, कि मार्च के प्रथम पखवाड़े में मौसम परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से 1.02 लाख किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है।

**बागवानी फसलों को भी झेलना पड़ा है नुकसान**

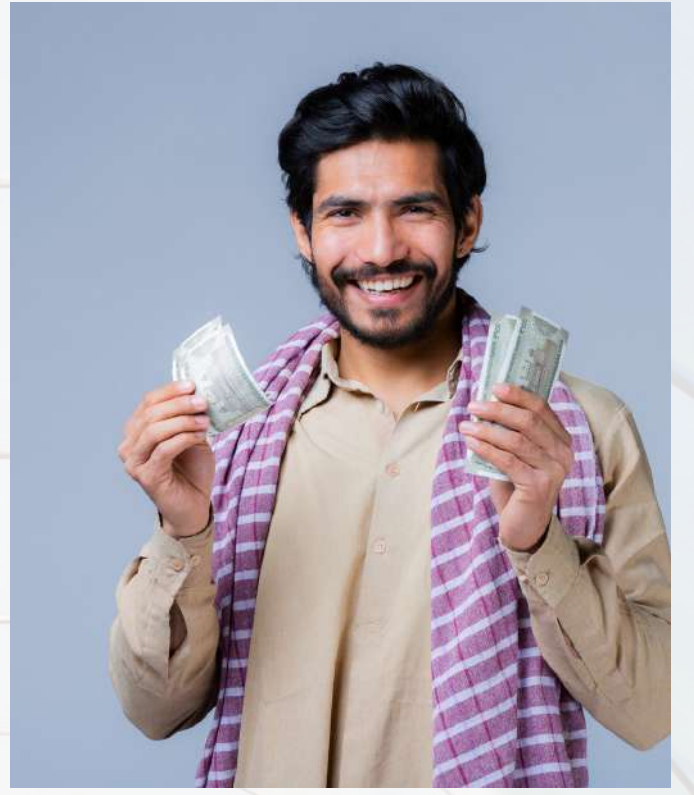
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्च के समापन के दो दिनों में बदली परिस्थितियों से पूरे प्रदेश के कृषि क्षेत्र पर बेकार तरह प्रभावित हुई है। विशेष रूप से अलीगढ़, बरेली, सीतापुर, उन्नाव, सोनभद्र, हमीरपुर, संभल, मुरादाबाद और पीलीभीत में ओलावृष्टि से तैयार कटी हुई फसलें चौपट हुई हैं।



इनमें से विभिन्न जनपदों में आलू की खुदाई चल रही थी। वहीं, आम के पेड़ पर बौर आ रहे थे। परंतु, खेत में सुखाने हेतु रखे हुए आलू तो बर्बाद हुए ही, आम के बौर भी पेड़ों से झड़कर भूमि पर गिर चुके हैं। किसानों के अतिरिक्त बागवान भी आम के उत्पादन के संबंध में काफी चिंतित हैं।

### योगी सरकार ने फसल क्षति का सर्वेक्षण करने के लिए आदेश

किसानों के लिए आफत बनी बेमौसम बारिश का कहर अभी तक जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पहले पखवाड़े में मूसलाधार बारिश के पूर्वानुमान की जानकारी दी गई थी। इधर आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में फसल कटाई एवं नई फसल की बुवाई का कार्य सुचारू है। ऐसी स्थितियों पर ध्यान देते हुए योगी सरकार द्वारा फसल नुकसान का सर्वेक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके आधार पर कृषि निवेश राहत सहायता धनराशि भी मुहैया कराई जाएगी।



**ESCORTS**

जापक करता **फार्मट्रैक 60**  
अथ **16.9** के बड़े टायर में

**55**  
HP किलोवाट

**FARMTRAC**  
**60**  
POWERMAX

**CAC** **T20**

**FARMTRAC**  
एन एच सी सी

# इस योजना के अंतर्गत सरकार

## किसानों को देगी 18 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन



### इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को देगी 18 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन

सरकार लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर ढेरों योजनाएं चला रखी हैं। जिनसे देश के किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने एक और योजना शुरू की है। जिसे 'पीएम किसान एफपीओ योजना' नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसान को एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने के लिए 18 लाख रुपये तक की सहायता देती है। योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 11 किसानों को मिलकर एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाना जरूरी है।

#### क्या है पीएम किसान एफपीओ योजना

किसान एफपीओ योजना को केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए चलाई है। जिसमें खेती बाड़ी से जुड़े बिजनेस शुरू करने के लिए 18 लाख रुपये तक की राशि मुहैया कवाई जाती है। यह राशि आवेदन करने के बाद आगामी 3 साल में सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। इस योजना से जुड़ने पर और भी कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे:- किसान सस्ती दरों पर बैंकों से लोन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत उपज को बेचने के लिए किसानों के लिए आसानी से बाजार उपलब्ध हो जाता है। साथ ही किसान भाई बेहद रियायती दरों पर फर्टिलाइजर, सीड, केमिकल और कृषि यंत्र जैसे जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं।

#### ये लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

आवेदक का कृषि का व्यवसाय होना जरूरी है। इसके साथ ही उसके पास कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। आवेदक किसान उत्पादक संगठन का हिस्सा होना चाहिए। मैदानी क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए, इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन में 100 सदस्य होने चाहिए।

#### आवेदनकर्ता के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी

आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इन सभी दस्तावेजों की जानकारी आवेदन करते समय देनी होगी।

#### ऐसे करें पीएम किसान एफपीओ योजना में आवेदन

जो भी किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाह रहे हैं उन्हें सर्वप्रथम किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह प्रक्रिया ई-नाम पोर्टल के माध्यम से बेहद आसानी से पूरी की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ई-नाम की आधिकारिक वेबसाइट [HTTPS://WWW.ENAM.GOV.IN](https://www.enam.gov.in) पर जाएं। वहां पर ई-नाम का पेज होगा। इस पेज में अपनी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दें। इसके अलावा किसान भाई ई-नाम मोबाइल ऐप और नजदीकी ई-नाम मंडी जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

## बेमौसम बरसात या ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने पर KCC धारक किसान को मिलती है ये सुविधाएं



## बेमौसम बरसात या ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने पर KCC धारक किसान को मिलती है ये सुविधाएं

सरकार किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिनका फायदा उठाकर किसानों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है। अब मध्यम एवं छोटे किसान भी सरकार से मिलने वाली सहायता के कारण बिना किसी चिंता और परेशानी के खेती कर पा रहे हैं। ऐसी ही हम आपको एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे अभी तक लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना को 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले साल 1998 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बेहद आसानी से कृषि कार्यों के लिए लोन मिल जाता है, जिससे किसानों को खाद बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए पैसे की कमी नहीं होती। इसके साथ ही अगर किसान ने KCC लिया हुआ है तो प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने की स्थिति में भी किसानों को बड़ी राहत प्रदान की जाती है।

### ऐसे लें KCC लोन

इस योजना में किसानों को नकद पैसे न देकर क्रेडिट कार्ड पर लोन दिया जाता है। जिससे किसान खेती के लिए कृषि यंत्रों सहित अन्य जरूरी समान की खरीदी समय पर कर पाएं। नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले बैंक इस योजना के तहत किसानों को लोन मुहैया करवाते हैं। जो बेहद रियायती दरों पर होता है। इससे किसान साहूकारों और महाजनों के कर्ज के जाल में फंसने से बच जाते हैं।

इस कार्ड के अंतर्गत लोन लेने के बाद किसान को एक साल के भीतर लोन चुकता करना होता है। लोन चुकता करने के लिए किसानों के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है।

### इतने रुपये का मिलता है लोन

KCC के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाया जाता है। इसके लिए किसान को बैंक में किसी भी प्रकार की जमानत नहीं रखनी होती है। इसके अलावा बैंक 5 साल के लिए 3 लाख रुपये का अल्पकालिक लोन भी देते हैं। इसके लिए किसान को बैंक में कुछ न कुछ जमानत रखनी होती है। क्रेडिट कार्ड जारी करने के 15 दिन के भीतर बैंक द्वारा लोन जारी कर दिया जाता है।

### फसल बर्बाद होने पर किसानों को ऐसे मिलता है प्रोटेक्शन

जब बैंक किसानों को लोन जारी करता है तब सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किसान की फसलों को इश्योरेंस कवरेज भी दिया जाता है। अगर किसान की फसल कीटों से प्रभावित होती है या किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है तो किसान अपना इश्योरेंस क्लेम कर सकता है। इन दिनों देश में प्राकृतिक आपदा के कारण बड़े स्तर पर फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में जिन भी किसानों ने KCC के माध्यम से लोन लिया होगा, वो बेहद आसानी से अपनी नष्ट हुई फसल के लिए इश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं।

# प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को मिलेगा बम्पर मुआवजा, ऐसे करें आवेदन

## प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को मिलेगा बम्पर मुआवजा, ऐसे करें आवेदन

खेती किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमेशा अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। कभी भी मौसम की मार किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। मौसम की बेरुखी के कारण किसानों को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ता है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देश भर में मौसम ने अपना कहर बरपाया है, जिससे लाखों किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई दिनों तक चली बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों को हुआ है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे किसानों को हुए नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सकती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि किसान इस योजना के साथ नहीं जुड़ते। ऐसे में किसानों को सरकार अपने स्तर पर अनुदान देती है ताकि किसान अपने पैरों पर खड़े रह पाएं।

किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार की सरकार ने 'कृषि इनपुट अनुदान योजना' चलाई है। इस योजना के तहत यदि किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो सरकार अनुदान के रूप में किसानों को 13,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह मदद ऐसे किसानों को दी जाएगी जो सिंचित इलाकों में खेती करते हों। इसके साथ ही 'कृषि इनपुट अनुदान योजना' के अंतर्गत असिंचित इलाकों में खेती करने वाले किसानों को फसल नुकसान पर 6,800 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नदियों से आने वाली रेत के कारण फसल चौपट हो जाती है। ऐसे किसानों को फसल नुकसान पर 12,200 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

**कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ये किसान कर सकते हैं आवेदन**

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही किसान के पास खुद की कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होना चाहिए। डीबीटी के माध्यम से अनुदान ट्रांसफर करने में आसानी हो, इसके लिए किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड नंबर से लिंक होना चाहिए।

**योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी**

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आई डी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि होना जरूरी है। इन सभी चीजों का विवरण आवेदन करते समय देना अनिवार्य है।

**कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन**

प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान का अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान भाई बिहार के कृषि विभाग की वेबसाइट [HTTPS://DBTAGRICULTURE.BIHAR.GOV.IN](https://dbtagriculture.bihar.gov.in) / पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन करने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय, वसुधा केंद्र या जन सेवा केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं।

# प्रगतिशील किसान

**मैना चौधरी बागवानी के क्षेत्र में बनीं महिलाओं के लिए मिशाल**



## मैना चौधरी बागवानी के क्षेत्र में बनीं महिलाओं के लिए मिशाल

हरियाणा राज्य के पंचकूला की मैना चौधरी विगत 25 वर्षों से खेती करती आ रही हैं। साथ ही, उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में काफी नाम रोशन किया है। प्रगत व उन्नत विधियों के माध्यम से सब्जी की खेती कर आज मैना चौधरी खूब मोटी आमदनी कमा रही हैं।

खेती-किसानी में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी बढ़ती जा रही है। हालाँकि, महिलाएं पूर्व से ही कृषि कार्यों में अपने परिवार में सहयोग करती थीं। परंतु, आज पूर्ण जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ महिलाएं खेती की दशा एवं दिशा को बदल रही हैं। आपको बता दें कि ऐसी ही महिला किसानों में हरियाणा के पंचकूला की किसान मैना चौधरी भी शामिल हैं। मैना चौधरी आज सीजनल एवं ऑफ सीजनल सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं। इस कार्य में मैना चौधरी को बागवानी विभाग का भी पूरा सहयोग और मदद मिलती है।

### शौक के रूप में खेती से कमा रही मुनाफा

आज के समय मैना चौधरी उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत और मिशाल बन रही हैं, जो बागवानी में अपने बल पर कुछ करना चाहती है। मैना चौधरी को आरंभ से ही खेती किसानी का बेहद शौक था।

इसी शौक को 25 वर्ष पूर्व अपने कार्य में परिवर्तित क दिया। मैना चौधरी का कहना है, कि हम खेती के क्षेत्र में बहुत कुछ नवीन कर सकते हैं। अपने नवाचारों को लेकर किसान भाई-बहनों को आगे बढ़ना चाहिए। यदि सही तरीका मालूम हो तो किसान बहनें भी हर प्रकार की फसल से मोटा और अच्छा खासा उत्पादन उठा सकती हैं।

### मैना चौधरी मौसमी और गैर मौसमी दोनों तरह की सब्जियां उगाती हैं

यह कोई जरूरी नहीं कि नकदी फसलों के द्वारा ही अच्छा मुनाफा कमाया जाता हो। आज के दौर में किसान करेला, टमाटर, लौकी, तोरई, खीरा जैसी सब्जी की फसलों की आधुनिक खेती करके उत्तम पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। मैना चौधरी भी हर प्रकार की मौसम-बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करती हैं। इनका ध्यान केवल वर्षभर खाई जाने वाली सब्जियों की पैदावार पर होता है। बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मैना चौधरी द्वारा पॉलीहाउस भी स्थापित किया जाएगा। अब सब्जियों का विक्रय करने हेतु बार-बार बाजार नहीं जाना पड़ता, बल्कि ये थोक में ही बिक जाती है।

## बागवानी विभाग की तरफ से भी मिलती है मदद

मैना चौधरी का कहना है, कि उन्हें बागवानी विभाग से भरपूर सहायता प्राप्त हो रही है। बागवानी विभाग की टीम कई बार उनके खेत पर मुआयना करने आती रहती है। उन्हें वक्त-वक्त पर नई योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाती है। इन योजनाओं में आवेदन करके मैना चौधरी को खूब लाभ भी हुआ है। इससे बागवानी के खर्चे को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। मैना चौधरी द्वारा अपने खेतों पर सब्जियों सहित नींबू एवं अनार के वृक्ष भी रोपे गए हैं। वो कहती हैं, कि उचित फसल का चयन करके किसान भाई मोटा मुनाफा उठा सकते हैं।



# EURO 45 PLUS 4X4



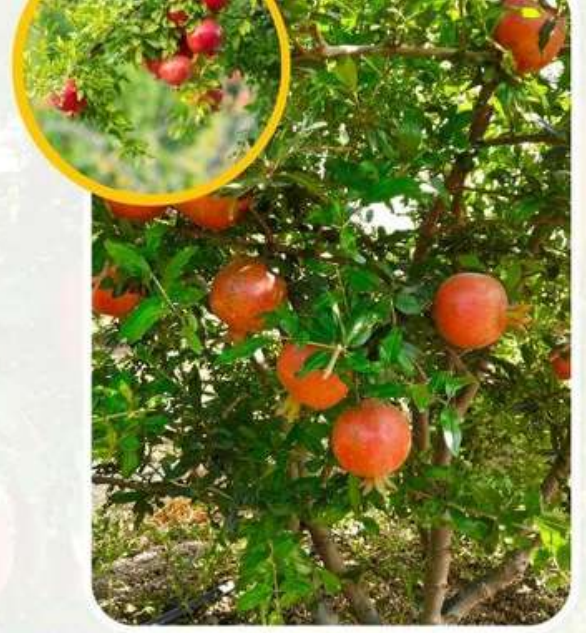
**चारों पहिये करे काम**  
ताकत. सुख्या. गति. आराम

35 kW  
(47 HP)

8+8  
Gear Box



# विदेश से नौकरी छोड़कर आया किसान अनार की खेती से कमा रहा करोड़ों



## विदेश से नौकरी छोड़कर आया किसान अनार की खेती से कमा रहा करोड़ों

राजस्थान राज्य के सिरोही निवासी नवदीप एक सफल किसान के तौर पर उभरके सामने आए हैं। दरअसल, वह प्रति वर्ष 1.25 करोड़ की आय अर्जित कर रहे हैं।

राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के निवासी नवदीप गोलेछा ने कृषि क्षेत्र में एक ऐसा कार्य कर दिया है, जिससे संपूर्ण राजस्थान में उनका नाम रोशन हो रखा है। आज वह कृषि के क्षेत्र में लाखों की आमदनी कर रहे हैं। बता दें, कि नवदीप एक व्यावसायिक परिवार से आते हैं। उन्होंने साल 2011 में वित्तीय अर्थशास्त्र में एमएससी की पढ़ाई इंग्लैंड से संपन्न की है। नवदीप ने उधर ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप पर कार्य करना चालू किया था।

इसी बीच उनके परिवार वाले उनके ऊपर लौटकर भारत आने का दबाव बनाना चालू कर दिया था। नवदीप वर्ष 2013 में अपनी नौकरी को छोड़के भारत वापस लौट आए।

### इतने एकड़ भूमि पर कर रहे अनार का उत्पादन

घर लौटकर आने के उपरांत नवदीप ने रिजॉर्ट चालू करने के विषय में विचार विमर्श किया। परंतु, नवदीप ने पुनः वृक्षारोपण में हाथ आजमाने के विषय में विचार किया। उसके उपरांत पुनः उन्होंने जोधपुर से 170 किलोमीटर दूर सिरोही गांव में 40 एकड़ की भूमि पर कृषि करने के विषय में विचार किया। उन्होंने समकुल 30 एकड़ में अनार के पौधों का वृक्षारोपण किया एवं बाकी 10 एकड़ में पपीता, शरीफा और नींबू के पेड़ लगाने चालू किए। उस समय उनके गाँववाले उनका खूब मजाक बनाते थे। क्योंकि, नवदीप ने विदेश से नौकरी छोड़ खेती किसान की तरफ अपना रुख किया।

### एपीडा से पंजीकरण करा सीधे कर रहे अनार के उत्पादन का निर्यात

नवदीप गोलेछा ने अनार का उत्पादन करने से पूर्व ही सर्वप्रथम क्षेत्र के कृषि विभाग में संपर्क साधा था। नवदीप ने अपनी भूमि की मृदा का परीक्षण करवाया एवं रिसर्च के उपरांत अनार की खेती चालू की थी। जब अनार के फलों की पैदावार चालू होने लगी तो उन्होंने खुद के उत्पादन का निर्यात करने हेतु एपीडा सहित पंजीकरण करावाया साथ ही खुद के उत्पाद को सीधे तौर पर निर्यात करने की मंजूरी ली है। नवदीप नीदरलैंड में खुद के काफी अधिक उत्पादों का निर्यात करते हैं।



# किसान समाचार



**इस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था हेतु मुहैया कराई गई 463 करोड़ रुपए**

## **इस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था हेतु मुहैया कराई गई 463 करोड़ रुपए**

किसानों की दोगुनी आमदनी करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किसानों को सुविधा और राहत दिलाने के लिए 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

राजस्थान सरकार प्रदेश के किसान भाइयों को मजबूती पहुंचाने हेतु लगातार कोशिशें करते रहते हैं। इसके चलते विगत कुछ माहों से राज्य सरकार प्रदेश में स्वयं की समस्त योजनाओं पर कार्य कर लोगों की सहायता कर रही है। हाल ही, में सरकार द्वारा आम जनता के लिए CNG और PNG के मूल्यों में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं राज्य हेतु सरकार नित नए दिन कुछ न कुछ नवीन पहल कर रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला लिया है।

सरकार कितने करोड़ की धनराशि अनुदान स्वरूप किसानों को प्रदान कर रही है

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए डिग्गी, फार्म पौण्ड और सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों हेतु 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही, सरकार की तरफ से अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं, कि इस परियोजना पर शीघ्रता से कार्य चालू किया जाना चाहिए।

सरकार कितने करोड़ की धनराशि अनुदान स्वरूप किसानों को प्रदान कर रही है

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए डिग्गी, फार्म पौण्ड और सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों हेतु 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही, सरकार की तरफ से अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं, कि इस परियोजना पर शीघ्रता से कार्य चालू किया जाना चाहिए।



## सरकार किसको अनुदान मुहैया कराएगी

यदि आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप आसानी से इस सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि उपरोक्त में आपको कहा गया है, कि राज्य में किसानों की सहायता करने के लिए सरकार डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन से संबंधित कार्य हेतु लगभग 463 करोड़ रुपए का खर्चा करने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार द्वारा यह भी कहा गया है, कि इस सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था के तहत एससी, एसटी के गैर लघु-सीमांत किसान भाइयों को तकरीबन 10 प्रतिशत से अतिरिक्त अनुदान की सहायता प्रदान की जाएगी।

बता दें, कि इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी जानकारी प्रदान की गई है। जिससे कि प्रदेश की इस सुविधा के विषय में प्रत्येक किसान भाई को पता चल सके।



## इस राज्य में केंद्र से आई टीम ने गुणवत्ता प्रभावित गेहू का निरीक्षण किया



## इस राज्य में केंद्र से आई टीम ने गुणवत्ता प्रभावित गेहू का निरीक्षण किया

जैसा कि हम जानते हैं, कि मार्च माह में देश के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत बहुत सारे राज्यों में ओलावृष्टि सहित वर्षा हुई थी। इसकी वजह से लाखों हेक्टेयर के रकबे में खड़ी रबी फसल को काफी क्षति पहुंची है।

अब उत्तर प्रदेश के कृषकों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों के समरूप ही गेहू खरीद में ढिलाई दी जा सकती है। दरअसल, इसके लिए यूपी के किसान भाइयों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दरअसल, फसल क्षतिग्रस्त का अंदाजा लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यूपी में कुछ टीमों भेजकर खेतों में हुई फसल हानि का आकलन कराया जा रहा है। उसके बाद यह टीमों सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जिसके उपरांत एमएसपी की घोषणा की करदी जाएगी। इसके साथ ही गेहू खरीद में भी राहत प्रदान करने हेतु मानक निर्धारित किए जाएंगे।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से सोमवार को ही अपनी कई टीमों को उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद में भेजी गई हैं। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, इन टीमों के अंतर्गत डिप्टी सेक्रेटरी के समेत बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं। यह टीमों खेतों में पहुंच कर गेहू की फसल में हुई क्षति का आकलन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रदान करेगी। इसके आधार पर मंत्रालय किसानों से गेहू की खरीदारी करने के लिए मानक निर्धारित करेगा।

### सर्वेक्षण के लिए उत्तर प्रदेश भेजी गई टीमों

मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, विगत शनिवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एमएसपी पर गेहू की खरीद चालू करने की मांग केंद्र से की थी। इसके चलते उसने केंद्र द्वारा गेहू खरीद में एमएसपी को लेकर मानक भी निर्धारित करने को कहा था। यही कारण है, कि केंद्र सरकार को अतिशीघ्र फसल हानि का आकलन करने हेतु उत्तर प्रदेश में अपनी टीमों भेजनी पड़ी हैं।

दरअसल, मार्च के माह में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में ओलावृष्टि के साथ-साथ बारिश हुई थी। इससे लाखों हेक्टेयर भूमि के रकबे में खड़ी रबी फसल को काफी हानि हुई है। विशेष रूप से गेहू की फसल को सर्वाधिक हानि पहुंची है। राजस्थान राज्य में 3 लाख हेक्टेयर में खड़ी गेहू की फसल को बेमौसम बारिश से काफी हानि पहुंची है। इसकी वजह से गेहू की गुणवत्ता भी काफी प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहू खरीद के नियमों में ढील प्रदान की गई है।

### एमएसपी में कितने रुपए की कटौती की जाएगी

मतलब कि इन राज्यों में बारिश से गुणवत्ता प्रभावित गेहू को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। यदि इन तीनों प्रदेशों में गेहू के दाने 6 फीसद से कम टूटे हुए मिलते हैं, उस स्थिति में एमएसपी में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि गेहू के दाने 16 से 18 प्रतिशत के मध्य बेकार मिलते हैं, तब एमएसपी में 31.87 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती की जाएगी।

## गुणवत्ता प्रभावित गेहूं के लिए मानक भी निर्धारित किए गए

इन सब बातों का सीधा सा मतलब है, कि रिपोर्ट पेश होने के उपरांत उत्तर प्रदेश के लिए भी केंद्र सरकार गेहूं खरीद के नियमों में ढिलाई प्रदान कर सकती है। इसके उपरांत यहां के किसान भाई भी पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर गुणवत्ता प्रभावित गेहूं को तय मानक के अनुरूप बेच सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की दिक्कतों को कम करने हेतु खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की भी खरीद करने हेतु सरकारी एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, इसके लिए मानक भी निर्धारित कर दिए गए हैं।



## इस राज्य में दीर्घकालीन

**कृषि कर्ज पर कृषकों को  
5 % प्रतिशत ब्याज अनुदान  
दिया जाएगा**



## इस राज्य में दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर कृषकों को 5 % प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा

दीर्घकालीन कृषि लोन में किसानों को अधिक ब्याज भरना पड़ता है, इस वजह से किसानों पर कर्ज का भार काफी बढ़ जाता है। इस समस्या से थोड़ी राहत अदा करते हुए राज्य सरकार की तरफ से दीर्घकालीन लोन पर 5% प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है।

किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिशों की जा रही हैं। किसानों को नवीन वैज्ञानिक तकनीकों एवं यंत्रों से अवगत करवाया जा रहा है। खेती-किसानी को आसान करने के लिए विभिन्न कृषि योजनाएं जारी की जा रही हैं। खेती में होने वाले खर्च को कम करने हेतु कृषकों को स्थिर कृषि से जोड़ा जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें एकमत होकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ व शक्तिशाली बना रही हैं। इसके चलते किसानों पर आर्थिक जोर डालने वाले कर्ज की मार को भी हल्का करने की पहल जारी हो चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा दीर्घ काल हेतु कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। जिसके लिए ब्याज अनुदान योजना भी लागू की जा रही है।

### ब्याज अनुदान योजना क्या होती है

किसानों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से सहकारी समितियां लघुकालीन एवं दीर्घकालीन के कृषि लोन लागू करते हैं। यह कर्ज काफी कम ब्याज दरों पर प्राप्त होता है। परंतु, विभिन्न बार कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों या व्यक्तिगत समस्याओं के चलते किसान यह कर्जा उचित वक्त पर नहीं चुका पाते।

काफी दीर्घ मतलब लॉन्ग टर्म कर्ज लेने वाले किसानों सहित ऐसे हालात अधिक देखने को मिलते हैं। यही कारण है, कि दीर्घ कालीन कृषि कोर्पोरेट लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मुहैया कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 के बजट में ब्याज मुक्त फसल लोन और ब्याज अनुदान योजना से जुड़ा ऐलान किया है।

### ब्याज अनुदान योजना का लाभ इस प्रकार अर्जित किया जा सकता है

जानकारी के लिए बता दें, कि केवल सहकारी समितियों से ली गई दीर्घकालीन कृषि लोन पर ही ब्याज अनुदान का फायदा प्राप्त होगा। किसान अगर चाहें, तो इस ब्याज अनुदान के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अगर किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने हेतु अपनी सहकारी विकास बैंक की शाखा अथवा जनपद में कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क साध सकते हैं।

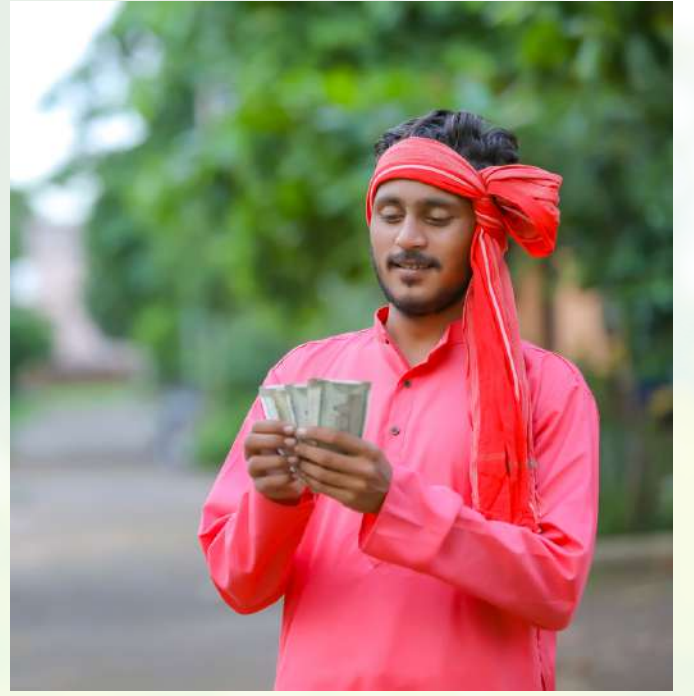
इस दौरान किसान भाइयों को आवेदन पत्र सहित कुछ दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। इनमें बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, खेती की जमीन के कागज आदि शामिल हैं।

## कृषि से जुड़ी इन चीजों पर कर्ज की ब्याज माफ होगी

किसान भाईयों को दीर्घकालीन कृषि लोन पर न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी की जाती थी। जिस पर 5% प्रतिशत अनुदान का ऐलान किया गया था। मतलब कि फिलहाल किसानों को 5% प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

यह लोन कृषि इनपुट्स अथवा बाकी सुविधाओं के लिए किसानों को मुहैया कराया जाता है। इसमें कुआ विनिर्माण, नाली निर्माण, हौज निर्माण, फार्म पौण्ड निर्माण, कृषि बिजली कनेक्शन, सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम, पंपसेट और नलकूप स्थापित करने के लिए लागू किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त कार्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर की खरीद हेतु लंबी अवधि के लिए लोन जारी किए जाते हैं, जिनकी ब्याज धनराशि निजी बैंकों के ब्याज की धनराशि से काफी कम होती है।



**E**  
ESCORTS

आपका सबसे **फार्मट्रैक 60**  
अब **16.9** के बड़े टायर में

उत्पादन  
**55**  
HP तक



**FARMTRAC**  
**60**  
POWERMAX

**CAC**  **T20**

**FARMTRAC**  
एक ही घर, दो ही



# यूपी के इस जिले की हींग को मिला जीआई टैग किसानों में दौड़ी खुशी की लहर

## यूपी के इस जिले की हींग को मिला जीआई टैग किसानों में दौड़ी खुशी की लहर

भारतीय मसालों का स्वाद देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। भारत के विभिन्न प्रकार के मसालों को विदेश में भी अत्यंत पसंद किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय मसालों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं की एक अनोखी पहचान स्थापित की हुई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि हींग जिसको हम सभी अपने भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। हींग को हम भारतीय व्यंजनों में स्वाद को बढ़ाने के लिए उपयोग करने वाला सर्वोत्तम मसाला भी मानते हैं। अपने अनोखे स्वाद और गुणवत्ता की वजह से हींग को वर्तमान में केवल भारतीय मसालों में ही सम्मिलित नहीं किया गया है, इसने विदेशी बाजार के अंदर भी अपनी एक हटकर पहचान स्थापित की है।

बता दें, कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में शामिल हाथरस की हींग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके उपरांत से ही देश-दुनिया के बाजारों में भारतीय हींग की मांग में काफी वृद्धि देखने को मिली है।

### रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न होंगे

मीडिया द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुरूप, विश्व स्तर पर हींग को पहचान हासिल होने के उपरांत यह अंदाजा लगाया जा रहा है, कि भारत के बहुत से युवाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न होंगे। साथ-साथ लोगों की आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा।

साथ-साथ लोगों की आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। बता दें, कि उत्तर प्रदेश की हाथरस हींग को जीआई टैग प्राप्त होने के उपरांत भारतीय व्यापारियों को विदेशों में अपने व्यवसाय को विस्तृत करने में काफी सुगमता रहेगी। अगर हम नजर डालें तो विदेशों में केवल हींग ही नहीं हाथरस की नमकीन, रंग, गुलाल एवं गारमेंट्स आदि भी काफी प्रसिद्ध हैं।

### जीआई टैग होता क्या है

जीआई टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, यह किसी स्थान विशेष की पहचान होता है। सामान्यतः जीआई टैग किसी भी स्थान विशेष के उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान प्रदान करता है। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट-1999 के अंतर्गत भारतीय संसद में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जारी किया गया था। यह किसी प्रदेश को किसी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में मिलने वाली वस्तुओं हेतु विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ऐसी परिस्थितियों में उस विशेष इलाके के अतिरिक्त उस उत्पाद की पैदावार नहीं की जा सकती है।

### जी आई टैग की आवेदन प्रक्रिया

जीआई टैग के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेड मार्क्स के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। चेन्नई में इसका मुख्य कार्यालय मौजूद है। यह संस्था आवेदन के पश्चात इस बात की जांच पड़ताल करती है, कि यह बात कितनी ठीक है। इसके उपरांत ही जीआई टैग प्रदान किया जाता है।

## यूपी की राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आईसीएआर- भारतीय कदन्न (श्री अन्न) अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद का किया सर्वेक्षण



## यूपी की राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आईसीएआर-भारतीय कदन्न (श्री अन्न) अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद का किया सर्वेक्षण

अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न (मिलेट्स) वर्ष 2023 के अवसर पर, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज भाकअनुप-भारतीय कदन्न (श्री अन्न) अनुसंधान संस्थान (भाकअनुसं), हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने संस्थान में स्थापित श्री अन्न के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उनके समक्ष, भारत के अद्वितीय तथा एक बृहत् जननद्रव्य संग्रह एवं श्री अन्न की नवीनतम किस्मों के पुष्प गुच्छों का प्रदर्शन किया गया।

माननीय राज्यपाल ने श्री अन्न को लोकप्रिय करने हेतु संस्थान द्वारा की जा रही कोशिशों, इसके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और प्रशिक्षण की तारीफ की है। उन्होंने कहा है, कि लोग पहले श्री अन्न के विविध उत्पाद तैयार करने की विधि और तकनीकों के विषय में नहीं जानते थे। अब इस संस्थान के माध्यम से श्री अन्न उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय राज्यपाल ने उल्लेख किया कि हमारे देश में किसान उत्पादन संगठन (FPO) काफी महत्वपूर्ण हैं। आज किसान उत्पादक संगठन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बाजार से कैसे संपर्क किया जाए, उत्पाद को ऑनलाइन कैसे बेचा जाए साथ ही उत्पादों का परीक्षण कैसे किया जाए, आदि।

माननीय राज्यपाल के समक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकअनुप) के द्वारा विकसित एवं उद्यमियों को प्रदत्त लाइसेंसीकृत, विविध मूल्यवर्धित उत्पाद और प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित की गईं। इस अवसर पर भाकअनुसं के वैज्ञानिकों तथा राज्यपाल श्रीमती पटेल के साथ एक संवादात्मक बैठक भी आयोजित की गई।

डॉ. (श्रीमती) सीतारा सत्यवती, निदेशक, भाकअनुसं ने माननीय राज्यपाल को संस्थान के मैट्रिक्स, लक्ष्यों एवं दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी दी।

डॉ. संगप्पा, वैज्ञानिक ने कहा कि गांवों में श्री अन्न पर काम करने वाले किसानों, कृषि अधिकारियों, उद्यमियों और अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस संस्थान के द्वारा चार राज्यों में 33 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है।

**श्री अन्न किसानों की आय 3000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 7000-8000 रुपये प्रति क्विंटल हुई है**

श्रीमती रक्षिता लडवंती, सीईओ, अलंदभूताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, कलबुर्गी, कर्नाटक, ने उल्लेख किया कि उनकी सफलता की कुंजी किसान उत्पादक संगठन से कच्चा माल खरीदने हेतु उद्यमियों से जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि स्थानीय महिलाओं को मूल्यवर्धित उत्पादों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसका परिणाम है कि श्री अन्न किसानों की आय 3000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 7000-8000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

डॉ. बीदयाकर राव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यूट्री हब, भाकअनुसं ने बताया कि भाकअनुसं के द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार हेतु मुख्य प्रशिक्षण का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसके आधार पर स्थानीय अधिकारियों एवं अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है।



## NDRI करनाल ने IVF क्लोनिंग तकनीक के जरिए पैदा किए मुरा भैंस के दो क्लोन

वैज्ञानिक निरंतर रूप से किसानों को अच्छी आय कराने के लिए नए नए शोध करते रहते हैं। साथ ही, एनडीआरआई द्वारा आईवीएफ क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से मुरा भैंस के दो क्लोन पैदा किए जा चुके हैं जो कि हाइजेनिक मटेरियल युक्त हैं। इसके माध्यम से पैदा होने वाली भैंस में अधिक दूध की क्षमता और दूध उत्पादन भी काफी ज्यादा रहता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाली भैंस पैदा होती है।

बढ़ती जनसंख्या के चलते देश में दूध की मांग में निरंतर बढ़ोत्तरी होती जा रही है, इसी वजह से समय-समय पर दूध के दाम बढ़ने की खबर भी सुनने को मिलती है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए भारत में सफेद क्रांति एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। किसान और पशुपालकों की आमदनी को अच्छी करने के लिए पशुपालन योजनाओं के जरिए आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाती है। इसी कड़ी में किसानों को दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

साथ ही, पशुपालकों को भी खूब सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वैज्ञानिकों द्वारा शोध करके बेहतरीन नस्लें विकसित करली गई हैं। जिसकी सहायता से अच्छी दूध देने वाली भैंस की नस्लों में सुधार करने पर कार्य किया जाएगा। इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों में नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि अच्छी दूध देने की क्षमता वाले एवं गुणवत्तापूर्ण पशुओं की तादात में वृद्धि की जा सके। भारत की बहुत सी बड़ी संस्थाएं इस पर कार्य कर रही हैं।

वहीं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने आईवीएफ क्लोनिंग तकनीक से सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली मुरा भैंस के दो क्लोन पैदा किए हैं।

### पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता काफी बढ़ जाएगी

मीडिया खबरों के अनुसार, एनडीआरआई करनाल द्वारा आईवीएफ क्लोनिंग तकनीक से मुरा भैंस की उत्पादकता बढ़ाने की कोशिशों में सफलता प्राप्त कर ली गई है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश का पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भी क्लोनिंग की इस तकनीक को राज्य में लेके जा रही है। फिलहाल, निगम के अधिकारियों ने भी यह मान लिया है, कि यह तकनीक पशु उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक भूमिका निभा सकती है। राज्य में इस प्रोजेक्ट को भोपाल के मदरबुल फार्म की आईवीएफ लैब से संचालित किया जाएगा। यहां गाय-भैंस की नस्ल सुधार हेतु इस आईवीएफ तकनीक को उपयोग में लाने की योजना है।

### आईवीएफ लैब में होल्सटीन फ्रीजियन नस्ल की गाय का बछड़ा ने जन्म लिया

आपको इस बात से रूबरू करा दें कि मध्य प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु पहली बार आईवीएफ क्लोनिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। हालाँकि, इससे पूर्व एक आईवीएफ लैब में एंब्रियो के माध्यम होल्सटीन फ्रीजियन नस्ल की गाय का बछड़ा पैदा हो चुका है।



वर्तमान में भोपाल में मौजूद मदरबुल फार्म में जिस तकनीक का उपयोग किया जाना है। इसके क्लोन हाइजेनिक मटेरियल वाले बताए गए हैं। यह पशु की नस्ल सुधार, गुणवत्ता एवं दूध उत्पादन क्षमता को अधिक करने हेतु बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे।

वर्तमान में भोपाल में मौजूद मदरबुल फार्म में जिस तकनीक का उपयोग किया जाना है। इसके क्लोन हाइजेनिक मटेरियल वाले बताए गए हैं। यह पशु की नस्ल सुधार, गुणवत्ता एवं दूध उत्पादन क्षमता को अधिक करने हेतु बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे।

इसको सेल कल्चर भी कहा जाता है। वर्तमान में संवर्धित कोशिका का मिलान स्लॉटर हाउस से मिली ओवरी केंद्रक रहित अंडाणु से कराया जाता है। इस प्रक्रिया के 8 वें दिन भ्रूण बनकर तैयार हो जाता है। इसके उपरांत भ्रूण को भैंस के गर्भाशय के अंदर हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके उपरांत क्लोन बच्चे पैदा होते हैं, जो कि बिल्कुल साधारण भैंस की भांति दिखाई देते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, कि मुर्गा भैंस की दूध उत्पादन क्षमता की मिसाल पूरी दुनिया देती है। यहां तक कि ब्राजील जैसे देश भी आज मुर्गा भैंस की तर्ज पर बड़ी मात्रा में दूध उत्पादन कर रहे हैं। अगर दूध की बात करें तो एक साधारण मुर्गा भैंस प्रतिदिन 15-16 लीटर दूध देती है। यही वजह है, कि मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के डेयरी किसान मुर्गा भैंस को अपनी पहली पसंद मानते हैं।





बनारस के अब तक 22 उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग, अब बनारसी पान भी इसमें शामिल हो गया है

## बनारस के अब तक 22 उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग, अब बनारसी पान भी इसमें शामिल हो गया है

आज तक उत्तर प्रदेश के समकुल 45 उत्पादों को जीआई टैग हांसिल हो चुका है। इन के अंतर्गत 22 उत्पाद बनारस जनपद के ही हैं। बता दें, कि जीआई टैग प्राप्त होने से बनारस के लोगों के साथ-साथ किसान भी काफी प्रसन्न हैं।

अपने मीठे स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान को जीआई टैग मिल गया है। विशेष बात यह है कि इसके अतिरिक्त लंगड़ा आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। विशेष बात यह है कि जीआई टैग प्राप्त होने से किसी भी उत्पाद की ब्रांडिंग बढ़ जाती है। साथ ही किसी खास क्षेत्र से उसकी पहचान भी जुड़ जाती है। जानकारी के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश के समकुल 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें से 22 उत्पाद एकमात्र बनारस के ही हैं। वहीं जीआई टैग मिलने से बनारस की आम जनता और किसानों में भी खुशी की लहर दौड़ रही है। जानकारी के अनुसार, बनारस में उत्पादित किए जाने वाले बैंगन की एक विशेष किस्म 'भंता' को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है।

### बनारसी पान को मिला जीआई टैग

वाराणसी के प्रसिद्ध बनारसी पान को भौगोलिक संकेत टैग मिल गया है। यह टैग प्रदर्शित करता है, कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान के उत्पादों में कुछ ऐसे गुण विद्यमान होते हैं, जो उस मूल की वजह होते हैं। अपने बेहतरीन स्वाद के लिए प्रसिद्ध बनारसी पान विशेष सामग्री का उपयोग करके अनोखे ढंग से बनाया जाता है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित जीआई विशेषज्ञ रजनीकांत ने बताया है, कि बनारसी पान समेत वाराणसी के तीन अतिरिक्त उत्पादों रामनगर भांटा (बैंगन), बनारसी लंगड़ा आम और आदमचीनी चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है।

बनारसी पान को जीआई टैग प्राप्त होने के उपरांत काशी इलाका फिलहाल 22 जीआई टैग उत्पादों का दावा करता है। नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) उत्तर प्रदेश की सहायता से, कोविड चरण के समय 20 राज्य-आधारित उत्पादों के लिए जीआई आवेदन दायर किए गए थे। इनमें से 11 उत्पाद, जिनमें सात ओडीओपी एवं काशी क्षेत्र के चार उत्पाद शामिल हैं। इनको नाबार्ड एवं योगी आदित्यनाथ सरकार की सहायता से इस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हो चुका है।

### बाकी नौ उत्पाद भी सम्मिलित किए जाएंगे

रजनीकांत का कहना है, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जीआई उत्पादों को निर्मित करने में कारीगरों समेत समकुल 20 लाख लोग शामिल होते हैं, जिनमें वाराणसी के लोग भी सम्मिलित हैं। इन उत्पादों का वार्षिक कारोबार 25,500 करोड़ रुपये आंका गया है। उन्होंने यह आशा भी जताई कि अगले माह के अंत तक बाकी नौ उत्पादों को भी देश की बौद्धिक संपदा में शामिल कर लिया जाएगा। इनमें बनारस लाल भरवा मिर्च, लाल पेड़ा, चिरईगांव गुसबेरी, तिरंगी बर्फी, बनारसी ठंडाई आदि सम्मिलित हैं।

## बनारस के कौन-कौन से उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग

इससे पूर्व, काशी एवं पूर्वांचल इलाके में 18 जीआई उत्पाद मौजूद थे। इनमें बनारस वुड कार्विंग, मिजापुर पीतल के बर्तन, मऊ की साड़ी, बनारस ब्रोकेड और साड़ी, हस्तनिर्मित भदोही कालीन, मिजापुर हस्तनिर्मित कालीन, बनारस मेटल रेपोसी क्राफ्ट, वाराणसी गुलाबी मीनाकारी, वाराणसी लकड़ी के लाख के बर्तन और खिलौने, निजामाबाद काली पत्री, बनारस ग्लास शामिल थे। बीड़स, वाराणसी सॉफ्टस्टोन जाली वर्क, गाजीपुर वॉल हैंगिंग, चुनार सैंडस्टोन, चुनार ग्लेज पटारी, गोरखपुर टेराकोटा क्राफ्ट, बनारस जरदोजी और बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट आते हैं।

इसके अंतर्गत 1,000 से अधिक किसानों का पंजीयन किया जाएगा। साथ ही, जीआई अधिकृत उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। नाबार्ड के एजीएम अनुज कुमार सिंह का कहना है, कि आने वाले समय में नाबार्ड इन जीआई उत्पादों को और आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चालू करने जा रहा है। उनका कहना है, कि वित्तीय संस्थान उत्पादन एवं विपणन हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा।





# IIT मद्रास ने मिलावटी दूध की पहचान करने विकसित की मिल्क किट

## IIT मद्रास ने मिलावटी दूध की पहचान करने विकसित की मिल्क किट

आज कल दूध में मिलावट की आए दिन सामने आने वाली खबरों को ध्यान में रखते हुए IIT मद्रास मिल्क किट दूध मिलावट की जानकारी प्रदान करने के लिए एक किट तैयार की है।

पूरे भारत में दूध की बढ़ती मांग के चलते इसमें मिलावट की दिक्कतें भी आम होती जा रही है। स्वस्थ जीवनयापन करने के लिए हर कोई दूध का सेवन करता है। परंतु, बाजार में मिल रहे मिलावटी दूध से स्वास्थ्य ठीक होने की जगह और खराब हो सकती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कि मिलावटी दूध की पहचान करें तो किस तरह करें। आईआईटी मद्रास ने इस परेशानी का समाधान निकाल लिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT MADRAS) के शोधकर्ताओं ने एक 3डी पेपर आधारित पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। जो 30 सैकेंड के भीतर दूध की जांच पड़ताल करके बता देगा कि इसमें क्या तत्व मिला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल दूध के साथ-साथ इस उपकरण से विभिन्न तरह के ड्रिंक्स में मिलावट की पहचान की जा सकती है।

### मिल्क किट किस प्रकार अपना कार्य करती है

दूध की शुद्धता की पहचान करने के लिए आईआईटी मद्रास ने विकसित की मिल्क किट एक 3-D पेपर-आधारित पोर्टेबल डिवाइस है। ये डिवाइस आपको घर बैठे दूध में सोडियम-हाइड्रोजन-कार्बोनेट, नमक, यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या किस तत्व की मिलावट की जानकारी दे देता है।

मिलावटी तत्वों की जानकारी प्रदान करने के लिए डिवाइस में 8 सेक्शन दिए हैं, जो बाजार में सामान्य तौर पर मिलाई जाने वाली घातक चीजों की पहचान करने में सक्षम हैं। शीघ्र सरकार की स्वीकृति के उपरांत इस मिल्क टेस्टिंग डिवाइस को बाजार में मुहैया कराया जाएगा।

### अब कम खर्च और आसानी से होगी मिलावटी दूध की पहचान

सीधी सी बात यह है, कि दूध की पहचान करने के लिए बहुत वर्षों से लैब पर निर्भरता बरकरार है। परंतु लैब में दूध की जांच-पड़ताल करवाने की प्रक्रिया बेहद लंबी एवं खर्चीली होती है। वहीं, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई यह डिवाइस सस्ती है एवं केवल 1 मिली दूध की टेस्टिंग करके 30 सैकेंड में नतीजा सामने दिख जाता है।

फिलहाल आज तक बेंगलोर, जयपुर, गुरुग्राम, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई की भांति के बड़े शहरों में मिलावटी दूध के कई मामले सामने आते हैं। कई बार तो लोग दूध की पहचान नहीं कर पाते एवं जहरीला दूध पीकर बीमार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आईआईटी मद्रास की डिवाइस लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है।

इस डिवाइस के शोधकर्ता डॉ. पल्लव सिन्हा महापात्रा ने कहा है, कि इन मिल्क किट का उपयोग मिल्क पॉइंट, घर, डेयरी, मिल्क कलेक्शन सेंटर पर दूध की जांच-पड़ताल करने के लिए किया जा सकता है। इस मिल्क किट की सहायता से ताजा जूस, मिल्क शेक के साथ जल में भी मिलावटी तत्वों की पहचान की जा सकती है।



## KITS वारंगल ने विकसित

# किया स्वचालित ट्रैक्टर, लागत और मेहनत करेगा कम

## KITS वारंगल ने विकसित किया स्वचालित ट्रैक्टर, लागत और मेहनत करेगा कम

आज के आधुनिक और मशीनीकरण युग में नित नए अविष्कार हो रहे हैं। सभी क्षेत्रों में अच्छे खासे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में KITS वारंगल द्वारा स्वचालित ट्रैक्टर विकसित किया है, जिसका फिलहाल चौथा ट्राइल भी सफलता पूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। बता दें, कि यह ट्रैक्टर लागत प्रभावी है, जो आधुनिक तरीके से किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा।

आधुनिक तकनीकों एवं मशीनों द्वारा तकरीबन हर क्षेत्र में क्रांति का उद्घोष हो चुका है। महीनों तक विलंबित पड़े कार्य फिलहाल चंद मिनटों में पूर्ण हो जाते हैं। खेती-किसानी के कार्यों को भी सुगम एवं सुविधाजनक करने हेतु बहुत सारे यंत्र, टूल्स एवं वाहन तैयार किए जा रहे हैं। जो कि लागत को प्रभावी होने के साथ-साथ किसानों की आमदनी को दोगुना करने में सहायक हैं। इसी ओर काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, वारंगल (KITS-W) ने किसानों के लिए एक ड्राइवरलेस ऑटोमैटिक ट्रैक्टर तैयार किया है, जिसका चौथा ट्राइल भी सफलतापूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है।

**इस स्वचालित ट्रैक्टर की क्या-क्या विशेषताएं हैं**

KITS, वारंगल के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग (CSE) के प्रोफेसर डॉ. पी निरंजन ने बताया है, कि ड्राइवरलेस स्वचालित ट्रैक्टर के लिए 41 लाख रुपये की परियोजना राशि मुहैया कराई गई थी।

इसी कड़ी में इस ट्रैक्टर की विशेषताओं को लेकर इस प्रोजेक्ट के हेड अन्वेषक एमडी शरफुद्दीन वसीम ने जानकारी दी है, कि यह स्वचालित ट्रैक्टर किसानों को सुविधाजनक तरीके से खेतों की जुताई करने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा है, कि यह लागत प्रभावी ट्रैक्टर खेती में किसानों की लागत के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। साथ ही, किसानों की आमदनी को अधिक करने में भी सहायक भूमिका निभाएगी।

विशेषज्ञों के कहने के मुताबिक, इस स्वचालित ट्रैक्टर को विकसित करने का प्रमुख लक्ष्य खेती में मानव परिश्रम को कम करना है। इस ट्रैक्टर को बिल्कुल उसी प्रकार डिजाइन किया गया है। किसान भाई एक रिमोट द्वारा नियंत्रित उपकरण से इस ट्रैक्टर का सफल संचालन कर कृषि कार्य कर सकते हैं।



**असली हीरो की ताकत  
भरोसे की विरासत**



NEW HOLLAND  
AGRICULTURE

## इस तरह संचालित होगा यह ट्रैक्टर

सीएसई के प्रोफेसर निरंजन रेड्डी का कहना है, कि स्वचालित ऑटोमैटिक ट्रैक्टर को कंप्यूटर गेम की भांति ही एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन की सहायता से संचालित कर सकते हैं। इस स्वचालित ट्रैक्टर में लाइफ फील्ड से डेटा एकत्रित करने हेतु विशेषज्ञों ने सेंसर भी स्थापित किए हैं, जो कि किसी जगह विशेष पर कार्य करने हेतु तापमान एवं मृदा की नमी का भी पता करने में सहायता करेंगे। इससे मृदा की खामियों के विषय में भी जाँच करके डेटा एकत्रित करने में भी सुगमता रहेगी।



# मिर्जागालिब से लेकर बॉलीवुड के कई अभिनेता इस 200 साल पुराने दशहरी आम के पेड़ को देखने पहुँचे हैं



## मिर्जा गालिब से लेकर बॉलीवुड के कई अभिनेता इस 200 साल पुराने दशहरी आम के पेड़ को देखने पहुँचे हैं

पुरे विश्व में स्वयं की भीनी-सोंधी खुशबू एवं मीठे स्वाद की वजह से प्रसिद्ध दशहरी आम की खोज 200 वर्ष पूर्व ही हुई थी। लखनऊ के समीप एक गांव में आज भी दशहरी आम का प्रथम पेड़ उपस्थित है साथ बेहद प्रसिद्ध भी है।

आम तौर पर लोग गर्मी के मौसम की वजह से काफी परेशान ही रहते हैं। परंतु, एक ऐसा फल है, जिससे गर्मियों का मजा दोगुना कर देती हैं। उस फल का नाम है आम जिसको सभी फलों का राजा बोला जाता है। जी हां, भारत में आम की बागवानी बड़े स्तर पर की जाती है। भारत की मिट्टी में आम की हजारों किस्मों के फल स्वाद लेने को उपस्थित हैं। लेकिन यदि हम देसी आम की बात करें तो इसकी तरह स्वादिष्ट फल पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल पाएगा। सभी लोगों की जुबान पर दशहरी आम का खूब चस्का चढ़ा हुआ है। यूपी में ही दशहरी आमों की पैदावार होती है। बता दें कि केवल यहीं नहीं अन्य देशों में भी इस किस्म के आमों का निर्यात किया जाता है। साथ ही, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि दशहरी आम का नामकरण एक गांव के नाम के आधार पर हुआ था।

### इस आम का नाम दशहरी आम क्यों रखा गया था

यूपी के लखनऊ के समीप काकोरी में यह दशहरी गांव मौजूद है। ऐसा कहा जाता है, कि दशहरी गांव के 200 वर्ष प्राचीन इस वृक्ष से सर्वप्रथम दशहरी आम प्राप्त हुआ था। ग्रामीणों से मिलकर इस आम का नामकरण गांव दशहरी के नाम पर हुआ था। वर्तमान में 200 वर्ष उपरांत भी ना तो इस दशहरी आम के स्वाद में कोई बदलाव आया है और ना ही वो पेड़, जिससे विश्व का प्रथम दशहरी आम प्राप्त हुआ था।

### इस पेड़ के आम आखिर क्यों नहीं बेचे जाते

फिलहाल, दशहरी आम लखनऊ की शान और पहचान बन चुका है। देश के साथ-साथ विदेशी लोग भी इसका स्वाद चखते हैं। हर एक वृक्ष द्वारा काफी टन फलों की पैदावार हांसिल होती है। परंतु, विश्व का पहला दशहरी आम देने वाला पेड़ अपने आप में भिन्न है। वर्तमान में 200 वर्ष उपरांत भी यह वृक्ष भली-भांति अपनी जगह पर स्थिर है।

आम के सीजन की दस्तक आते ही इस बुजुर्ग वृक्ष फलों के गुच्छे लद जाते हैं। परंतु, तेवर ही कुछ हटकर है, कि इस वृक्ष का एक भी फल विक्रय नहीं किया जाता है। मीडिया खबरों के मुताबिक, दशहरी गांव में इस आम के पेड़ को नवाब मोहम्मद अंसार अली ने रोपा था और आज भी उन्हीं के परिवारीजन इस पेड़ पर स्वामित्व का हक रखते हैं। इसी परिवार को पेड़ के सारे आम भेज दिए जाते हैं।

### दशहरी आम कैसे पहुँचा मलीहाबाद

दशहरी गांव के लोगों का कहना है, कि बहुत वर्ष पूर्व इस दशहरी आम की टहनी को ग्रामीणों से छिपाकर मलीहाबाद ले जाया गया। जब से ही दशहरी आम मलीहाबादी आम के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ग्रामीणों की श्रद्धा को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वह इसको एक चमत्कारी वृक्ष मानते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, कुछ वर्ष पूर्व यह वृक्ष पूर्णतः सूख गया था। समस्त पत्तियां पूरी तरह झड़ गई थीं। परंतु, वर्तमान में सीजन आते ही 200 साल पुराना यह वृक्ष आम से लद जाता है।

## मिर्जा गालिब भी इस दशहरी आम के मुरीद रहे हैं

जानकारी के लिए बता दें, कि दशहरी गांव फिलहाल मलीहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मलीहाबाद के लोगों का कहना है, कि कभी मिर्जा गालिब भी कोलकाता से दिल्ली की यात्रा किया करते थे। तब मलीहाबादी आम का स्वाद अवश्य चखा करते थे। वर्तमान में भी बहुत से सेलेब्रिटी दशहरी आम को बेहद पसंद करते हैं। दशहरी गांव के लोगों का कहना है, कि भारतीय फिल्म जगत के बहुत से अभिनेता इस वृक्ष को देखने गांव आ चुके हैं। दूसरे गांव से भी लोग इस वृक्ष को देखने पहुंचते हैं। इसकी छांव के नीचे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं लोग इस पेड़ की यादों को तस्वीरों में कैद करके ले जाते हैं।





# 15,000 रुपये का मुआवजा

बेमौसम बरसात तथा ओलावृष्टि से बर्बाद  
हुई फसल पर किसानों को मिलेगा



बेमौसम बरसात तथा ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल पर किसानों  
को मिलेगा 15,000 रुपये का मुआवजा

इस साल देश में मार्च के महीने में जमकर बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई है। जिसके कारण किसानों का जमकर नुकसान हुआ है। फसलें खेतों में बिछ गई थीं और बहुत सारी फसलें सड़कर खराब हो गई थीं। इसको देखते हुए अब हरियाणा की सरकार किसानों को मुआवजा देने जा रही है। हरियाणा की सरकार ने दोबारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है ताकि जिन भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वो फिर से मुआवजे की मांग कर सकें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य के अलग-अलग इलाकों में फसल नुकसान के आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सरकार ने किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा है।



हरियाणा के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली तैयार की गई है। जिसके आधार पर नुकसान के आकलन और सत्यापन के बाद किसानों राहत प्रदान की जाएगी। गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद मई के महीने के अंत तक किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी।



अधिकारियों ने बताया है कि जिन किसानों की फसलों का बीमा नहीं था, उन किसानों की फसलों का 75 फीसदी नुकसान होने पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन फसलों को 50 से 75 फीसदी तक नुकसान हुआ है उनको 12 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा।



साथ ही जिन किसानों की फसलों का बीमा है उनके नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। इसके लिए किसान को नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी को मुहैया करवानी होगी। फसल कटाई एक बाद खेत में सुखाने के लिए रखी हुई फसल का भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी बीमा कंपनी करेगी।



# जर्दालु आम को समस्त राज्यपाल व LG को उपहार स्वरूप भेजेगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय

## जर्दालु आम को समस्त राज्यपाल व LG को उपहार स्वरूप भेजेगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय

बिहार राज्य के भागलपुर जनपद को जर्दालु आम की वजह से ही प्रसिद्धि मिली है। बता दें, कि भागलपुर में सर्वाधिक जर्दालु आम के ही बाग हैं। जर्दालु आम एक अगोती किस्म है। इसी कड़ी में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह निर्णय किया है, कि इस बार वह देश के समस्त राज्यपाल एवं उप राज्यपालों के लिए जर्दालु आम भेजा जाएगा। मतलब कि राज्यपाल समेत राजभवन के अधिकारियों द्वारा भी इसका स्वाद लिया जाएगा। साथ ही, विशेषज्ञों ने कहा है, कि कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से जर्दालु आम का विपणन और ब्रांडिंग करने हेतु निर्णय लिया गया है। अब हम यह जानेंगे कि जर्दालु आम में ऐसी कौनसी विशेषता है, जिसके चलते इसको भारत के समस्त राजभवनों को उपहार के तौर पर दिए जाने का फैसला लिया गया है।

बिहार राज्य के भागलपुर जनपद को जर्दालु आम की वजह से ही प्रसिद्धि मिली है। बता दें, कि भागलपुर में सर्वाधिक जर्दालु आम के ही बाग हैं। जर्दालु आम एक अगोती किस्म है। इसी कड़ी में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह निर्णय किया है, कि इस बार वह देश के समस्त राज्यपाल एवं उप राज्यपालों के लिए जर्दालु आम भेजा जाएगा। मतलब कि राज्यपाल समेत राजभवन के अधिकारियों द्वारा भी इसका स्वाद लिया जाएगा। साथ ही, विशेषज्ञों ने कहा है, कि कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से जर्दालु आम का विपणन और ब्रांडिंग करने हेतु निर्णय लिया गया है। अब हम यह जानेंगे कि जर्दालु आम में ऐसी कौनसी विशेषता है, जिसके चलते इसको भारत के समस्त राजभवनों को उपहार के तौर पर दिए जाने का फैसला लिया गया है।

### जर्दालु आम में कितना वजन होता है

भागलपुर जनपद को जर्दालु आम की वजह से ही जाना जाता है। भागलपुर में सर्वाधिक जर्दालु आम के बाग पाए जाते हैं।

इसको आम की एक अगोती प्रजाति है। वैसे तो आम में मंजर बसंत के उपरांत आने चालू हो जाते हैं। परंतु, इसमें जनवरी माह से ही मंजर आने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि 20 फरवरी के उपरांत टिकोले आम का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि जून माह से पकने चालू हो जाते हैं। हालांकि, इससे पूर्व यह सेवन करने योग्य बाजार में आ जाते हैं। इस आम आकार भी अन्य किस्मों की तुलना में काफी बड़ा होता है। बता दें, कि इसके एक आम का वजन 200 ग्राम से ज्यादा होता है। साथ ही, इसका छिलका थोड़ा मोटा भी होता है। इस वजह से लोग इसको अंचार लगाने में भी बेहद इस्तेमाल किया करते हैं।

### 25 टन आम का उत्पादन केवल एक हेक्टेयर के बगीचे से होता है

जर्दालु आम को उसके रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। पकने के उपरांत जर्दालु आम का रंग हलका पीला एवं नारंगी हो जाता है। अब इस स्थिति में लोग इसको सहजता से पहचाना जा सकता है। इसमें तकरीबन 67 फीसद गुदा रहता है। रेशा तो बिल्कुल मौजूद नहीं होता है। किसान भाई इसके एक पेड़ से एक सीजन में 2000 फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। एक हेक्टेयर के बाग से 25 टन आम का उत्पादन मिलता है।

बता दें, कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इससे पूर्व भी बहुत सारे नेताओं एवं संवैधानिक पद पर विराजमान लोगों को जर्दालु आम भेजा जा चुका है। बीते वर्ष इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति को जर्दालु आम उपहार में दिया था। साथ ही, इसको विदेशों में भी नामचीन लोगों को उपहार स्वरूप दिया जाता रहा है।

# मुरैना की गजक और रीवा के सुंदरजा आम के बाद अब कांगड़ा चाय को मिला GI टैग



## मुरैना की गजक और रीवा के सुंदरजा आम के बाद अब कांगड़ा चाय को मिला GI टैग

चाय की मांग देश के साथ साथ विदेशों तक हो रही है। भारत के हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय विदेशों तक प्रसिद्ध हो गई है। कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ के जरिए जीआई (GI) टैग हांसिल हुआ है। अब इसकी वजह से यूरोपीय संघ देशों में कांगड़ा चाय को अच्छी खासी प्रसिद्धि मिली है।

आजकल केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पाद अपना परचम लहरा रहे हैं। देश के संतरा, चावल, आम, सेब और गेहूँ के अतिरिक्त बहुत सी अन्य फल सब्जियों को विदेशी पटल पर पसंद किया जाता है। दार्जिलिंग की चाय भी बेहद मशहूर होती है। फिलहाल, हिमाचल प्रदेश की चाय ने विदेशों में भी अपनी अदा दिखा रही है। कांगड़ा की चाय अपनी एक पहचान बना रही है। बता दें कि हिमाचल की कांगड़ा चाय को विदेश से जीआई (GI) टैग मिला है। इससे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल की कौन सी चाय को जीआई टैग मिला है।

### मुरैना की गजक और रीवा के सुंदरजा आम के बाद अब कांगड़ा चाय को मिला जीआई टैग

हाल ही में मुरैना की गजक एवं रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल गया है। फिलहाल, विदेश से हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। यूरोपीय संघ के स्तर से कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। इसका यह लाभ हुआ है, कि कांगड़ा की चाय को भारत के अतिरिक्त विदेश में भी अच्छी पहचान स्थापित करने में सहायता मिलेगी। विदेशों तक इसकी मांग बढ़ने से इसकी खपत भी ज्यादा होगी। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो जाएगी।

### हिमाचल की कांगड़ा चाय को किस वर्ष में मिला इंडियन जीआई टैग

आपको बता दें कि असम और दार्जिलिंग में बहुत बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी बड़े इलाके में चाय की खेती की जाती है। हिमाचल में चाय की खेती ने वर्ष 1999 में काफी तेजी से रफ्तार पकड़ी थी। बढ़ते उत्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में इसको भारतीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बता दें, कि चाय की खेती समुद्री तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है।

### इसमें भरपूर मात्रा पोषक तत्व पाए जाते हैं

हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय में पोषक तत्वों की प्रचूर मात्रा पाई जाती है। बता दें, कि इसकी पत्तियों में लगभग 3 प्रतिशत कैफीन, अमीनो एसिड और 13 फीसद कैटेचिन मौजूद रहती है। जो कि मस्तिष्क को आराम पहुंचाने का कार्य करती है। खबरों के अनुसार, कांगड़ा घाटी में उल्लोंग, काली और सफेद चाय का उत्पादन किया जाता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बहुत से जगहों पर भी कांगड़ा चाय उगाई जाती है।



## जीआई टैग का क्या मतलब होता है

किसी भी राज्य में यदि कोई उत्पाद अपनी अनूठी विशेषता की वजह से देश और दुनिया में अपना परचम लहराने लगे तब भारत सरकार अथवा विदेशी सरकारों द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है। बता दें कि इसको प्रमाणित करने के कार्य को जीआई टैग मतलब कि जीओ ग्राफिकल इंडीकेटर के नाम से बुलाया जाता है।



आपका चहेता **फार्मट्रैक 60**  
आब **16.9** के बड़े टायर में

उत्पादित  
**55**  
HP तक



**FARMTRAC**  
**60**  
POWERMAX



**FARMTRAC**  
एक ट्रेक्टर, नौ जीए

# फर्जीवाड़ा करने वाले अपात्र



## किसानों को सूची से किया गया बेदखल

### फर्जीवाड़ा करने वाले अपात्र किसानों को सूची से किया गया बेदखल

महाराष्ट्र कृषि विभाग द्वारा नकली बीमा की जानकारी करने के लिए बेहद सजग सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में यह जानकारी प्राप्त हुई है, कि 82,338 आवेदकों में से 8,674 लोगों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे अपात्र किसानों की छटनी के बाद अब मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) में घपलों की खबर सुनने को मिल रही है। बताया जा रहा है, कि आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत बागवानी फसलों के बीमा का फायदा लेने हेतु किसानों द्वारा अवैध तरीके से आवेदन किया गया है। जिसकी जांच पड़ताल करने के उपरांत अपात्र घोषित कर दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन हेतु बीमित बागवानी फसलों की सच्चाई पता करने के लिए सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। सर्वेक्षण में यह पता चला है, कि बीमा का फायदा लेने के लिए किसानों ने फर्जी लीज डीड का इस्तेमाल किया है। विशेष बात यह है, कि जिन फसलों के बीमा हेतु फर्जी लीज डीड का इस्तेमाल किया गया था, वह उस खेत में उपस्थित ही नहीं थी।

#### केंद्र सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी कितने करोड़ है

जिसके उपरांत महाराष्ट्र कृषि विभाग द्वारा नकली बीमा की जानकारी करने के लिए सजग सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के अंतर्गत जानकारी मिली है, कि 82,338 आवेदकों में से 8,674 लोगों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है।

जानकारी के अनुसार, सोलापुर जनपद में सर्वाधिक 2715 मामले फर्जी पकड़े गए हैं। इसके उपरांत सांगली में 1395 वहीं जलगांव में 744 मामले पाए गए। खबरों के अनुसार, अधिकांश जनपदों में फर्जी मामले सामने आए हैं। उधर, प्रीमियम में किसानों की भागीदारी लगभग 9.07 करोड़ रुपये थी। वहीं, राज्य एवं केंद्र सरकार की संयुक्त भागीदारी 31.77 करोड़ रुपये है।

#### अवैध रूप से 42 करोड़ रुपए का फायदा उठाया

जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों हरियाणा में पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़े की खबर देखने को मिली थी। यहां पर पेंशनधारी, ज्यादा जोत वाले किसान एवं करदाता भी फर्जी दस्तावेजों के उपयोग से पीएम किसान का फायदा उठा लिए थे। इन लोगों द्वारा 42 करोड़ रुपए की धनराशि बहुत सी किस्तों में उठाई थी। हालांकि, मसला सामने आने के बाद कुछ ही किसान इन रुपयों को वापस लौटा पाए हैं। अब सरकार द्वारा इन कृषकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।



# औषधीय खेती



**इन फूलों का होता है औषधियां बनाने में इस्तेमाल, किसान ऐसे कर सकते हैं मोटी कमाई**

## इन फूलों का होता है औषधियां बनाने में इस्तेमाल, किसान ऐसे कर सकते हैं मोटी कमाई

रबी की फसलों की कटाई का दौर चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद खेत खाली हो जाएंगे। इस बीच किसान ऐसी फसलों का चयन कर सकते हैं जो कम समय में ज्यादा कमाई दे सकें। इस कड़ी में हम आपको ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खेती करके किसान कम समय में मोटी कमाई कर सकते हैं। फूलों की खेती की तरफ बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए कई राज्यों की सरकारें फूलों की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी भी मुहैया करवाती हैं।

गर्मियों में बचे हुए समय में किसान भाई ग्लेडियोलस के फूलों की खेती बेहद आसानी से कर सकते हैं। यह फूल औषधीय गुणों से युक्त होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल औषधियां बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही ग्लेडियोलस के फूलों का इस्तेमाल कट फ्लॉवर्स, क्यारियों, बॉर्डर, बागों और गमलों की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। बाजार में इन दिनों इस फूल की जबरदस्त मांग है।

### बाजार में उपलब्ध ग्लेडियोलस की उन्नतशील प्रजातियां

वैसे तो ग्लेडियोलस की 10 हजार से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां मशहूर हैं, जिनकी खेती भारत के उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में की जाती है।

इनमें से स्नो क्वीन, सिल्विया, एपिस ब्लासमें, बिस् ग्लोरी, टेबलर, जैक्सन लिले, गोल्ड बिस्मिल, रोज स्पाइटर, कोशकार, लिंगे न डे, पैट्रीसिया, जार्ज मैसूर, पेंटर पियर्स, किंग कीपर्स, किलोमिंगो, क्वीन, अग्नि, रेखा, पूसा सुहागिन, नजराना, आरती, अप्सरा, सोभा, सपना एवं पुनमें जैसी प्रजातियां बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाती हैं।

### भूमि की तैयारी और बुवाई

भूमि को तैयार करते वक्त मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। ग्लेडियोलस की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य होना चाहिए। साथ ही ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जहां सूरज की पर्याप्त रोशनी रहती हो। साथ पानी निकास की उचित व्यवस्था हो।

ग्लेडियोलस की खेती के लिए जमीन की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी को भुरभुरा होने तक छोड़ दें। ग्लेडियोलस की फसल कंदों के रूप में बोई जाती है। जिसे अप्रैल तथा अक्टूबर में बोया जा सकता है। एक हेक्टेयर भूमि पर बुवाई के लिए लगभग 2 लाख कंदों की जरूरत होती है। कंदों की बुवाई कतार में करनी चाहिए। कंद को 5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए, साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रहनी चाहिए।

## सिंचाई का प्रबंधन

खेत में पहली सिंचाई घनकंदों के अंकुरण के बाद करनी चाहिए। इसके बाद गर्मियों में 5-6 के बाद सिंचाई करते रहें। यदि यह फसल आपने सर्दियों के मौसम में बोई है तो सिंचाई 10-12 दिन के अंतराल में करें। सिंचाई के वक्त ध्यान रखें की पानी खेत में जमा न होने पाए। साथ ही जब फसल पीली हो जाए तब सिंचाई बंद कर दें।

## फूलों के कटाई का समय

फूलों की कटाई पूरी तरह से ग्लेडियोलस की किस्मों पर निर्भर करती है। अगेती किस्मों में कंदों की बुवाई के लगभग 60-65 दिन बाद कटाई शुरू हो जाती है। जबकि मध्य किस्मों 80-85 दिनों बाद तथा पछेती किस्मों में 100-110 दिनों बाद फूलों की कटाई प्रारंभ हो जाती है।

## बाजार में है ग्लेडियोलस के फूलों की जबरदस्त मांग

चूंकि इन फूलों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है, इसलिए हर समय बाजार में इनकी मांग बनी रहती है। ग्लेडियोलस के फूलों का ज्यादातर उपयोग शादियों और होटलों में सजावट के लिए किया जाता है। इसके साथ ही गुलदस्ते बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए किसान भाई इसकी खेती करके फूलों को ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं और बंपर मुनाफा कमा सकते हैं।



# पशुपालन-पशुचारा



## इन पशुपालन में होता है जमकर मुनाफा

### इन पशुपालन में होता है जमकर मुनाफा

देश में किसानों के लिए खेती बाड़ी के साथ-साथ पशुपालन भी एक मुख्य व्यवसाय है। इसलिए देश के ज्यादातर किसान अपने घरों में पशु जरूर पालते हैं ताकि उन्हें खेती के अलावा कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके। इन दिनों केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि पशुपालक अपने पैरों पर खड़े हो सकें। किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं लॉन्च की हैं। जिनमें किसानों को पशुपालन करने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। आज हम आपको ऐसे पशुपालन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से जल्द से जल्द अच्छा पैसा कमाया जा सकता है।

#### बकरी पालन

बकरी पालन में बेहद कम निवेश की जरूरत होती है। यह पशुपालन कम पूंजी के साथ भी शुरू किया जा सकता है। ज्यादातर किसान दूध उत्पादन के लिए बकरियों को पालते हैं। इसके अलावा मांस उत्पादन में भी बकरियों का अहम रोल है। देश में बकरे के मांस की काफी मांग रहती है। इस हिसाब से किसान बकरी पालन करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसकी शुरुआत किसान भाई 2 बकरियों और एक बकरे के साथ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे-जैसे मुनाफा होता जाए, वैसे-वैसे निवेश बढ़ाते जाएं।

#### मुर्गी पालन

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक लोकप्रिय व्यवसाय बनता जा रहा है। मुर्गियों का पालन अंडों के लिए और मांस के लिए किया जाता है। जिसकी बाजार में हमेशा मांग रहती है। बढ़ी हुई मांग को देखते हुए किसान अलग-अलग तकनीकों का प्रयोग करके मुर्गी पालन कर रहे हैं, जिससे उन्हें बंपर मुनाफा होता है। सरकार किसानों को बैकयार्ड में मुर्गी पालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार की यह पहल लोगों को काफी पसंद आ रही है। अगर किसानों के अगल-बगल या आगे-पीछे कहीं भी खाली जमीन पड़ी होती है तो किसान भाई वहां पर आसानी से मुर्गी पालन प्रारंभ कर सकते हैं। इससे किसानों को मुर्गी पालन में ज्यादा लागत नहीं आती और मुर्गियों की देखरेख के कारण अधिक मात्रा में अंडे और मांस का उत्पादन किया जाता है।

#### मछली पालन

इन दिनों मुर्गी पालन के साथ-साथ मछली पालन भी ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इसके लिए भी सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए सरकार मछली पालन के लिए भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है।



जिससे लोग इस व्यवसाय की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। किसान इन दिनों कतला, रोहू तथा मृगल जैसी मछलियों का पालन करते हैं। इनके अलावा विदेशी कार्प मछलियों में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प जैसी मछलियों का पालन किया जा रहा है। मछलियों का प्रयोग मांसाहारी भोजन में किया जाता है। इसके अलावा मछलियों से तेल समेत अन्य कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए किसान भाई मछली पालन करके जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं।

## भैंस और गाय पालन

भैंस और गाय का पालन मुख्यतः दूध की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा पशुपालन है जिसमें थोड़ा बहुत पूंजी की भी जरूरत होती है। ऐसे में सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को पूंजी उपलब्ध करवा रही है ताकि किसानों को भैंस और गाय पालन के लिए पैसों की कमी न आए। आजकल बाजार में दूध की बढ़ती हुई मांग के कारण किसान भाई भैंस और गाय पालन में रुचि दिखा रहे हैं। जिससे उन्हें जमकर मुनाफा हो रहा है।





# काऊ मिल्क प्लांट करोड़ों के खर्च से तैयार खड़े होने के बावजूद भी किसान दूध बेचने को परेशान

## काऊ मिल्क प्लांट करोड़ों के खर्च से तैयार खड़े होने के बावजूद भी किसान दूध बेचने को परेशान

आज हम आपको इस लेख में एक ऐसे काऊ मिल्क प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसमें करोड़ों की लागत लगाने पर कन्नौज मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर तिर्वा क्षेत्र के बढनपुर वीरहार गांव में लगभग 8 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। 140.39 करोड़ रुपये के खर्चा से यह प्लांट 2016 में प्रस्तावित हो चुका था एवं 2018 में निर्मित होकर तैयार हो चुका है।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद के तिर्वा क्षेत्र में करोड़ों के खर्चा से बना काऊ मिल्क प्लांट बजट की कमी के चलते बंद होने की स्थिति पर आ चुका है। यह भी कह सकते हैं। विगत 6 माह से काऊ मिल्क प्लांट बंद पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसी भी मिल्क प्लांट से उत्तम एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह प्लांट 2018 में बनकर तैयार हो चुका था। इस प्लांट में विदेशों से एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक मशीनें स्थापित कर दी गई थीं। आसपास के तकरीबन 15 जनपदों के किसानों को इस प्लांट से अच्छा मुनाफा मिल रहा था।

### काऊ मिल्क प्लांट 2018 में बनकर तैयार हो चुका है

काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर तिर्वा क्षेत्र के बढनपुर वीरहार गांव में करीब 8 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। इस प्लांट को 2016 में लगभग 140.39 करोड़ रुपये के खर्चा से शुरू किया जो कि 2018 में निर्मित हो चुका था। उसके बाद इसका 2019 में उद्घाटन कर के इसको चालू कर दिया गया था। इस काऊ मिल्क प्लांट की एक सर्वोच्च विशेषता यह है, कि इसमें केवल गाय का ही दूध लिया जाता है। यहां दूध से दही, घी एवं पनीर समेत विभिन्न अन्य उत्पाद भी निर्मित किए जाते थे। जिसमें ट्रेड पैकिंग का उपयोग किया जाता था।

**प्लांट हर दिन 1 लाख लीटर दूध भंडार के लिए समर्थ है**

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि इस प्लांट में हर दिन 1 लाख लीटर दूध भंडारण की शक्ति होती है। प्लांट में अत्याधुनिक मशीनों के सहयोग से तकरीबन 6 माह तक दूध पूर्णतय सुरक्षित रह सकता था। कन्नौज जनपद के समीपवर्ती लगभग 15 जनपदों के किसान इस प्लांट के साथ जुड़कर अपने दूध का कारोबार काफी अच्छे तरीके से कर रहे थे। परंतु, प्लांट में आरंभ से ही दिक्कत परेशानियाँ रही हैं। प्लांट निर्मित होने के एक वर्ष बाद तक तो प्लांट शुरू नहीं हुआ है। परंतु, जब शुरू हुआ तो जैसे-तैसे तत्कालीन अधिकारी इसको धक्का देके चलाते रहे।

**प्लांट पर प्रति माह 40 से 50 लाख रुपए का खर्च किया है**

बता दें, कि हर महीने 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा होता है। इसके पीछे की मुख्य वजह इस प्लांट को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बजट नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए इस काऊ मिल्क प्लांट की स्थिति खराब होती जा रही है। प्लांट के नवीन प्रभारी मनीष चौधरी ने कहा है, कि प्लांट लगभग विगत 6 माह से बंद पड़ा हुआ है। प्लांट में जो कर्मचारी मौजूद थे, उनको भी हटा दिया गया था। साथ ही, इलाके में दूध खरीदने वाली मौजूद समितियाँ भी बंद की जा चुकी हैं।

## किसान भाई अपना दूध कहां बेचने जाएं

मनीष चौधरी का कहना है, कि यह प्लांट पूर्व की सपा सरकार में निर्मित हुआ था। उसने भी इसके बजट की उचित व्यवस्था नहीं की थी। साथ ही, इस संबंध में कानपुर मंडल के जनरल मैनेजर बृजमोहन त्यागी से चर्चा की तो उन्होंने इस प्लांट को अपने से भिन्न बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में कन्नौज जनपद समेत समीप के बहुत सारे जनपदों में पराग के दूध की आपूर्ति नाममात्र के लिए भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में समीपवर्ती जनपदों के विभिन्न किसान काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसान अपना दूध कहां बेचे और किसको भेजें।

## आखिर कब तक प्लांट सुचारु हो पाएगा

साथ ही, फिलहाल मजबूरी में किसानों को दूध निजी संस्थानों के यहां बेचना पड़ रहा है। जहां पर उनको न तो उचित भाव प्राप्त हो रहा साथ ही, ढंग की सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में किसान फिलहाल दर-दर के धक्के खाने को विवश हो गए हैं। हालाँकि, प्लांट के अब तक आरंभ होने की कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ रही है।





**इस नंबर पर कॉल करते ही गाय-भैंस का इलाज करने घर पर आएगी पशु चिकित्सकों की टीम**

## इस नंबर पर कॉल करते ही गाय-भैंस का इलाज करने घर पर आएगी पशु चिकित्सकों की टीम

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण बाजार में पशु उत्पादों की बढ़ती हुई मांग है। इन दिनों देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ डेयरी उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए खेती किसानों पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब पशुपालन को भी एक अन्य व्यवसाय की तरह देख रही है। जिससे ग्रामीण लोगों को जबरदस्त फायदा हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन की तरफ बढ़ रहे रुझान को देखते हुए अब केंद्र तथा राज्य सरकारें भी पशुपालन को प्रमोट कर रही हैं। इसके तहत किसानों को पशुपालन के लिए आर्थिक मदद दी जाती है ताकि गांव के लोग बिना किसी परेशानी के अपना पशुपालन का व्यवसाय आगे बढ़ा सकें। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण पशुपालकों की मदद करने के लिए एक और निर्णय लिया है। अब मध्य प्रदेश सरकार राज्य में गाय-भैंसों के अलावा अन्य पशुओं के लिए एंबुलेंस चलाएगी जिससे राज्य के पशुओं को घर बैठे इलाज मिल पाएगा। अब बीमार पशुओं को लेकर किसानों या पशुपालकों को पशु अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा।

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई इस एंबुलेंस में पशु चिकित्सकों के साथ कंपाउंडरों की टीम भी मौजूद रहेगी। जो घर पर पहुंचकर पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। यह एंबुलेंस प्रदेश के सभी ब्लॉक में चलाई जाएगी। जिसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 407 एंबुलेंस खरीदी थीं और उन्हें ब्लॉक स्तर पर स्थित पशु चिकित्सालयों को दे दी गई हैं।

यदि किसी किसान या पशुपालक का जानवर बीमार हो जाता है तो वह टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके अपने घर पर एंबुलेंस को बुला सकता है। कॉल करने के कुछ देर बाद ही चिकित्सकों और कंपाउंडरों सहित पशु एंबुलेंस किसान या पशुपालक के घर पर पहुंच जाएगी। साथ बिना समय गंवाए जल्द से जल्द पशु का इलाज किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि हर एंबुलेंस को प्रति माह दवाइयों के लिए 35 हजार रुपये तथा डीजल के लिए 33 हजार रुपये दिए जाएंगे। एंबुलेंस के माध्यम से जिन पशुओं का इलाज किया जाएगा, वह पूरी तरह से निशुल्क होगा। एंबुलेंस सेवा उन पशुओं के लिए एक राहत भरा कदम है जो एक्सीडेंट होने या बीमार होने के कारण पशु अस्पताल नहीं पहुंच पाते और असमय ही दम तोड़ देते हैं। अब ऐसे पशुओं को समय पर बेहतर इलाज मिल पाएगा, जिससे किसानों एवं पशुपालकों को पशु हानि नहीं होगी।

इसके पहले इसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू की जा चुकी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 502 पशु एंबुलेंस दिए थे। उत्तर प्रदेश में भी टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके किसान भाई एवं पशुपालक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी पशु चिकित्सकों की टीम एंबुलेंस में बैठकर घर-घर पशुओं का इलाज करने जाएगी। इस सुविधा के चालू हो जाने के बाद गंभीर रूप से बीमार पशु समय रहते पशु अस्पताल भेजे जा सकेंगे। जिससे दुधारू पशुओं की जान बचाई जा सकेगी।

आंध्र प्रदेश की सरकार ने पशुओं के लिए इस तरह की योजना साल 2022 में ही शुरू कर दी थी। तब आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने पशु एंबुलेंस खरीदने के लिए 143 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम खर्च की थी। जिसके परिणामस्वरूप राज्य को 175 पशु एंबुलेंस मिली थीं। जिनका आज भी पशुओं के इलाज के लिए उपयोग हो रहा है और बीमार पशुओं की जान बचाई जा रही है।



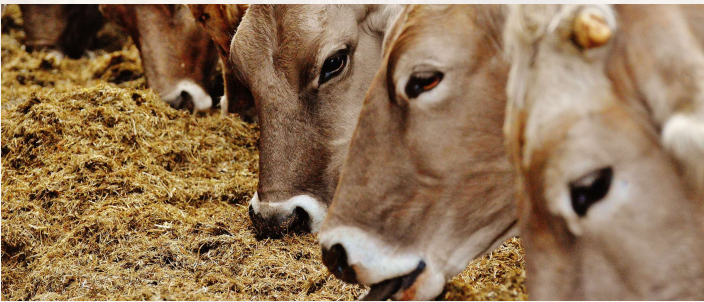
# पशुओं की जान ले सकता है लंगड़ा बुखार इस तरह से पहचानें लक्षण



## पशुओं की जान ले सकता है लंगड़ा बुखार, इस तरह से पहचानें लक्षण

भारत के किसान खेती-किसानी के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं ताकि उन्हें कुछ अतिरिक्त आमदनी होती रहे। इसके लिए सरकार भी किसानों को पशुपालन के प्रति जागरूक करती है तथा समय-समय पर पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। पशुपालन के लिए सरकार समय-समय पर किसानों को सब्सिडी भी देती है। हालांकि इस प्रकार की सहायता से भी पशुपालन में किसानों की चुनौतियां कम नहीं होती। कई बार दुधारू पशुओं में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनके कारण किसानों को काफी परेशान होना पड़ता है, इसके साथ ही कई बार किसानों को पशुपालन में घाटा भी लग जाता है।

इन दिनों दुधारू पशुओं के बीच लंगड़ा बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। पशुओं को होने वाली यह बीमारी जानलेवा हो सकती है, जिसके कारण पशुओं की मौत भी हो सकती है। यह बीमारी भैंस और गाय के साथ-साथ अन्य दूध देने वाले पशुओं में भी फैल जाती है। इस बीमारी के लिए क्लोस्ट्रीडियम चौवई नामक जीवाणु उत्तरदायी है, जो पशुओं में घाव के माध्यम से तथा दूषित चारागाह में चरने के दौरान चारे के माध्यम से फैलते हैं।



### यह होते हैं लंगड़ा बुखार के लक्षण

यह एक जीवाणु जनित बीमारी है जिसके कारण पशु को तेज बुखार आता है। इसके साथ ही पशु के पिछली व अगली टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आ जाती है। सूजन वाली जगह सूख कर उनकी चमड़ी कड़ी हो जाती है। कुछ समय बाद इसी जगह पर घाव हो जाता है। धीरे-धीरे जीवाणुओं की मदद से यह रोग पूरे शरीर में फैल जाता है। इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करवाना बहुत जरूरी है अन्यथा पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी की रोकथाम में प्रोकेन पेनिसिलीन के टीके काफी उपयोगी पाए गए हैं। इसलिए बीमारी की रोकथाम में प्रोकेन पेनिसिलीन के टीकों का बहुतायत से उपयोग किया जाता है।

### ऐसे करें लंगड़ा बुखार से पशुओं का बचाव

एक बार किसी भी पशु के लंगड़ा बुखार की जद में आने पर उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर भी कुछ उपाय करके इस रोग को अन्य पशुओं तक पहुंचने से रोका जा सकता है, साथ ही पशुओं की बचाया भी जा सकता है। एक बार बीमार होने पर बीमार पशु को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। इसके साथ ही समय पर टीकाकरण करवा दें। सूजन में चीरा मारकर खोल देना चाहिए ताकि जीवाणु हवा के संपर्क में आ सकें। इससे जीवाणुओं का प्रभाव काफी कम हो जाता है। बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही पशु का चिकित्सक से पशु का इलाज कराना चाहिए।



# इन नस्लों की भेड़ पालने से पशुपालक जल्द ही हो सकते हैं मालामाल



## इन नस्लों की भेड़ पालने से पशुपालक जल्द ही हो सकते हैं मालामाल

भारत में भेड़ पालन एक लोकप्रिय पशुपालन उद्योग है। भेड़ को दूध, मांस और ऊन के उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ पालन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनते हैं और इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह काम किसान भाई खेती बाड़ी के साथ ही करते हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। भेड़ पालन का काम ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान करते हैं। भेड़ों की मौत के बाद उनकी खाल की भी बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। भेड़ की खाल से जूते, चप्पल और हैंड बैग जैसी चीजें बनाई जाती हैं।

इन दिनों भारत में किसानों के द्वारा कई नस्लों की भेड़ें पाली जाती हैं। जिनका उपयोग ज्यादातर ऊन उत्पादन में किया जाता है। इनमें जैसलमेरी, मंडियां, छोटा नागपुरी शहाबाबा, मारवाड़ी, बेकानेरी, मालपुरा, कोरिडायल रामबुतु और मैरिनो प्रमुख हैं। इन सभी प्रजातियों की भेड़ें किसी भी प्रकार के मौसम में रह सकती हैं, जिससे पशुपालकों को इनको पालने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। पशुपालकों द्वारा ऐसा कई बार कहा जाता है कि उन्हें भेड़ पालन में उचित मुनाफा नहीं होता है, इसलिए आज हम आपको भेड़ों की ऐसी नस्लों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे किसान भाई रातोंरात मालामाल बन सकते हैं।

### अविकालीन भेड़

यह भेड़ उन्नत किस्म के ऊन का उत्पादन करती है। जिसका उपयोग कालीन बनाने में किया जाता है। इस भेड़ से प्राप्त होने वाला ऊन बेहद पतला होता है। अगर इसके वार्षिक उत्पादन की बात करें तो यह भेड़ एक साल में 2 से लेकर 2.5 किलो तक ऊन दे सकती है। इस नस्ल की भेड़ का पालन करके किसान भाई अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।

### अविवस्त्र भेड़

यह सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है। यह एक साल में 4 किलोग्राम से ज्यादा ऊन दे सकती है। इसके साथ ही इस भेड़ का वजन भी तेजी से बढ़ता है। ऐसे में इसका मांस बेंचकर भी पशुपालक अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस भेड़ का वजन एक साल के भीतर 23 किलोग्राम तक हो सकता है।

### चौकला भेड़

यह बेहद वजनी भेड़ होती है, जिसका वजन 32 से लेकर 40 किलोग्राम तक हो सकता है। यह भेड़ एक साल में 2.5 किलोग्राम ऊन का उत्पादन कर सकती है। इस नस्ल की भेड़ में सींग नहीं होते। यह ज्यादातर राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चुरू जिले में पाई जाती है।

इनके अलावा भारत में लोही, कूका, गुरेज, नुरेज, हसन, नैल्लोर, जालौनी, शाहवादी, बजीरी, बैलारी, जालौनी, भाकरवाल, मागरा, काठियावाड़ी, भादरवाल और दक्कनी नस्ल की भेड़ें भी पाई जाती हैं।



# सामान्य लेख



जानें सबसे ज्यादा सरसों की खरीद किस राज्य में हुई है, नाफेड को खुद भी क्यों करनी पड़ी खरीद शुरू

जानें सबसे ज्यादा सरसों की खरीद किस राज्य में हुई है, नाफेड को खुद भी क्यों करनी पड़ी खरीद शुरू

नाफेड ने मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए सरसों की एमएसपी दर 5450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यह भारत का एकमात्र प्रदेश है, जो अकेला 42 फीसदी सरसों की पैदावार करता है।

गेहूं समेत भारत के ज्यादातर राज्यों में तिलहन की खरीद भी चालू हो चुकी है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में एमएसपी पर सरसों की खरीद की जा रही है। मौसम के गर्म होते-होते सरसों की खरीद में तीव्रता भी होती जा रही है। यही कारण है, कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) द्वारा अब तक 169217.45 मेट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है। साथ ही, इसके एवज में किसान भाइयों के खाते में करोड़ों रुपये की धनराशि भी भेजी जा चुकी है। इससे सरसों का उत्पादन करने वाले कृषक काफी खुश हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को आशा है, कि आगामी दिनों में सरसों खरीदी में और ज्यादा तीव्रता आएगी।

नाफेड ने खुद की सरसों की खरीद शुरू

किसान तक की खबरों के अनुसार, तीन वर्ष बाद ऐसा हुआ है, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर होने के कारण नाफेड स्वयं सरसों की खरीदी कर रहा है। इससे पूर्व किसान स्वयं मंडियों में जाकर व्यापारियों को एमएसपी से महंगी कीमत पर सरसों विक्रय करते थे। अब तक 84914 किसानों ने एमएसपी पर सरसों विक्रय करते हैं। इसके एवज उनके खाते में 922.24 रुपये भेजे जा चुके हैं। आहिस्ते-आहिस्ते सरसों खरीद केंद्रों पर किसानों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। हालाँकि, बेमौसम बारिश के कारण से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश समेत बहुत से तिलहन उपादक राज्यों में फसल की कटाई में विलंब हो गया था। साथ ही, बरसात से सरसों की फसल को काफी क्षति भी पहुंची है।





## हरियाणा में विगत 20 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है

भारत में राजस्थान सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। परंतु, इस बार हरियाणा सरसों की खरीद करने के संबंध में राजस्थान से आगे है। नाफेड ने अब तक हरियाणा के अंदर 139226.38 मीट्रिक टन सरसों की खरीद करली है। हालाँकि, हरियाणा राज्य में भी देश के कुल उत्पादन का अकेले 13.5 फीसद सरसों का उत्पादन किया जाता है। इसके बदले में कृषकों को 758.78 करोड़ रुपये दिए गए हैं। विशेष बात यह है, कि हरियाणा में विगत 20 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की गई है।

## इन राज्यों में इतने मीट्रिक टन सरसों की एमएसपी पर खरीद की जा चुकी है

नाफेड ने मार्केटिंग सीजन 2023-24 हेतु सरसों की एमएसपी दर 5450 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दी है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो यहां की जलवायु के अनुरूप यह भारत का एकमात्र राज्य है, जो अकेला 42 फसदी सरसों का उत्पादन करता है। इसके बावजूद भी राजस्थान में अब तक 4708.40 मीट्रिक टन ही सरसों की खरीद हो सकती है। साथ ही, सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश भी कोई पीछे नहीं है। यह 12 प्रतिशत सरसों का उत्पादन किया करता है। मध्य प्रदेश में अब तक 9977.74 मीट्रिक टन सरसों की खरीद संपन्न हुई है। इसके उपरांत गुजरात 4.2 फीसद सरसों का उत्पादन करता है।

**MASSEY FERGUSON  
245 DI SMART**

**4WD**



# इस राज्य में किसानों को घर बैठे अनुदानित दर पर बीज मुहैया कराए जाएंगे



## इस राज्य में किसानों को घर बैठे अनुदानित दर पर बीज मुहैया कराए जाएंगे

खेती किसानी में बेहतर पैदावार जब ही प्राप्त हो सकती है, जब उर्वरक भूमि के साथ-साथ बेहतरीन गुणवत्ता के बीज भी होने चाहिए। बिहार सरकार फिलहाल उत्तम गुणवत्ता के बीजों को किसानों के घर तक पहुंचाएगी।

बेहतरीन खेती के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीजों का होना काफी आवश्यक होता है। किसान बीज प्राप्त करने के लिए बाजार एवं बीज केंद्रों के चक्कर काटते रहते हैं। उत्तम गुणवत्ता का बीज न मिलने की वजह से किसानों की फसल उतनी खास नहीं हो पाती है। किसानों के समक्ष चुनौती यह भी रहती है, कि बेहतरीन गुणवत्ता के बीजों की पहचान किस तरह की जाए। राज्य सरकार के स्तर से भी किस तरह अच्छे बीज प्राप्त हो सकें। किसान इसको लेकर भी मांग करते रहते हैं। फिलहाल, बिहार सरकार ने इसी दिशा में पहल की जा रही है। किसानों की काफी परेशानियां भी समाप्त कर दी है।

### बिहार सरकार की तरफ से बीजों की होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है

बिहार सरकार खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के बीजों को अनुदान देकर मुहैया करा रही है। बीजों को किसानों के घर तक मुहैया कराने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा भी दी गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया है, कि जो किसान घर पर बीज प्राप्त करना चाहते हैं। उनको एक अलग विकल्प भरना होगा। होम डिलीवरी हेतु उनसे अतिरिक्त धन भी लिया जाएगा।

### बिहार सरकार द्वारा किया अपील की गई है

बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर यह जानकारी प्रदान की है। बिहार सरकार की तरफ से बताया गया है, कि किसान भाइयों एवं बहनों, कृपया गौर करें! खरीफ मौसम, 2023 में विभिन्न फसलों के बीज की सब्सिडी दर पर उपलब्धता से जुड़ी सूचना। कृषि विभाग द्वारा बिहार राज्य बीज निगम के जरिए से खरीफ मौसम, 2023 की विभिन्न योजनाओं में खरीफ फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना तैयार कर ली है।

### किसान ऑनलाइन आवेदन यहां कर सकते हैं

इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न खरीफ फसलों के बीज प्राप्त करने के लिए DBT PORTAL ([HTTPS://DBTAGRICULTURE.BIHAR.GOV.IN](https://dbtagriculture.bihar.gov.in)) / BRBN PORTAL ([BRBN.BIHAR.GOV.IN](http://brbn.bihar.gov.in)) के बीज अनुदान / आवेदन लिंक पर दिनांक 15 अप्रैल, 2023 से 30 मई, 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। किसान सुविधानुसार साइबर कैफ / वसुधा केंद्र / कॉमन सर्विस सेंटर अथवा स्वयं के ANDROID MOBILE के उपयोग से आवेदन किया जा सकता है।

## बीज की डिलीवरी इस प्रकार से की जाएगी

किसानों का आवेदन संबंधित एग्रीकोऑर्डिनेटर को भेजा जाएगा। एग्री कोऑर्डिनेटर जिस स्थान पर बीज आवंटित करेगा, उस जगह की जानकारी किसान को दी जाएगी। किसान बीज विक्रेता को बीज वितरण के दौरान आधार कार्ड आधारित फिंगर प्रिंट अथवा आईरिस पहचान द्वारा आधार प्रमाणीकरण करवाकर एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर साझा करना होगा। इसके उपरांत पंजीकृत नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। उसको दर्ज करने के उपरांत अनुदान की धनराशि भी घट जाएगी एवं शेष धनराशि का भुगतान कर दें।



# मिट्टी की सेहत - खाद

हैदराबाद में सब्जियों के अवशेष से बन रहा जैविक खाद, बिजली और ईंधन, पीएम मोदी ने की प्रशंसा

## हैदराबाद में सब्जियों के अवशेष से बन रहा जैविक खाद, बिजली और ईंधन, पीएम मोदी ने की प्रशंसा

हैदराबाद की बोवेनपल्ली सब्जी मंडी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही है। यहां मंडी व्यापारियों की कोशिशों पर बेकार अथवा बची हुई अशुद्ध सब्जियों के उपयोग से जैविक खाद, बिजली और जैव-ईंधन निर्मित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की है।

आजकल ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी खासी आमदनी का स्रोत बनता जा रहा है। इसके चलते पर्यावरण को संरक्षण देने में भी विशेष मदद प्राप्त हो रही है। साथ ही, आजकल लोग ऑर्गेनिक वेस्ट के जरिए खूब मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। यह किसान भाइयों के लिए एक उन्नति का जरिया बनता जा रहा है। आजकल हैदराबाद की बोवेनपल्ली मंडी के अंदर भी कुछ इसी प्रकार का ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। यहां पर मंडी में बची हुई अथवा बेकार सब्जियों से हरित ऊर्जा बनाई जा रही है। बोवेनपल्ली मंडी में सब्जियों के अवशेष को उपयोग करके बिजली, जैविक खाद, जैविक ईंधन निर्माण कार्य चल रहा है। मंडी व्यापारियों के नवाचार एवं सफल कोशिशों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की है।

**प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सराहनीय कार्य की खूब प्रशंसा की है**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बोवेनपल्ली सब्जी मंडी के व्यापारियों के नवोन्मेषी विचारों की खूब प्रशंसा की है।

पीएम मोदी ने बताया है, कि ज्यादातर सब्जी मंडियों में सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिससे असुरक्षित खाद्यान हालात उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे में समस्या का निराकरण करने हेतु हैदराबाद की बोवेनपल्ली सब्जी मंडी व्यापारियों द्वारा इस अवशेष से हरित ऊर्जा निर्मित करने का निर्णय लिया गया है।

मंडी में फल एवं सब्जियों के प्रत्येक औंस अवशेषों द्वारा 500 यूनिट बिजली एवं 30 किलो जैव ईंधन बनाया जा रहा है। यहां उत्पादित होने वाली विद्युत आपूर्ति प्रशासनिक भवन, जल आपूर्ति नेटवर्क, स्ट्रीट लाइट्स और 170 स्टाल्स को की जा रही है।

साथ ही, ऑर्गेनिक वेस्ट से निर्मित जैव ईंधन को बाजार में स्थित रेस्त्रा, ढाबे अथवा व्यावसायिक रसोईयों में भेजा जा रहा है। यहां विद्युत के जरिए मंडी की कैंटीन प्रकाशित की जा रही है। साथ ही, यहां का चूल्हा तक भी प्लांट के ईंधन के जरिए जल रहा है।

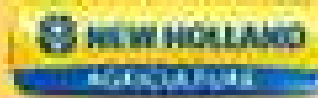
जानकारी के लिए बता दें, कि बोवेनपल्ली मंडी में प्रतिदिन 650-700 यूनिट विद्युत खपत होती है। उधर, प्रतिदिन 400 यूनिट बिजली पैदा करने के लिए 7-8 टन फल एवं सब्जियों के अवशेषों की जरूरत पड़ती है।

## महिलाओं के लिए भी रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न हुए हैं

हैदराबाद की बोवेनपल्ली सब्जी मंडी में स्थापित बायोगैस प्लांट से वर्तमान में बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। यहां पर सब्जी बेचने वाले एवं अन्य लोग भी जैव कचरे को एकत्रित कर प्लांट में पहुंचाते हैं। साथ ही, प्लांट में पहुंचाए गए जैव कचरे को अलग करने, कटाई-छंटाई करने, मशीन चलाने व प्लांट प्रबंधन का काम महिलाएं देख रही हैं।

मंडी अधिकारियों के अनुसार, बायोगैस प्लांट में प्रतिदिन 10 टन अवशेष एकत्रित किया जाता है। यदि अनुमान के अनुसार बात करें तो इस अवशेष से एक वर्ष में 6,290 किग्रा. कार्बन डाई ऑक्साइड निकलती है। जो कि पर्यावरण एवं लोगों के स्वास्थ्य हेतु बिल्कुल सही नहीं है। इस चुनौती एवं समस्या को मंडी व्यापारियों ने संज्ञान में लिया है। इसका बायोगैस प्लांट को स्थापित करके संयुक्त समाधान निकाल लिया गया है।

तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद की इस बोवेनपल्ली मंडी में बायोगैस प्लांट को चालू करने का श्रेय जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं कृषि विपणन तेलंगाना विभाग, गीतानाथ को जाता है। यहीं बायोगैस प्लांट वित्त पोषित है। इस बायोगैस प्लांट को व्यवस्थित रूप से चलाने में सीएसआईआर-आईआईसीटी के वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन शामिल है। यहीं की पेटेंट तकनीक के माध्यम से बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई है।



# आसली हीरो की ताकत भारोरो की विश्वासता



